



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 4, 2006/भाद्र 13, 1928

No. 131]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 4, 2006/BHADRA 13, 1928

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2006

फा. सं. 6-4/2006-बी एण्ड सीएस.- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (के) के प्रावधान तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (डी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा फा. सं. 13-1/2004-रिस्ट्र से निर्गत अधिसूचना सं. 39 [सं. का.आ. 44(अ) तथा 45(अ) दिनांक 9 जनवरी, 2004] के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी) के उप-खण्ड (ii), (iii) और (iv) तथा धारा 36 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतद्वारा दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) अन्तरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) (जिसे यहाँ इसके बाद "प्रधान विनियम" कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार :-

- यह विनियम "दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) अन्तरसंयोजन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006 (2006 का 10)" कहा जाएगा।
- यह विनियम इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. प्रधान विनियम के खण्ड 2 में उप-खण्ड (एन) के बाद निम्नलिखित नया उप-खण्ड और उससे संबंधित प्रविष्टियों को उप-खण्ड (ओ) से (आर) के रूप में जोड़ा जाएगा :

- (ओ) 'आरआईओ' का आशय पार्टी द्वारा प्रकाशित संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव से है, जिसमें वे शर्तें निर्धारित होती हैं जिनको पूरा करने पर दूसरी पार्टियाँ, उस पार्टी से अन्तरसंयोजन प्राप्त करने की हकदार होंगी।
- (पी) 'सब्सक्राइबर आधार' का आशय ऐसे सब्सक्राइबरों की संख्या से है,
- (i) जिनके बारे में गैर एड्रेसेबल प्रणाली में दो सेवा प्रदाताओं के बीच सहमति हो तथा जिसके आधार पर एक सेवा प्रदाता द्वारा दूसरे सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए अथवा,
 - (ii) जहां एड्रेसेबल सिस्टम लागू हो, वहां सब्सक्राइबर मनेजमेंट सिस्टम द्वारा प्रतिबिम्बित किया जाए।
- (क्यू) 'सब्सक्राइबर लाइन रिपोर्ट' अथवा 'एसएलआर' का आशय गैर-एड्रेसेबल प्रणाली में एक ऐसे मासिक विवरण से है, जिसके बारे में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा केबल ऑपरेटर उस माह के सब्सक्राइबर आधार के बारे में सहमत हों।
- (आर) 'सब्सक्राइबर मनेजमेंट सिस्टम' अथवा 'एसएमएस' का आशय ऐसी प्रणाली या उपकरण से है, जिसमें एड्रेसेबल प्रणाली में सब्सक्राइबर के नाम, पता आदि से संबंधित रिकॉर्ड तथा ब्यौरे के साथ-साथ सब्सक्राइबर द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले हार्डवेयर, सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइबड किए गए चैनलों/चैनल समूहों, प्रणाली में निर्धारित किए गए ऐसे चैनलों अथवा चैनल समूहों की कीमत, किसी चैनल या चैनल समूहों को एक्टिवेट/डिअक्टिवेट करने की तारीख तथा समय के बारे में सूचना, सब्सक्राइबर के रिकॉर्ड में सभी निष्पादित कार्यों का विवरण, प्रत्येक सब्सक्राइबर को जारी किए गए बीजक तथा प्रत्येक बिल अवधि के लिए सब्सक्राइबर द्वारा किए गए भुगतान का ब्यौरा दर्ज होता है।

3. प्रधान विनियम के खण्ड 3 में:

- (क) उपखण्ड 3.2 के दूसरे प्रावधान के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी:—

"स्पष्टीकरण

टीवी चैनलों के ऐसे आवेदक वितरक जो इस समय सम्बद्ध मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से भिन्न किसी अन्य मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से या ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के किसी एजेंट/किसी अन्य मध्यस्थ से अथवा सीधे ब्राडकास्टर से सिगनल फीड प्राप्त करना चाहता है वह सेवा के लिए अपने अनुरोध के साथ-साथ नवीनतम मासिक बीजक की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसमें इस समय सम्बद्ध मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के किसी एजेंट/किसी अन्य मध्यस्थ, जो टीवी चैनलों के सिगनल मुहैया कराने के लिए भुगतान वसूल करता है को देय राशि, यदि कोई हो, का ब्यौरा दर्शाया गया हो।"

- (ख) उपखण्ड 3.2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित नया उपखण्ड तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को उपखण्ड 3.3 के रूप में जोड़ा जाए:

"3.3 कोई ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का कोई एजेंट—कोई अन्य मध्यस्थ, जो टीवी चैनलों के वितरक को टीवी चैनल के सिगनल मुहैया कराने के लिए भुगतान वसूल करता है, वह टीवी चैनलों के वितरक को मासिक बीजक जारी करेगा। मासिक बीजक में भुगतान की देय राशि के साथ-साथ बकाया राशि तथा वर्तमान देय राशि स्पष्ट दिखाई जाएगी।

स्पष्टीकरण

बकाया राशि के किसी भी दावे के साथ यह सेवा प्रमाण भी दिया जाना चाहिए कि जिस अवधि से संबंधित बकाया राशि है, उसके लिए बीजक जारी किया गया था।

(ग) वर्तमान खण्ड 3.3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को खण्ड 3.4 के रूप में पुनर्स्थापित किया जाएगा और वर्तमान खण्ड 3.4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा।

(घ) उपखण्ड 3.4 के बाद निम्नलिखित नया उपखण्ड और उससे संबंधित प्रविष्टियों को उपखण्ड 3.5 के रूप में जोड़ा जाएगा:

3.5 कोई ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का कोई एजेंट/कोई अन्य मध्यस्थ, जिसे टीवी चैनल के सिगनल मुहैया कराने के लिए अनुरोध किया जाता है, वह सिगनल की मांग करने वाले टीवी चैनलों के वितरक को या तो आपसी सहमति की शर्तों पर सिगनल मुहैया कराएगा या समुचित समय के भीतर ऐसी शर्तों को विनिर्दिष्ट करेगा जिस पर वे टीवी चैनल के सिगनल मुहैया कराने के लिए तैयार हैं, परन्तु यह अवधि अनुरोध किए जाने की तारीख से 60 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या ब्राडकास्ट/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का कोई एजेंट/कोई अन्य मध्यस्थ, जिससे टीवी चैनल के सिगनल मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है, टीवी चैनल के सिगनल के अनुरोध को अस्वीकार करता है तो टीवी चैनल के सिगनलों को मुहैया कराने का अनुरोध किए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर अनुरोध अस्वीकार करने के कारण अवश्य सूचित किए जाने चाहिए ताकि टीवी चैनलों का वितरक समुचित मंच पर इस मामले को उठा सके।

स्पष्टीकरण

60 दिन की समय सीमा में ब्राडकास्टर द्वारा लिया गया वह समय भी शामिल होगा, जो टीवी चैनलों के ऐसे वितरक, जिसने सिगनलों के लिए अनुरोध किया है, के संबंध

में ब्राडकास्टर द्वारा अपने एजेंट या मध्यस्थ से और प्रतिकूलतः अर्थात् इन लोगों द्वारा ब्राडकास्टर से संपर्क करने में लगे।”

- (ड) वर्तमान उपखण्ड 3.5 में और इससे संबंधित प्रविष्टियों को उपखण्ड 3.6 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और वर्तमान उपखण्ड 3.6 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा।
- (च) पुनर्संख्यांकित उपखण्ड 3.6 वर्तमान स्पष्टीकरण और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:

“स्पष्टीकरण

“समान प्रकार के टीवी चैनलों के वितरक” का आशय टीवी चैनलों के ऐसे वितरकों से है जो समान प्रकार की परिस्थितियों में काम करते हैं। टीवी चैनलों के वितरक समान प्रकार के हैं या नहीं यह विश्लेषण करने के लिए ऐसे कारकों पर कि क्या वे एक ही भौगोलिक क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में परिचालित करते हैं, मोटेतौर पर उनके सब्सक्राइबर की संख्या समान है, वे समान उपकरण खरीदते हैं, और वितरण की समान प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, पर आधारित होता है, परन्तु यह इसी तक सीमित नहीं है।

संदेह को दूर करने के लिए आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि टीवी चैनलों के वितरकों जो एड्रसेबल सिस्टमों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डीटीएच, आईपीटीवी और इस प्रकार के माध्यम भी शामिल हैं, को गैर-एड्रसेबल प्रणालियों का इस्तेमाल करने वाले टीवी चैनलों के वितरकों के समान प्रकार का वितरक नहीं कहा जा सकता है।”

4. प्रधान विनियम में वर्तमान खण्ड 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:

टीवी चैनल के सिगनलों का वियोजन

4.1 तीन सप्ताह का ऐसा नोटिस दिए बिना, जिसमें प्रस्तावित कार्रवाई के कारणों का स्पष्ट उल्लेख हो, कोई भी ब्राडकास्टर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, टीवी चैनलों के वितरक को मुहैया कराए गए टीवी चैनल के सिगनलों का वियोजन नहीं करेगा।

यदि कोई ऐसा करार, लिखित या मौखिक हो, जिसमें ब्राडकास्टिंग सेवा के वितरण की अनुमति दी गई हो और जो समय बीतने के साथ समाप्त हो गया हो तो भी टीवी चैनलों के वितरक को मुहैया कराए गए सिगनलों के वियोजन से पूर्व भी नोटिस दिया जाना अपेक्षित होगा।

आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि सिगनलों के वितरण की अनुमति प्रदान करने के लिए कोई करार, लिखित या मौखिक, न हो तो कोई नोटिस दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

4.2 टीवी चैनलों का कोई भी वितरक, ब्राडकास्टर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, को तीन सप्ताह का ऐसा नोटिस दिए बिना जिसमें प्रस्तावित कार्रवाई के कारणों का स्पष्ट उल्लेख हो, किसी टीवी चैनल के रि-ट्रांसमिशन का वियोजन नहीं करेगा।

4.3 ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/टीवी चैनल के वितरक उपभोक्ताओं को ऐसे विवाद के बारे में सूचित करेंगे ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें। तदनुसार, यदि टीवी चैनलों का वितरक का एक जिले में परिचालन हो तो सिगनलों के वियोजन का नोटिस दो स्थानीय समाचारपत्रों में भी दिया जाएगा, जिनमें से कम से कम एक नोटिस स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में स्थानीय भाषा में दिया जाएगा और यदि चैनलों का वितरक दो जिलों से ज्यादा में सेवा मुहैया कराता हो तो दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में नोटिस दिया जाएगा। इस विनियम के उपखण्ड 4.1 और 4.2 में उल्लिखित तीन सप्ताह की अवधि, समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किए जाने या सेवा प्रदाता को नोटिस दिए जाने, के जो भी बाद में हो, से प्रारंभ होगी।

स्पष्टीकरण

1. यदि दो समाचार पत्रों में अलग-अलग दिन नोटिस प्रकाशित किया जाता है तो तीन सप्ताह की अवधि दोनों तारीखों में से बाद की तारीख से प्रारंभ होगी।

2. ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/टीवी चैनलों के वितरक, संबंधित चैनल (चैनलों) पर स्क्रीन चलाकर भी उपभोक्ताओं को सूचित कर सकते हैं। तथापि समाचारपत्रों में नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा।

4.4 समाचार पत्रों में दिए जाने वाले नोटिसों में संक्षेप में वियोजन के कारण भी दिए जाने चाहिए।”

5. समय-समय पर यथा संशोधित प्रधान विनियम में वर्तमान खण्ड-7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को खण्ड 14 के रूप में पुनर्संख्याकित किया जाएगा।
6. समय-समय पर यथा संशोधित प्रधान विनियम के खण्ड 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित नए खण्डों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों को खण्ड 7 से 13 के रूप में जोड़ा जाएगा।

7. फ्री टु एयर चैनल/पे चैनल का रूपान्तरण

7.1 किसी चैनल अर्थात् फ्री टु एयर अथवा पे चैनल का स्वरूप सामान्यतौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए समान रहेगा। फ्री टु एयर चैनल का कोई ब्राडकास्टर जो चैनल को पे चैनल में बदलने के इच्छुक हो या पे चैनल का कोई ब्राडकास्टर जो चैनल को फ्री टु एयर चैनल में बदलने के इच्छुक हो वह, प्राधिकरण को इस बारे में सूचित करेगा तथा इस परिवर्तन की निर्धारित तारीख से एक माह पूर्व खण्ड 4.3 में विनिर्दिष्ट तरीके से सार्वजनिक सूचना देगा।

8. वर्तमान करारों के नवीकरण की समयावधि

8.1 टीवी चैनलों के सिगनलों की सप्लाइ के लिए अन्तरसंयोजन करार की पार्टियां, वर्तमान करार की समाप्ति की तारीख से कम से कम दो महीने पहले वर्तमान करार के नवीकरण के लिए विचार-विमर्श प्रारंभ करेंगे।

यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि अन्तरसंयोजन करार के नवीकरण का विचार-विमर्श, वर्तमान करार की समाप्ति की तारीख से आगे भी जारी रहता है तो वर्तमान करार की शर्तें, नया करार किए जाने तक अथवा मूल करार की समाप्ति से अगले तीन महीने तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा। बहरहाल, पार्टियों के बीच करार हो जाने के बाद नई वाणिज्यिक शर्तें, मूल करार की समाप्ति की तारीख से लागू होंगी।

आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि पार्टियां आपस में सहमति के आधार पर नया करार करने में समर्थ न हों तो कोई भी पार्टी खण्ड 4.3 में विनिर्दिष्ट तरीके से तीन सप्ताह का नोटिस देकर मूल करार की समाप्ति के बाद टीवी चैनल के सिगनलों के रि-ट्रांसमिशन का वियोजन कर सकता है। मूल करार की वाणिज्यिक शर्तें सिगनलों के वियोजन की तारीख तक लागू होंगी।

9. पहले करार के समय सब्सक्राइबर आधार को अंतिम रूप देना

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा केबल ऑपरेटर के बीच पहला करार

9.1 गैर एड्रसेबल प्रणालियों में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा केबल ऑपरेटर के बीच पहली बार अन्तरसंयोजन करार निष्पादित करते समय, करार की पार्टियां, सब्सक्राइबर लाइन रिपोर्ट (एसएलआर), जहां ऐसा एसएलआर मौजूद हो के आधार पर केबल ऑपरेटर के सब्सक्राइबर आधार को ध्यान में रखेंगी। जहां ऐसा एसएलआर मौजूद न हो, वहां दोनों पार्टियों द्वारा मुहैया कराए गए सब्सक्राइबर आधार पर आपसी

विचार-विमर्श में इसे तय किया जाएगा। ऐसा करने के लिए समान स्थिति में काम करने वाले केबल ऑपरेटरों के सब्सक्राइबर आधार तथा स्थानीय सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण

सब्सक्राइबर लाइन रिपोर्ट (एसएलआर), सब्सक्राइबर आधार का पता लगाने के लिए एक संसूचक मात्र है और दोनों पार्टियों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तय सब्सक्राइबर आधार, एसएलआर द्वारा संसूचित संख्या से अधिक या कम हो सकता है।

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा ब्राडकास्टर के बीच पहला करार

9.2 गैर एड्रैसेबल प्रणालियों में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और ब्राडकास्टर के बीच पहली बार अन्तरसंयोजन करार निष्पादित करते समय, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर उन केबल ऑपरेटरों की सूची, उनके सब्सक्राइबर आधार के साथ, प्रदान करेगा जो उसके नेटवर्क से सिगनल प्राप्त करेंगे। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर आधार के संबंध में विचार-विमर्श करते समय, करार की पार्टियां, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से सम्बद्ध केबल ऑपरेटरों के सब्सक्राइबर आधार को भी ध्यान में रखेंगी। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जिन्हें मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा सीधे सेवित करने का प्रस्ताव है, इस विनियम के उपखण्ड 9.1 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

10. करार की वैधता के दौरान सब्सक्राइबर आधार में अन्तर

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा केबल ऑपरेटर के बीच

10.1 गैर-एड्रैसेबल प्रणालियों में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर के बीच अन्तरसंयोजन करार के निष्पादन के समय पार्टियों द्वारा स्वीकृत सब्सक्राइबर आधार, करार के दौरान ऐसे आपवादिक परिस्थितियों, जिनमें सब्सक्राइबर आधार को बढ़ाना या

घटाना आवश्यक हो, को छोड़कर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, सब्सक्राइबर आधार में परिवर्तन करने के इच्छुक सेवा प्रदाता के लिए आवश्यक है कि वह इसके कारण बताए और प्रस्तावित परिवर्तन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसमें स्थानीय सर्वेक्षण प्रस्तुत करना भी शामिल है।

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा ब्राडकास्टर के बीच

10.2 गैर एड्रसेबल प्रणाली में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और ब्राडकास्टर के बीच अन्तरसंयोजन करार के निष्पादन के समय पार्टियों द्वारा स्वीकृत सब्सक्राइबर आधार करार के दौरान ऐसे आपवादिक परिस्थितियों, जिनमें सब्सक्राइबर आधार को बढ़ाना या घटाना आवश्यक हो, को छोड़कर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सब्सक्राइबर आधार में परिवर्तन करने के इच्छुक सेवा प्रदाता के लिए यह आवश्यक है कि वह इसके कारण बताए और प्रस्तावित परिवर्तन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसमें स्थानीय सर्वेक्षण प्रस्तुत करना है।

यह भी प्रावधान है कि केबल ऑपरेटर द्वारा किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को ज्वाइन करने या उसे छोड़ने के कारण किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर आधार में परिवर्तन होने के मामले में यह उपखण्ड लागू नहीं होगा।

आगे यह भी प्रावधान है कि यह भी कि किसी केबल ऑपरेटर के मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के नेटवर्क को ज्वाइन करने या उसे छोड़ने के कारण किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर आधार, जिसपर ब्राडकास्टर को किए जाने वाला भुगतान आधारित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन केबल ऑपरेटर के सब्सक्राइबर आधार, नेटवर्क ज्वाइन करने या छोड़ने वाले, के समान होगा।

11. करारों के नवीकरण के समय सब्सक्राइबर आधार को अंतिम रूप देना

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर के बीच

11.1 गैर एड्रैसेबल प्रणालियों में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर के बीच अन्तरसंयोजन करार के नवीकरण के समय, सब्सक्राइबर आधार में संशोधन के लिए किए जाने वाले विचार-विमर्शों में विगत तीन वर्षों के दौरान केवल ऑपरेटर के सब्सक्राइबर आधार में के साथ-साथ उसी क्षेत्र में जहां केबल ऑपरेटर का परिचालन हो और उसके आसपास के क्षेत्रों में परिचालन कर रहे अन्य केबल ऑपरेटरों के सब्सक्राइबर आधार में वर्तमान अवधि में हुए परिवर्तन को भी ध्यान में रखा जाएगा।

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और ब्राडकास्टर

11.2 गैर एड्रैसेबल प्रणाली में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और ब्राडकास्टर के बीच अन्तरसंयोजन करार के नवीकरण के समय सब्सक्राइबर आधार में संशोधन के लिए विचार-विमर्श करते समय पिछले तीन वर्षों के दौरान मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर आधार में हुए परिवर्तनों के साथ-साथ उस क्षेत्र में जहां मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का परिचालन हो और उसके आसपास के क्षेत्रों में परिचालन कर रहे अन्य मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों के सब्सक्राइबर आधार में वर्तमान अवधि में हुए परिवर्तन को भी ध्यान में रखना होगा।

12 मासिक सब्सक्राइबर आधार का विवरण

12.1 गैर-एड्रैसेबल प्रणालियों में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, सब्सक्राइबर आधार के साथ-साथ केबल ऑपरेटरों की अद्यतन सूची मासिक आधार पर ब्राडकास्टरों को प्रस्तुत करेंगे।

13 संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव

13.1 सभी ब्राडकास्टर इस विनियम के जारी होने के 90 दिनों के भीतर अपने संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे जिसमें अन्य बातों के

साथ-साथ गैर-एड्रैसेबल प्रणालियों में अन्तरसंयोजन की तकनीकी तथा वाणिज्यिक शर्तों का उल्लेख होगा। इसे ब्राडकास्टर द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव की शर्तों का मसौदा प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के बाद इसकी एक प्रतिलिपि अपनी वेबसाइट में भी डालेंगे। ब्राडकास्टर द्वारा इस प्रकार प्रकाशित संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव इसके बाद निष्पादित किए जाने वाले सभी अन्तरसंयोजन कार्यों के लिए आधार होगा।

13.2 प्रकाशित संदर्भ अन्तरसंयोजन करार में परिवर्तन प्राधिकरण को पूर्व में सूचित करने के बाद ही किया जा सकता है। ब्राडकास्टर द्वारा इस प्रकार प्रकाशित संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव के आधार पर अन्तरसंयोजन करार किया जाएगा। बहरहाल, यह आपसी सहमति के आधार पर पर किया जाएगा। संबंधित पार्टियां इसमें संशोधन कर सकते हैं और/या अलग-अलग करार करने के लिए प्रकाशित संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव में अनुबंधित शर्तों में जोड़ सकते हैं।

13.3 यदि खण्ड से किसी कानून, विनियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन होता पाया गया तो प्राधिकरण किसी भी समय इसमें हस्तक्षेप कर संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव के खण्ड में संशोधन करने या उसे हटाने का निर्देश जारी कर सकता है।

इस विनियम के अनुबंध 'क' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न है, जिसमें प्रधान विनियम के संशोधन करने के कारण दिए गए हैं।

आदेशानुसार,

राकेश कक्कड़, सलाहकार (बी एण्ड सीएस-1)

[विज्ञापन-III/IV/142/2006/असा.]

अनुबंध 'क'

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारत में केबल टीवी, 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में अपने प्रारंभ से ही गैर विनियमित रहा। दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) अन्तरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) जारी करके इसे ट्राई द्वारा विनियमित करने की मांग की गई थी। यह विनियम 10 दिसम्बर, 2004 को जारी किया गया अर्थात् इसे 1-1/2 वर्ष से पहले जारी किया गया था। इस अवधि के दौरान कुछ नए मुद्दे सामने आए हैं। इस अवधि के अनुभव से पता चलता है कि अन्तरसंयोजन विनियम से संबंधित कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्तरसंयोजन विनियमों के कार्यान्वयन के कारण कुछ विवाद तथा मुकदमेबाजी भी हुई। इस प्रकार अन्तरसंयोजन विनियमों को स्पष्ट करने और इसके क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता समझी गई ताकि संदेह की स्थिति कम से कम हो और विवाद/मुकदमेबाजी भी कम हो।

टीवी चैनल के सिगनलों का वियोजन

2. विनियम में निर्धारित नोटिस अवधियों के कारण विशिष्ट मामलों में लागू नोटिस अवधि के बारे में कई विवाद खड़े हुए। नोटिस की एक अवधि रखकर, इन विवादों से बचा जा सकता है। इसके अलावा, नोटिस की कम अवधि से कोई लाभ नहीं होगा और सिगनलों के वियोजन के लिए नोटिस जारी करने के मामलों में सही कारण दब जाएंगे और उपभोक्ता को सही मुद्दे की जानकारी विवाद के बाद ही होगी। नोटिस की अवधि पर्याप्त होनी चाहिए ताकि प्रभावित पार्टी, समुचित मंच में जाकर इसपर हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर सके और उपभोक्ताओं को भी अपने हितों को सुनिश्चित करने के लिए समुचित मंच में इस मुद्दे को उठाने का मौका मिले और उन्हें इस विवाद की वजह से हानि न हो। साथ ही सिगनलों की चोरी के मामलों में किसी भी प्रकार का नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इसके अतिरिक्त यदि टीवी चैनलों के वितरक, ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ किसी विवाद के कारण किसी खास चैनल के सिगनल स्विच ऑफ करने का निर्णय करें तो उपभोक्ताओं के साथ-साथ ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तदनुसार उनके हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है कि टीवी चैनल के सिगनलों के वियोजन के बारे में उन्हें भी इसी प्रकार का अग्रिम नोटिस प्राप्त हो। अतः सिगनलों के वियोजन के बारे में अग्रिम नोटिस देने की आवश्यकता में टीवी चैनलों के वितरकों को भी शामिल किया गया है।

4. सार्वजनिक नोटिस जारी करने का प्रयोजन उपभोक्ताओं को इस मुद्दे को समुचित मंच में उठाने का मौका देना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे विवाद की वजह से जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई हानि न हो। बहरहाल, यदि सेवा प्रदाताओं को नोटिस देते समय सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की जाती है और इसे काफी बाद में जारी किया जाता है जिससे उपभोक्ताओं को इस मुद्दे को समुचित मंच में उठाने के लिए बहुत कम समय मिलता है तो इसका प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। तदनुसार यह आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को नोटिस, इस अवधि के प्रारंभ होने से पहले ही प्राप्त हो। यह देखते हुए ही कि केवल टीवी देश के दूरस्थ भागों तक पहुंच गया है इसलिए नोटिस की अवधि पर्याप्त होनी चाहिए ताकि प्रभावित पार्टियां इस मुद्दे को समुचित मंच में उठा सकें।

5. देश में देशी भाषाओं के समाचारपत्रों की पहुंच, अंगरेजी भाषा के समाचारपत्रों से ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा कवरेज के लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक सूचना स्थानीय भाषा के समाचारपत्र के स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया जाना चाहिए।

6. संबंधित सेवा प्रदाता को दिए जाने वाले नोटिस में सेवा प्रदाता को प्रस्तावित वियोजन के कारण स्पष्ट सूचित किए जाना चाहिए। नोटिस जारी करने का कारण करार का उल्लंघन है बताने के बजाय नोटिस में करार की उन शर्तों का उल्लेख होना चाहिए जिनका कथित तौर पर उल्लंघन हुआ हो और इस प्रकार के उल्लंघन का ब्योरा दिया जाना चाहिए। ऐसा

करना इसलिए आवश्यक है जिससे विवाद के निश्चित कारणों का पता लग सके ताकि प्रभावित पार्टी या तो उल्लंघन के मामले ठीक कर सके या इस मुद्दे के समाधान के लिए इसे समुचित मंच पर उठा सके। इसी प्रकार सार्वजनिक नोटिस में प्रस्तावित वियोजन के कारण संक्षेप में दिए जाने चाहिए।

सामग्री अभिगम

7. सिगनल के लिए किए गए अनुरोध पर कार्रवाई करने की समय-सीमा निर्धारित करने का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है यदि सिगनल के लिए अनुरोध करने वाले टीवी चैनलों के वितरक के अनुरोध को समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा अपने एजेंट/मध्यस्थ को या ऐसे एजेंट/मध्यस्थ द्वारा ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को भेज दिया जाता है और समय सीमा नए सिरे से शुरू कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त सेवा प्रदाता के लिए यह आसान है कि वह समय-सीमा समाप्त होने से पहले कुछ ब्यौरा मांग कर अनुरोध पर कुछ कार्रवाई शुरू कर दे और तत्पश्चात् पूरक ब्यौरा मांग कर इस प्रक्रिया को ज्यादा समय तक खींच ले। अतः एक ऐसी समय-सीमा निर्धारित करना आवश्यक है जिसमें या तो टीवी चैनलों के वितरकों को सिगनल मुहैया कराए जाएंगे या उसे वे विशिष्ट शर्तें सूचित की जाएंगी, जिन्हें पूरा करने पर सिगनल मुहैया किए जाएंगे।

ब्राडकास्टर के एजेंट के रूप में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर

8. सी टीवी नेटवर्क लि. के मामले में टीडीसैट के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। अतः प्राधिकरण के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह इस बारे में कोई विनियम बनाए। इस प्रकार विनियम में किसी एमएसओ को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, किसी ब्राडकास्टर के एजेंट के रूप में नियुक्त करने की मनाही होगी या नहीं और इससे सम्बद्ध मामले, इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अन्ततः निर्भर करेंगे। अतः प्राधिकरण ने इस संबंध में आगे कार्रवाई न करने और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया है, जो सभी सम्बन्धितों के लिए बाध्यकारी होगा।

भुगतान में चूक

9. जब वे बकाया देय राशि को भुगतान करने में समर्थ न हों या भुगतान करने में अनिच्छुक हों तो कभी-कभी एलसीओ अपने सम्बद्ध एमएसओ को बदल देते हैं। इसके परिणामस्वरूप, उनके सम्बद्ध एमएसओ के लिए यह डूबा ऋण हो जाता है और एमएसओ, एलसीओ के भाग की देय राशि को ब्राडकास्टर को भुगतान करने में असमर्थ रहता है। ब्राडकास्टर भी ऐसे एमएसओ, जिससे ऐसा दोषी एलसीओ सम्बद्ध होता है, इस प्रकार की देय राशि वसूल करने में समर्थ नहीं होते। दूसरी ओर बीजक नियमित तौर पर जारी न किए जाने पर एलसीओ को अचानक पता चलता है कि उनका भारी बकाया देय है, जिसका भुगतान करने का उनके पास कोई साधन नहीं है। इस समस्या का समाधान यह सुनिश्चित करके किया जा सकता है कि एलसीओएस को मासिक आधार पर बीजक जारी किए जाएं जिनमें बकाया राशि तथा वर्तमान देय राशि स्पष्टतः दर्शायी जाए। ऐसी स्थिति में जब कोई एलसीओ किसी नए एमएसओएस के साथ सम्बद्ध होना चाहे तो तब नवीनतम बीजक में स्पष्टतः दर्शाया गया होगा कि एलसीओ पर कितनी राशि बकाया है। साथ ही इससे एलसीओ का भी अप्रत्याशित, अकस्मात् बकाए के भुगतान से बचाव होगा।

परिचालन का क्षेत्र और सब्सक्राइबर आधार

10. सब्सक्राइबर आधार शब्द, एड्रेसेबिलिटी की अनुपस्थिति में अस्पष्ट है, क्योंकि गैर-कैस क्षेत्रों में किसी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कितने सब्सक्राइबरों को सेवा मुहैया कराई जा रही है, इसकी वास्तविक संख्या जांच पाना असंभव है। अतः करार वास्तविक सब्सक्राइबर आधार के अनुसार करना संभव नहीं है अतः अन्तरसंयोजन करार के लिए सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण करने के लिए विचार-विमर्श पूर्णतः टीवी चैनलों के वितरकों द्वारा सेवित किए जाने वाले क्षेत्र पर आधारित होता है। बहरहाल, सब्सक्राइबरों की वास्तविक संख्या सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस), जहां एड्रेसेबल प्रणाली मुहैया कराई गई होती है, द्वारा पता लगती है। अतः ऐसी स्थिति में एसएमएस द्वारा ही सब्सक्राइबर आधार का वास्तविक पता चलता है।

जैसाकि ऊपर पैरा-8 में उल्लेख किया गया है, सी टीवी नेटवर्क लिमिटेड के मामले में टीडीसैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है तथा केबल ऑपरेटर और एमएसओ के सब्सक्राइबर आधार के निर्धारण से संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील में उठाया गया है। बहरहाल, उच्चतम न्यायालय के दिनांक 02 मार्च, 2006 के अंतरिम आदेश में प्राधिकरण को टीवी चैनलों के वितरकों के सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया को शुरू करने की विशेष रूप से अनुमति प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि —

“ इसके अलावा यदि वे ऐसा करना चाहें इन मामलों का लंबित रहना केन्द्र सरकार द्वारा कैसे लागू करने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं है और यदि ट्राई टीवी चैनलों के प्रत्येक वितरक के सब्सक्राइबरों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई प्रणाली विकसित करना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है। ”

माननीय उच्चतम न्यायालय के इस विचार के दृष्टिगत प्राधिकरण ने टीवी चैनलों के प्रत्येक वितरक के सब्सक्राइबरों के सही संख्या का पता लगाने तथा उसका निर्धारण करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने का कार्य शुरू किया है।

टीवी चैनलों का प्रसारण तथा वितरण से संबंधित प्राधिकरण ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2004 की अपनी सिफारिशों में यह माना है कि धीरे-धीरे एड्रेसेबिलिटी की तरफ बढ़ना आवश्यक है तथा इसे पूरे देश में तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। इन सिफारिशों में, प्राधिकरण ने केबल ऑपरेटरों तथा मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा सब्सक्राइबरों का रजिस्टर रखे जाने की सिफारिश की थी। प्राधिकरण ने यह सिफारिश दी थी कि:—

“ सभी केबल ऑपरेटर तथा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर सब्सक्राइबरों का एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें सब्सक्राइबरों के नाम, पते, प्रभारित किया जाने वाला

मासिक शुल्क तथा उनके द्वारा लिए गए चैनलों की संख्या का विवरण होगा। जब कभी प्राधिकृत अधिकारी यह देखने के लिए कि किसी विनियम के उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है इसकी जांच करने के लिए निरीक्षण करना चाहे तो इस रजिस्टर को उसके समक्ष, निरीक्षण प्रस्तुत किया जाएगा

एड्रेसेबिलिटी तथा सब्सक्राइबर्स के रजिस्टर की अनुपस्थिति में, टीवी चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के सब्सक्राइबर्स की संख्या का पता लगाना कठिन है। इस बाध्यता के बावजूद, प्राधिकरण ने टीवी चैनलों के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर के सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण करने के लिए एक तरीका मुहैया कराया है।

11. क्षेत्र का विस्तार होने पर विवाद उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि एड्रेसेबिलिटी के बिना, वास्तविक सब्सक्राइबर आधार का पता लगाना असंभव है तथा सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। परिचालन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सब्सक्राइबर आधार के संबंध में की जाने वाली वार्ता से सीधा संबंध है। बहरहाल, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के मौजूदा परिचालन क्षेत्र के बाहर कार्य कर रहे किसी केबल ऑपरेटर को मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा फीड करने का कार्य सब्सक्राइबर लाइन रिपोर्ट (एसएलआर) पर आधारित समझौता शर्तों के आधार पर किया जा सकता है। इसी प्रकार, केबल ऑपरेटर का परिचालन क्षेत्र का विस्तार भी सब्सक्राइबर लाइन रिपोर्ट (एसएलआर) पर प्रतिबिम्बित होगा।

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर

12. ब्राडकास्टर से सीधे सिगनल प्राप्त करने पर बहुत छोटे सब्सक्राइबर आधार के टीवी चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या से संबंधित विवादों को टीवी चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर के परिचालन क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण करके कम किया जा सकता है तथा उससे कम संख्या होने पर कोई भी ऑपरेटर ब्राडकास्टरों से सीधे सिगनल प्राप्त नहीं कर सकेगा। बहरहाल, इस आंकड़े को देश के विभिन्न भागों में सबसे छोटे सब्सक्राइबर आधार वाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा सेवित सब्सक्राइबर्स की संख्या के संबंध

में विभिन्न ब्राडकास्टर्स के लिए नगर वार डाटा का विस्तृत विश्लेषण करने के उपरांत ही अधिसूचित किया जा सकता है। इस समय, प्राधिकरण द्वारा ऐसी संख्या का निर्धारण करना संभव नहीं है। प्राधिकरण द्वारा संबंधित डाटा का विश्लेषण करने के बाद, यदि संभव हुआ, तो उसका निर्धारण बाद में किया जाएगा।

करारों का नवीकरण

13. करारों का नवीकरण अधिकांश मामलों में आसानी से हो जाता है, लेकिन समस्या तब आती है, जब नवीकरण के लिए समझौता-वार्ता मूल करार की समाप्ति के बाद भी जारी रहती है। मूल करार की तारीख बीत जाने के उपरांत सिगनल जारी रखने से संबंधित शर्तों को शासित करने के लिए मूल करार तब तक जारी रखा जा सकता, जबतक कि नवीकरण से संबंधित शर्तों पर कोई करार नहीं हो जाता। बहरहाल, ध्यान रहे कि नई वाणिज्यिक शर्तें मूल करार की समाप्ति की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगी। बहरहाल, यदि कोई करार नहीं हो पाता, तो इन विनियमों के विनियम-4 में किए गए उल्लेख के अनुसार साविधिक नोटिस देकर कोई भी पार्टी सिगनल वियोजित कर सकती है। मूल करार की शर्तें सिगनल वियोजित किए जाने की तारीख तक दोनों पार्टियों के लिए लागू होंगी। यह विश्वास किया जाता है कि पुराने करार की समाप्ति के तीन माह के भीतर (समझौता वार्ता के पांच माह के पश्चात्) पार्टियां नया करार कर लेंगी। बहरहाल, यदि इस अवधि के पश्चात् भी समझौता-वार्ता जारी रहती है, तो शर्तों के संबंध में कुछ नई अन्तरिम व्यवस्था पार्टियों के बीच तय होनी चाहिए तथा पुराने करार शर्तें इस अवधि के बाद स्वतः आगे जारी नहीं रहेंगी।

पे/फ्री टु एयर चैनलों का रूपांतरण

14. किसी भी चैनल की प्रकृति अर्थात् फ्री टु एयर या पे-चैनल में बार-बार बदलाव नहीं किया जाना चाहिए तथा सामान्यतः यह एक वर्ष की अवधि तक समान रहना चाहिए। वे ब्राडकास्टर जो अपने फ्री टु एयर चैनलों को पे-चैनल या पे चैनलों को फ्री टु एयर चैनल में बदलना चाहते हैं, उन्हें प्राधिकरण तथा आम-जनता को इस बारे में अग्रिम नोटिस देना चाहिए। कैस क्षेत्रों में ऐसा करना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसके लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स

को अपनी सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करना होगा। गैर-कैस क्षेत्रों के मामले में, इसके केबल सेवाओं के भुगतान में होने वाले संभावित परिवर्तनों तथा चैनलों की संभावित अनुपलब्धता के बारे में सूचित किया जाएगा।

संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव

15. दिनांक 12 जुलाई, 2002 के "दूरसंचार अन्तरसंयोजन (संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव) विनियम" के समान संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव पर एक विनियम जारी करने की विभिन्न वर्गों द्वारा मांग की गई है। इससे ब्राडकास्टर्स को ऐसे संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव का मसौदा इस प्रकार तैयार करने की सुविधा प्राप्त होती है जिसमें उनके सरोकारों को ध्यान में रखा गया हो। प्राधिकरण द्वारा संभावित हस्तक्षेप का प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि संदर्भ अन्तरसंयोजन प्रस्ताव से किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिस प्रकार से ब्राडकास्टर्स द्वारा मानक करार कर मसौदा तैयार किया गया है, इससे मुकदमेबाजी में कमी होगी। सेवा प्रदाता पारस्परिक करार से ऐसे आरआईओ के उपबंधों की विचलन कर सकते हैं। यह सेवा प्रदाताओं को विशेष वाणिज्यिक परिस्थितियां, जो कि किसी क्षेत्र या करार विशेष में उपलब्ध हो सकती हैं, को ध्यान में रखते हुए लचीलापन अपनाने की सुविधा-प्रदान करता है। एमएसओ के लिए ऐसे भी आरआईओ का होना भी वांछनीय है। बहरहाल, ऐसे एमएसओ की बड़ी संख्या को देखते हुए, प्राधिकरण द्वारा इस कार्य को करना व्यावहारिक नहीं है।

अंतिम चरण (लास्ट माइल) में एकाधिकार

16. अंतिम चरण (लास्ट माइल) में एकाधिकार के मुद्दे का समाधान डीटीएच और आईपीटीवी जैसे नए प्लेटफार्मों के कारण संवर्धित प्रतिस्पर्धा के द्वारा काफी हद तक हो जाने की संभावना है। दो डीटीएच सेवा प्रदाता पहले से ही अपनी सेवा दे रहे हैं तथा देश में आईपीटीवी सेवा भी निकट भविष्य में शुरू होने की संभावना है। अतः, इस समय, प्राधिकरण ने नए प्लेटफार्मों से होने वाली प्रतिस्पर्धा की प्रगति पर नज़र रखने का निर्णय लिया है तथा यदि आवश्यक होगा तो बाद में इस पर हस्तक्षेप किया जाएगा।

कैरिएज शुल्क विनियम

17. कैरिएज शुल्क विनियमन का सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों तथा भारतीय केबल ऑपरेटर फ़ैडरेशन द्वारा विरोध किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रकार का विनियमन से विवादों में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान परिस्थितियों में कैरिएज शुल्क का विनियमन करना बहुत कठिन है क्योंकि इससे स्थिति (पोजीशनिंग) का भी विनियमन करना होगा। देश के विभिन्न भागों में दर्शकों की पसंद के विभिन्न पैटर्न हैं। केबल नेटवर्क की क्षमता भी काफी भिन्न-भिन्न होती है। अतः कैरिएज शुल्क का स्तर भी मांग तथा आपूर्ति के अंतर के आधार पर देश के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न होता है।

इस समय, 6000 से अधिक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर हैं जो विभिन्न प्रकार की लेखा पद्धतियों का अनुसरण करते हैं। कैरिएज शुल्क की अदायगी प्रायः नकद या किसी अन्य प्रकार से की जाती है। अतः कैरिएज शुल्क के रूप में वास्तविक भुगतान का पता लगाना संभव नहीं है। कैरिएज शुल्क एक अस्थायी प्रक्रिया है तथा डिजीटल केबल प्रणाली शुरू होने पर इसे समाप्त जो जाने की संभावना है।

01 अक्टूबर, 2004 को टीवी चैनलों का प्रसारण तथा वितरण संबंधी मुद्दों पर दी गई अपनी सिफारिशों में भी प्राधिकरण द्वारा कैरिएज शुल्क के मुद्दे की जांच की गई थी, जिसमें प्राधिकरण ने उल्लेख किया था कि:—

‘6.5 निरपवाद रूप से प्रसारित किए जाने वाले टीवी चैनल’ के मुद्दे के संबंध में एनालॉग मोड में सिगनल वहन करने में क्षमता की तंगी तथा केबल स्पेक्ट्रम पर स्पेस के लिए प्रतिस्पर्धा के परिणामों के मौजूदा परिदृश्य को ध्यान में रखा गया है। चूंकि डिजलीकरण एक दीर्घकालिक लक्ष्य है, अतः केबल अधिनियम और नियमों में उपलब्ध मौजूदा ‘आवश्यकमेव निर्वहनीय दायित्वों (मास्ट कैरी ऑबलिगेशन्ज) के अतिरिक्त इस विषय पर नया विनियम बनाने को कोई प्रस्ताव

नहीं है। जब भी क्षमता में संवर्धन होगा, 'अवश्य' निर्वहनीय' विनियम लागू किया जाएगा। अतः इस समय कैरिएज प्रभारों पर कोई विनियम नहीं होगा।"

दिनांक 14 सितम्बर, 2005 को केबल टीवी के डिजिटलीकरण की अपनी सिफारिशों में, प्राधिकरण ने यह सिफारिश की थी कि एक निर्धारित तिथि में बाद डिजिटलीकरण सेवाएं मुहैया कराने के लिए लाइसेंस प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई थी कि डिजीटल सेवाओं के लिए लाइसेंस में मौजूदा डीटीएच लाइसेंस की शर्तों के आधार पर चैनलों के भेदभाव रहित प्रसारण की ही व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि लाइसेंसधारी विभिन्न कंटेंट प्रोवाइडरों/चैनलों को बिना किसी भेदभाव के एक्सेस मुहैया कराएगा।

मसौदा विनियम पर परामर्श

18. प्राधिकरण ने 21 मार्च, 2006 को एक परामर्श नोट जारी करके संबंधित मुद्दों के जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की ताकि उन पर चर्चा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जा सकें। इसके पश्चात् 21 मार्च, 2006 के परामर्श नोट पर स्टैकहोल्डरों की टिप्पणियों तथा विचारों को ध्यान में रखते हुए एक परामर्श पत्र तैयार किया गया। दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 के अन्तरसंयोजन करारों का रजिस्टर (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) विनियम, 2004 से संबंधित मुद्दों को भी शामिल किया गया। इस परामर्श पत्र को 11 मई, 2006 को जारी किया गया। इस पर अनेकों टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं तथा उनका ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया गया है। चूंकि टिप्पणियों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए इन टिप्पणियों के सार को इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ अनुबंध में खण्ड दर खण्ड आधार संक्षेप में तैयार किया गया है। मुंबई में 16 जून, 2006 को तथा दिल्ली में 19 जून, 2006 को ओपन हाउस चर्चा भी की गई। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व इन सभी टिप्पणियों तथा ओपन हाउस चर्चा के दौरान की गई टिप्पणियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है, जैसाकि विनियमों में किए गए संशोधनों से स्पष्ट है।

“दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) अन्तरसंयोजन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006” के व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुबंध

ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं से संबंधित मुद्दों के संबंध में परामर्श पत्र पर
प्राप्त टिप्पणियों का सार

उन स्टेकहोल्डरों की विषय-सूची, जिन्होंने टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।

क्र.सं.	नाम	स्थान
1.	कर्नल वीसी खरे (सेवानिवृत्त)—केबल टीवी उद्योग पर्यवेक्षक	मुंबई
2.	स्टार इंडिया प्रा. लि. (स्टार)	नई दिल्ली
3.	यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूएसआईबीसी)	वाशिंगटन, यूएसए
4.	मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन (एमसीए)	सिंगापुर
5.	ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा. लि. (ईएसपीएन)	गुडगांव, हरियाणा
6.	आरटेल कम्यूनिकेशन्स लि. (आरटेल)	उड़ीसा
7.	श्री आलोक सहल, बीएनबी केबल्स (बीएनबी केबल्स)	कोलकाता
8.	एससी इन्टरप्राइजेज लि. (एससी)	नौएडा
9.	सिटी केबल नेटवर्क लि. (सिटी केबल)	नई दिल्ली
10.	इंडसइंड मीडिया एण्ड कम्यूनिकेशन लि. (आईएमसीएल)	मुंबई
11.	हैथवे केबल एण्ड डाटाकॉम प्रा. लि. (हैथवे)	मुंबई
12.	केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (कोफी)	नई दिल्ली

परामर्श के लिए मुद्दा

भौजूदा विनियमों में संशोधन

दो नोटिस की अवधियां

- क्या सिगनलों को डिस्कनेट करने से पूर्व टीवी चैनलों के किसी वितरक को नोटिस देने के लिए केवल एक नोटिस अवधि होनी चाहिए?
- यदि हां, तो नोटिस अवधि क्या होनी चाहिए तथा क्या यह अप्राधिकृत रि-ट्रांसमिशन/पाइरेसी के मामलों में भी लागू होनी चाहिए?
- यदि नहीं, तो उन विवादों से बचने के लिए क्या विनियम में परिवर्तन किया जाए कि कौन सी नोटिस अवधि लागू होगी, विशेषकर, अप्राधिकृत वितरण को कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए?

प्राप्त टिप्पणियां

1. नोटिस अवधि केवल एक होनी चाहिए तथा वितरकों के अपने नेटवर्कों पर ऐसे नोटिसों की स्करोलिंग के अलावा ब्रॉडकास्टर्स के न्यूज चैनलों पर स्करोल किया जाना चाहिए। अप्राधिकृत रि-ट्रांसमिशन/पाइरेसी का यदि पता चलता है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कानूनी कार्रवाही की जानी चाहिए क्योंकि प्राधिकृत वितरक की सहमति से ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि एक नोटिस अवधि ही होगी तो विवाद उत्पन्न नहीं होंगे। यदि नेटवर्क में ऐसे सिगनल का पता चलता है जो वितरक के नेटवर्क के संबंधित नहीं है तो ऐसे वितरण को अप्राधिकृत माना जाएगा। (कर्नल वी सी खरे (सेवानिवृत्त) केबल टीवी उद्योग पर्यवेक्षक)

2. टीवी चैनलों के प्राधिकृत वितरक के लिए केवल एक नोटिस अवधि होनी चाहिए। टीवी चैनलों के प्राधिकृत वितरक के सिगनलों को डिस्कनेट करने के लिए नोटिस अवधि।

(भुगतान न करने के दोषी होने के मामले सहित) एक सप्ताह की होनी चाहिए। टीवी चैनलों के अप्राधिकृत वितरक को डिस्कनेक्शन करने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी जानी चाहिए तथा उनके सिगनलों को बिना किसी नोटिस के तुरंत डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। यह सुझाव है कि "टीवी चैनलों के अप्राधिकृत वितरक" को परिभाषित किया जाए तथा इस विनियम के खंड 4.1 में "टीवी चैनलों के अप्राधिकृत वितरक" के रूप में संशोधित किया जाए जिसका अर्थ है कि ट्राई विनियमों के अनुसार, टीवी चैनलों का कोई वितरक, जो करार को रिन्यू करने में असमर्थ रहता है, और/अथवा निम्नलिखित में से कोई कार्रवाई करता है। ऐसी कार्रवाई करने के लिए दुष्प्रेरित करना है जैसे करार में संचालन क्षेत्र से आगे सेवाएं मुहैया करता है, पूर्वलिखित प्राधिकार के बिना नए ऑपरेटरों को कनेक्ट करता है (करार में विनिर्दिष्ट ऑपरेटरों के अलावा); सिगनलों को ब्लॉक, आशोधित या क्षति पहुंचाता है या फीड में कोई अन्य ओवर-ले जोड़ता है; पूर्व लिखित सहमति के बिना विषय-वस्तु टेप करता है और/या रिप्रोड्यूस करता है; तथा पूर्व लिखित सहमति के बिना संस्थापन पते से आईआरडी हटाता। विनियम के खंड 4.1 को " कोई भी ब्राडकास्टर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर प्रस्तावित कार्रवाई के संक्षिप्त कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सप्ताह का नोटिस किए बिना टीवी चैनलों के किसी वितरक के टीवी चैनलों को डिस्कनेक्ट नहीं करेगा के रूप में संशोधित किया जाए। बशर्ते कि टीवी चैनलों के अप्राधिकृत वितरक के मामले में, नोटिस अवधि ऐसी कार्रवाई के लिए टीवी चैनलों के अप्राधिकृत वितरक को कारण बताते हुए दो कार्य दिवस होंगे।" (स्टार)

3. सिगनलों के डिस्कनेक्शन की नोटिस अवधियों की कोई भी चर्चा टीवी चैनलों के प्राधिकृत वितरकों के संबंध में ही लागू होनी चाहिए। ट्राई को उन विभिन्न माध्यमों, जहां स्वीकृति के बिना सिगनल प्राप्त किए जाते हैं तथा इस्तेमाल के लिए लगाए जाते हैं, को पकड़ने के लिए "टीवी चैनलों के अप्राधिकृत वितरक" की अपनी परिभाषा को और स्पष्ट करना चाहिए। टीवी चैनलों के प्राधिकृत वितरकों के लिए जिनके लिए वितरण करार की समाप्ति मांगी जाती है, उनकी नोटिस अवधि ब्राडकास्टर तथा ऑपरेटर के बीच संविदात्मक मामला होना चाहिए। पूरे विश्व के अन्य बाजारों में विद्यमान मानदंडों के अनुसार, ट्राई को अपेक्षाकृत कम अंतर्वेधी विनियामक उपाय पर विचार करना चाहिए। (यूएसआई बोसी)

4. मौजूदा स्क्रीम 30 दिन की नोटिस अवधि पर परिकल्पित है। बहरहाल, ब्राडकास्टर लागत का भुगतान करके विषय वस्तु की सृजन करते हैं इसलिए उसमें अपनी लागत जोड़कर अपने सिगनल ब्राडकास्ट करते हैं तथा केबल ऑपरेटरों को सिगनल मुहैया कराते हैं। केबल ऑपरेटरों का भुगतान दायित्व महीने की पहली तारीख को सिगनल प्राप्त करने के 30 वें दिन से आरंभ होता है। इस प्रकार, मौजूदा संविदात्मक व्यवस्था के भाग के रूप में उनके पास 30 दिन का नोटिस पहले से होता है। इसे देखते हुए, इस नोटिस अवधि की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित कैस क्षेत्रों में तथा गैर-कैस क्षेत्रों में अलग-अलग अवधि होनी चाहिए क्योंकि परिस्थितियों क्रमशः एड्रेसेबल तथा गैर-कैस एड्रेसेबल होती हैं। (एमपीए)
5. विनियम में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे विवादों से बचा जा सके (क) दोनों पार्टियों के बीच किसी मौखिक करारों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए; (ख) अप्राधिकृत/रि-ट्रांसमिशन को प्रमोट करने वाले केबल ऑपरेटरों/एमएसओ को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए तथा (ग) कोई अन्य विवाद होने पर, केवल एक नोटिस अवधि होनी चाहिए जिसे स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया जाना चाहिए। (ईएसपीएन)
6. टीवी चैनलों के वितकों को सिगनलों की डिस्कनेक्शन से पूर्व केवल एक नोटिस अवधि दी जानी चाहिए। नोटिस अवधि कम से कम 30 दिन की होनी चाहिए तथा यह अप्राधिकृत रि-ट्रांसमिशन/पायरेसी के मामलों में भी लागू होनी चाहिए क्योंकि यदि नोटिस अवधि कुछ दिनों की होगी, जैसा कि अभी हैं, तो इससे ग्राहकों, जिनका अपना कोई दोष नहीं है, को ही परेशानी उठानी पड़ेगी। (बीएनबी केबल्स)
7. अलग-अलग कारणों के लिए अलग-अलग नोटिस अवधियों की आवश्यकता होती है। ये कारण इन से जुड़े हो सकते हैं। 1) वाणिज्यिक कारण: भुगतान न करना, बकाया, आदि, ऐसे स्थानों पर जहां प्रवेश शुल्क (2 बड़ी खेलकूद की स्पर्धा के मामले में) बढ़ाने के लिए वे चाहते हैं कि वहां के लोग इसे न देखें सिगनल उपलब्ध कराना इन मामलों में 30 दिन का

नोटिस लागू होना चाहिए; 2) सिगनलों की पायरेसी; अप्राधिकृत डिकोडरों का इस्तेमाल करके केबल नेटवर्क पर रि-डिस्ट्रीब्यूशन करना तथा 3) सिगनलों के डिफ्रिप्शन के लिए मुहैया कराए गए उपकरण का दुरुपयोग: प्राधिकृत सेवा से अधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए कार्ड स्प्लिटर्स का इस्तेमाल करना। मौजूदा विनियमों में वाणिज्यिक कारणों के कारण सिगनलों की डिस्कनेक्शन के लिए एक माह की अवधि निर्धारित है। जबकि पायरेसी के लिए यह 2 दिन है। अतः यह उचित है क्योंकि एक माह से अधिक पायरेसी को अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे डीटीएच जैसे प्रतिस्पर्धी नेटवर्क को कम आंके जाने के साथ-साथ ही अत्याधिक राजस्व की हानि होगी। किसी केबल नेटवर्क पर डीटीएच/आईपीटीवी डिकोडर के इस्तेमाल का एक उदाहरण दिया जा सकता है। डीटीएच के मामले में मोबिलिटी का मामला ऐसे मामलों में अधिक संवेदनशील होगा तथा डीटीएच सेवा प्रदाता पायरेसी की रिपोर्ट प्राप्त होते ही मिनिटों में एयर पर डिकोडर को स्विच ऑफ करके तेजी से कार्रवाई कर सकता है। फिंगर प्रिंटिंग तंत्र साधारण तकनीक है। अप्राधिकृत वितरण की परिभाषा में अन्य बातों के साथ-साथ किसी क्रास सेवा उपकरण (जैसे केबल प्लान्ट पर आईपीटीवी या डीटीएच बॉक्स) का इस्तेमाल करना शामिल है; किसी कार्ड स्प्लिटर्स का इस्तेमाल करना जिसके द्वारा किसी डिकोडर को मल्टी चैनलों को डिलीवर करने के लिए विकृत किया जाता है; अनुबंधित किसी नेटवर्क के अलावा किसी दूसरे नेटवर्क से, पूर्व सहमति के बिना सिगनलों को जोड़ना तथा उन पते, क्षेत्र या स्थान जहां वह ऑपरेटर करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, में डिकोडरों को ट्रांसपोर्ट करना शामिल है। (एएससी)

8. दो नोटिस अवधि देने की मौजूदा व्यवस्था — पहली भुगतान में कथित चूक होने के लिए तथा दूसरे पायरेसी के लिए जारी रहनी चाहिए। बहरहाल, पायरेसी के मामले में इस समय यथा निर्धारित 2 दिन की नोटिस बहुत कम है। कथित पायरेसी के मामले में नोटिस अवधि मौजूदा 2 दिन से बढ़ाकर कम से कम 7 दिन किया जाए ताकि दुष्प्रेरित तथा बेवजह की नोटिसों के मामले में चैनल के वितरक टीडीसैट से राहत प्राप्त कर सके। पायरेसी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: जहां चैनलों का कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी ऐसे डिकोडर से सिगनलों को वितरित करता है, जो अप्राधिकृत हो अर्थात् इस बारे में चैनलों के

वितरक की ब्राडकास्टर्स के साथ कोई व्यवस्था नहीं हुई है और वह चैनलों के किसी प्राधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर (एमएसओ/ऑपरेटर) से फीड नहीं ले रहा है तथा जहां चैनलों का कोई डिस्ट्रीब्यूटर को किसी विवाद के कारण ब्राडकास्टर द्वारा स्विच ऑफ कर दिया है तथा वह चैनलों को डिस्ट्रीब्यूटर ब्राडकास्टर/किसी अन्य एमसीओ से कोई व्यवस्था किए बिना उन सेवा क्षेत्रों में सिग्नल वितरित कर रहा हो, केवल ऐसे मामलों में ही 7 दिन का नोटिस लागू होना चाहिए तथा अन्य सभी मामलों में ब्राडकास्टर्स द्वारा 30 दिन का नोटिस अवश्य दिया जाना चाहिए। विकल्प के तौर पर यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि पायरेसी की सूचना स्पष्ट रूप से 2 कार्य दिवस पहले दी जाए ताकि प्रभावित पार्टी टीडीसैट के राहत प्राप्त कर सके। इन संदर्भ में कार्य दिवस परिभाषित किए जाने चाहिए ताकि इनका अर्थ टीडीसैट तथा ट्राई द्वारा कार्य किए जाने वाले दिवस हो और शनिवार, रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश विशेष रूप से शामिल नहीं किए जाने चाहिए। (सिटी केबल)

9. केवल 30 दिन का नोटिस अवधि - होना चाहिए और या सभी मामलों में लागू होना चाहिए (इसे 'अप्राधिकृत वितरण' नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसके मामले में कोई नोटिस अपेक्षित नहीं है) उस व्यक्ति/पार्टी, जिसने करार पर हस्ताक्षर किए हैं या जिसने ब्राडकास्टर्स को भुगतान किया है, को अप्राधिकृत वितरण का दोषी नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह किसी ब्राडकास्टर का लाइसेंसधारी/प्राधिकृत वितरक होता है क्या क्षेत्र से बाहर का वितरण एक वाणिज्यिक विवाद है जो करार से उत्पन्न होते हैं जिसके लिए विवाद निपटान प्राधिकरण (टीडीसैट) अंतिम प्राधिकरण है। ब्राडकास्टर्स के एमएसओ से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइबर्स की संख्या पर वाणिज्यिक विवाद का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे विवादों के लिए ब्राडकास्टर्स द्वारा एक पक्षीय माध्यस्थ निर्णय लेने के बजाए टेलीकॉम अधिकरण का निर्णय प्राप्त करना चाहिए। अप्राधिकृत वितरण को दो भागों में परिभाषित किया जाना चाहिए: (i) यदि ब्राडकास्टर द्वारा अपने प्राधिकृत आईआरडी के लिए किसी एमएसओ को स्विच ऑफ कर देता है परन्तु वह किसी अन्य एमएसओ/आईसीओ के माध्यम से किसी विशेष ब्राडकास्टर के सिग्नलों को उनमें से किसी की भी लिखित सहमति प्राप्त किए बिना ट्रांसमिट करता है और (ii) कोई व्यक्ति, जो ब्राडकास्टर से सीधे या किसी एक एमएसओ/केबल ऑपरेटर के

माध्यम से कोई व्यवस्था किए बिना ब्राडकास्टर्स के सिगनलों का वितरण करता है।
(आईएमसीएल)

10. दो नोटिस की अवधियों की वर्तमान व्यवस्था उचित है क्योंकि ऐसे कई निर्णय हैं जो दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 के अन्तरसंयोजन विनियम से उत्पन्न हुए हैं। किसी विनियम तथा व्यवस्था में सामंजस्य बिठाया जाना चाहिए ताकि किसी भग्न से बचा जा सके। टीवी चैनलों के अप्राधिकृत वितरण के लिए दो दिन की नोटिस अवधि पर प्राधिकरण द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है। नोटिस दो कार्य दिवस का होना चाहिए जिसमें प्रिंट में प्रकाशन की तारीख/टीवी चैनलों पर स्करोल को छोड़कर तथा उस तारीख को छोड़कर जो सार्वजनिक अवकाश/शनिवार/रविवार को पड़ते हैं, ताकि उस व्यक्ति/उद्यम, जो डिस्कनेक्शन/कथित पायरेसी की कार्रवाई से प्रभावित है, को प्राधिकारी अधिकरण के सम्मुख अपना पक्ष रखने का समय मिल सके। (हैथवे)

11. 30 दिन की केवल एक नोटिस अवधि ही होनी चाहिए तथा यह सभी मामलों में लागू होनी चाहिए। 'अप्राधिकृत वितरण' के लिए कोई नोटिस अपेक्षित नहीं होना चाहिए यदि उस पार्टी के साथ कोई पूर्व व्यवसाय न हो। उस व्यक्ति/पार्टी, जिसने किसी करार में हस्ताक्षर किए हैं या ब्राडकास्टर को भुगतान किया है, को अप्राधिकृत वितरण का दोषी नहीं माना जा सकता क्योंकि वह किसी ब्राडकास्टर का लाइसेंसधारी/प्राधिकृत वितरक है और बाहरी क्षेत्र में वितरण एक वाणिज्यिक विकार है जो कि करार से उत्पन्न हुआ है जिसके लिए विवाद निपटान अधिकरण (टीडीसैट) अंतिम प्राधिकरण है। सब्सक्राइबर्स की संख्या पर वाणिज्यिक विवाद, पारस्परिक रूप से बढ़ाई गई भुगतान को मांगना तथा ब्राडकास्टर्स द्वारा मौजूदा संबद्ध एमएसओ/केबल ऑपरेटरों से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए संचालन क्षेत्र संबंधी विवादों को अप्राधिकृत वितरण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ऐसे विवादों के लिए ब्राडकास्टर्स द्वारा लिए गए एक पक्षीय निर्णय के बजाए टेलीकॉम अधिकरण का निर्णय प्राप्त किया जाना चाहिए। अप्राधिकृत वितरण को दो भागों में परिभाषित किया जाना चाहिए: (i) यदि ब्राडकास्टर द्वारा अपने प्राधिकृत आईआरडी के लिए किसी एमएसओ को स्विच ऑफ कर देता है परन्तु

वह किसी अन्य एमएसओ/केबल ऑपरेटर से उनमें से किसी की भी पूर्व लिखित सहमति लिए बिना उस विशेष ब्राडकास्टर के सिगनलों को ट्रांसमिट करता रहता है तथा (ii) कोई व्यक्ति, जिसके पास न तो ब्राडकास्टर से सीधे या किसी एमएसओ/केबल ऑपरेटर के माध्यम से कोई सहमति लिए बिना ब्राडकास्टरों के सिगनलों को वितरित करता है। (कोफी)

परामर्श के मुद्दे

कनेक्शन काटने का नोटिस

- क्या नोटिस अवधि की गणना सार्वजनिक नोटिस जारी करने की तारीख से की जानी चाहिए?
- क्या चैनलों पर स्क्रीन चलाकर सार्वजनिक नोटिस देने के लिए ब्राडकास्टरों/एमएसओ के मौजूदा विकल्प को हटा दिया जाना चाहिए?
- उन मामलों में, जहां ब्राडकास्टरों ने अपने चैनल स्विच ऑफ नहीं किए हैं, क्या एमएसओ तथा केबल ऑपरेटरों को कोई चैनल स्विच ऑफ करने से पहले ग्राहकों को नोटिस देना आवश्यक होगा?

प्राप्त टिप्पणियां

1. वितरक को पहले लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए, उसकी पावती लेनी चाहिए तथा उसके बाद प्रचारित करना चाहिए। ऐसे मामले में, नोटिस अवधि की गणना सार्वजनिक सूचना की तारीख से की जाएगी। सार्वजनिक नोटिस वितरक द्वारा पावती देने की तारीख का उल्लेख कर सकता है। चैनलों पर स्क्रीन चलाकर सार्वजनिक सूचना देने के ब्राडकास्टरों/एमएसओ के उपलब्ध विकल्प को हटाना नहीं चाहिए। नेटवर्क पर दर्शकों को हेडराइड ऑपरेटरों अर्थात् एमएसओ/वितरक द्वारा हेडएण्ड में हुक की चेतावनी अवश्य दी जानी चाहिए। (कर्नल बी. सी. खरे (सेवानिवृत्त)—केबल टीवी पर्यवेक्षक)

2. नोटिस अवधि की गणना सार्वजनिक सूचना के जारी होने के दिन से ही जानी चाहिए। चैनलों पर स्क्रीन के माध्यम से ब्राडकास्टर की विषय वस्तु को दर्शकों को दिखाना सम्प्रेषण का प्रभावी माध्यम है। अतः इसे निश्चित तौर पर नहीं हटाना चाहिए। बल्कि, प्रस्ताव है कि ट्राई को टीवी चैनलों के वितरक तथा दर्शकों को सूचना मुहैया कराने के लिए उसी स्क्रीन का इस्तेमाल करने की इजाजत ब्राडकास्टरों को देनी चाहिए। नोटिस अवधि न केवल, ब्राडकास्टरों तथा/या एमएसओ के लिए लागू होनी चाहिए बल्कि अंतिम उपभोक्ता को चैनलों का वितरक करने में लगे सभी उद्योगों, जिनमें लास्ट माईल ऑपरेटर भी शामिल है, पर भी लागू होनी चाहिए। एमएसओ और केबल ऑपरेटर के मनमाने ढंग से सिग्नल न देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, सिफारिश की जाती है कि ट्राई को "टीवी चैनलों का कोई वितरक प्रस्ताविक कार्रवाई विनियमन के खण्ड 4.1 ए में शामिल करना चाहिए कि वे कारणों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए ब्राडकास्टरों तथा ग्राहकों को एक सप्ताह का नोटिस दिए बिना ब्राडकास्टर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के टीवी चैनलों सिग्नलों को नहीं काटेगा"। टीवी चैनलों के वितरक द्वारा किसी चैनल के सिग्नलों को स्विच ऑफ करने की नोटिस अवधि वही होनी चाहिए जो ब्राडकास्टरों/एमएसओ के लिए लागू है। विनियम के खण्ड 4.2 को संशोधित किया जाए कि "टीवी चैनलों के ब्राडकास्टर/वितरक उस विवाद के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करेंगे ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें। तदनुसार, सिग्नल काटने की सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में भी दी जाएगी यदि टीवी चैनलों का वितरण लोकल एरिया में ऑपरेटर कर रहा है और यदि वितरक किसी बड़े क्षेत्र में सेवा मुहैया करा रहा है तो दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी दी जाएगी। विकल्प के तौर पर, ग्राहकों को संबंधित चैनल पर स्क्रीन के माध्यम से सूचित किया जा सकता है। टीवी चैनलों के वितरक संबंधित चैनल में स्क्रीन अवश्य करेंगे"। इसके अलावा, ऐसे एमएसओ तथा केबल ऑपरेटरों को उस दशा में 'मस्ट प्रोवाइड' विनियम के लाभ का पात्र नहीं होना चाहिए क्योंकि तब वे ट्राई द्वारा जारी विनियमों का उल्लंघन करते हैं। (स्टार)

3. नोटिस अवधि की गणना सार्वजनिक सूचना जारी करने के दिन से की जानी चाहिए। इसके अलावा, सिग्नल प्राप्त होने तथा विनियमित समय पर भुगतान करने के बीच के

समयावधि के कारण वस्तुतः 30 दिन की अवधि पहले से ही तय है। ब्राडकास्टर्स को स्क्रौल की पेशकश करने की प्रथा को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि सेवा आपराधिक जिम्मेवारियों के कारण बन्द नहीं की जाती है बल्कि किसी चैनल की डिलीवरी को रोकने का एक व्यावसायिक निर्णय है तो ऐसे निर्णय महत्वपूर्ण रूप से ऐसी सेवा के रद्दीकरण के समय लिए जाते हैं जिसमें सेवा के ऐसे लंबित परिवर्तन की सूचना ग्राहकों को दी जाती है। इस समय, एमएसओ तथा केबल ऑपरेटर न तो उपभोक्ताओं को और न ही ब्राडकास्टर्स को कोई सूचना दिए बगैर ब्राडकास्टर्स के सिगनल काट देते हैं। ब्राडकास्टर तथा आपरेटर्स के बीच की नोटिस अवधियों को संविदात्मक करार पर छोड़ देना बेहतर है परन्तु समानता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि ट्राई के विनियम एक दूसरे के पूरक हों बनाए जाते हैं। केबल ऑपरेटर्स तथा सब्सक्राइबर्स के बीच विनियमित नोटिस अवधि के संबंध में विनियामन हस्तक्षेप का कुछ औचित्य यह दिया जाता है कि इस संबंध में समझौते करने में उपभोक्ता अपने अंतिम सेवा प्रदाता को महत्व नहीं देते हैं। इसलिए, यह आवश्यक होना चाहिए कि उपभोक्ता सिगनलों के स्विच ऑफ किए जाने से पहले एमएसओ तथा केबल ऑपरेटर्स से अधिसूचना प्राप्त करते हैं। (यूएसआईबीसी)

4. किसी क्षेत्र में कैस लागू किए जाने के बाद पहले महीने में होने वाले घोषणा से संबंधित सभी विवादों के लिए नोटिस अवधि 30 दिन हो सकती है। पहले महीने के बाद, पायरेसी से संबंधित सभी डिस्कनेक्शन तुरंत किए जा सकते हैं ताकि और पायरेसी से बचा जा सके। उन कारणों से हुए डिस्कनेक्शन के मामले में, जो पायरेसी से जुड़े नहीं हैं, नोटिस अवधि 7 दिन की हो सकती है इस अवधि में इम्पेंडिंग डिस्कनेक्शन के बारे में उपभोक्ताओं को आगाह करने के लिए सिगनल में स्क्रौल इनसर्ट किया जा सकता है। एमएसओ/एलसीओ के साथ हुए ब्राडकास्टर के समझौते/करार में "अप्राधिकृत प्रदर्शन" की गुजाइश को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। (एमपीए)

5. नोटिस अवधि की गणना सार्वजनिक सूचना के जारी होने के दिन से की जानी चाहिए। समाचारपत्रों (राष्ट्रीय/दैनिक) के माध्यम से उपभोक्ताओं को अधिसूचित करना काफी

महंगा सौदा होता है। इसलिए चैनलों का स्क्रोल चलाकर जनसूचना देने के लिए ब्राडकास्टरों/एमएसओ के पास उपलब्ध विकल्प को बंद नहीं कर देना चाहिए। बल्कि एक निर्धारित अवधि होनी चाहिए। जिस दौरान चैनलों का स्क्रोल चलाए जा सकते हैं। यदि ब्राडकास्टर ने यह व्यवस्था उपलब्ध कराई है तो केबल ऑपरेटर/एमएसओ को चैनल स्विच ऑफ करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऑपरेटर/एमएसओ की पर कार्रवाई उपभोक्ताओं के अधिकारों को हनन करना होगी इसलिए इसे हर हालत में हतोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा, यदि इसमें "मस्ट प्रोवाइड" विनियम है तो केबल ऑपरेटरों/एमएसओ के लिए भी "मस्ट कैरी" विनियम होना चाहिए। (ईएसपीएन)

6. जी हां, नोटिस अवधि की गणना जन सूचना के दिन से की जानी चाहिए। स्क्रोल चलाने के विकल्प को हटा देना चाहिए। उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार के स्विच ऑफ की सूचना दी जानी चाहिए चाहे वह ब्राडकास्टर की ओर से हो जा एमएसओ की ओर से या केबल ऑपरेटर की ओर से क्योंकि यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से बनाया गया है। (बीएनबी केबल्स)

7. सही मायने में नोटिस अवधि लिखित रूप में सेवा प्रदाता द्वारा उपयोगकर्ताओं को सूचित करने के दिन से आरंभ होनी चाहिए तथा उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करने के 7 दिनों के भीतर जनसूचना अनिवार्य की जानी चाहिए। चैनलों पर स्क्रोल चलाना एक परिहार्य न्यसेंस होता है। इस्तेमाल किए जाने वाले डिकोडर्स में एड्रेसेबिलिटी होनी चाहिए ताकि इम्पेंडिंग डिस्कनेक्शन के बारे में किसी विशेष ऑपरेटर को ही आगाह किया जा सकता हो। सस्ते डिकोडरों से भी अब ऐसे एड्रेसेबल मैसेजिंग स्पोर्ट होते हैं। प्राधिकरण को यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि वह स्टॉक टिकरों से बचें और किसी क्षेत्र में स्क्रीन पर बलपूर्वक प्रदर्शित किए जा रहे मैसेजिंग को एक अनिवार्य बना देना चाहिए। यदि एमएसओ या केबल ऑपरेटर या कोई सेवा प्रदाता अपनी ओर से कोई सेवा स्विच ऑफ करना चाहता है तो उसे स्विच ऑफ करने से पहले सब्सक्राइबर्स को नोटिस देनी चाहिए। ब्राडकास्टर या सेवा प्रदाता के लिए उचित होगा कि वह जानता हो कि उसकी सेवाएं उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं के किसी

विशेष वर्ग में उपलब्ध नहीं होगी और वह उस क्षेत्र में किसी अन्य भिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से या अलग प्रौद्योगिकी के द्वारा उन सेवाओं की सुपुर्गों को वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है। (एमएससी)

8. नोटिस अवधि की गणना समाचारपत्रों में जनसूचना के जारी किए जाने की तारीख से की जानी चाहिए। ब्राडकास्टर के पास चैनल पर स्क्रीन चलाकर जन सूचना देने का विकल्प नहीं होना चाहिए और यह अनिवार्य होना चाहिए कि प्रस्तावित डिस्कनेक्शन की सूचना केवल समाचार पत्रों के माध्यम से ही दी जाए। किसी चैनल को स्विच ऑफ करने से पूर्व उपभोक्ताओं को नोटिस देना एमएसओ/केबल ऑपरेटरों के लिए संभव नहीं है क्योंकि अब अधिकांश ऑपरेटरों द्वारा 100 महीने से अधिक चैनल डिलीवर किए जा रहे हैं तथा नए चैनलों के लांच होने से नेटवर्क की क्षमता पर दबाव बढ़ने से चैनलों की शफलिंग करना बाधित हो गया है अन्यथा कोई भी नया चैनल कभी वितरित नहीं हो पाएगा। इसके अलावा, एमएसओ तकनीकी कारणों जैसे ऑडियो की खराबी या वीडियो के क्वालिटी की खराबी आदि जैसे कारणों के कारण चैनल को बंद करने के लिए बाधित हो सकता है। (सिटी केबल)

9. नोटिस अवधि उस तारीख से आरंभ होनी चाहिए जिस दिन यह समाचारपत्रों में जारी होता है या एमएसओ/सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किया जाता है। चैनलों पर स्क्रीन चलाकर जनसूचना देना सही है अन्यथा ब्राडकास्टर प्रचार के लिए किसी अज्ञात समाचारपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे उस नेटवर्क के कई सब्सक्राइबर शायद नहीं पढ़ते हों। (हालांकि ऐसे विज्ञापन जारी करने पर एमएसओ/केबल ऑपरेटर की निन्दा होती है और सब्सक्राइबर अपने बकायों का भुगतान करते समय समस्याएं खड़ी करते हैं।) एमएसओ तथा केबल ऑपरेटरों द्वारा किसी भी चैनल को स्विच ऑफ करने से पहले उपभोक्ताओं को सूचित करना अपेक्षित होता है और यह स्टेकहोल्डरों के बीच हुए करार का एक भाग हो सकता है अर्थात् नोटिस अवधि था सूचना। दूसरे शब्दों में, यदि किसी उपभोक्ता को सूचित किए जाने की आवश्यकता होती है तो एमएसओ ऐसे परिवर्तन करने के 3 दिन पहले अग्रिम सूचना दे सकता है और यदि कोई एमएसओ हमेशा के लिए किसी ब्राडकास्टर के सिगनल को स्विच ऑफ

करना चाहता है तो यह अवधि 30 दिन की होनी चाहिए। यदि ब्राडकास्टर किसी एमएसओ को 30 दिन का नोटिस देता है, तो निरपवाद रूप से अधिकांश मामलों में, चाहे टीडीसैट से हस्तक्षेप करने की मांग की गई हो या वह मामला पार्टियों के बीच निपटाया जाता है उस मामले में स्क्रोल पर ऐसी सूचनाएं देना या समाचारपत्रों में प्रकाशित करने का कोई अर्थ नहीं रहता है। दर्शकों को इसकी सूचना की जानी चाहिए कि उपर्युक्त निवारक उपायों का प्रयोग किया गया है अर्थात् टीडीसैट से कोई राहत नहीं मिली है और पार्टियों के बीच बातचीत असफल रही है और उस नेटवर्क पर उस ब्राडकास्टर के सिगनल स्विच ऑफ किया जा रहा है। (आईएमसीएल)

10. नोटिस अवधि में जनसूचना जारी करने की तारीख शामिल नहीं होनी चाहिए और इसमें सिगनलों को काटे जाने/डिएक्टिवेट करने की संभावित तारीख भी शामिल नहीं होनी चाहिए। चैनलों पर स्क्रोल चलाकर जन सूचनाएं देने के ब्राडकास्टरों/एमएसओ के तत्काल विकल्प को बंद नहीं करना चाहिए। किसी चैनल को स्विच ऑफ करने से पहले उपभोक्ताओं को सूचित करना एमएसओ तथा केबल ऑपरेटरों के लिए अपेक्षित नहीं होना चाहिए। कई बार ब्राडकास्टर धमकाने के लिए ही नोटिस दे देते हैं और उनका इरादा सिगनलों को काटने या डिएक्टिवेट करने का नहीं होता है बल्कि एमएसओ/एलसीओ पर रौब बनाए रखना होता है। (हैथवे)

11. नोटिस अवधि की गणना समाचारपत्रों में इससे प्रकाशन की तारीख से एमएसओ/केबल ऑपरेटर द्वारा पावती दिए जाने की तारीख से की जानी चाहिए। स्क्रीन पर स्क्रोल चलाकर जन सूचना देना बंद नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा ब्राडकास्टर किसी अज्ञात समाचारपत्रों में सूचना प्रसारित कर सकता है जिसे उन नेटवर्क के कई सबक्राइबर शायद नहीं पढ़ते हो। लेकिन यह माना जाता है कि ऐसे विज्ञापन एमएसओ और केबल ऑपरेटर के लिए निंदक हो सकते हैं क्योंकि ये उस नेटवर्क के सबक्राइबरों को भ्रम में डाल सकते हैं कि उनका केबल ऑपरेटर ब्राडकास्टर को अपने बकायों का भुगतान नहीं कर रहा है। जबकि सच्चाई कुछ और हो सकती है, हो सकता है अधिक आमदानी प्राप्त करने का विचार

ब्राडकास्टर तथा केबल ऑपरेटर के बीच सतहीपन पर कोई विवाद हो, जो अकसर हो जाते हैं। एमएसओ तथा केबल ऑपरेटरों को किसी चैनल को स्विच ऑफ करने से पहले उपभोक्ताओं को सूचित करना अपेक्षित होता है और यह स्टैकहोल्डरों के बीच हुए करार का हिस्सा हो सकता है अर्थात् नोटिस अवधि तथा सूचना। दूसरे शब्दों में, यदि किसी उपभोक्ता को सूचित किए जाने की आवश्यकता है तो एमएसओ ऐसे परिवर्तन करने से 7 दिन पहले अभिग्रह सूचना देने के लिए नेटवर्क पर स्क्रॉल चला सकता है और यदि एमएसओ हमेशा के लिए किसी ब्राडकास्टर के सिग्नल को स्विच ऑफ करना चाहता है तो इसके लिए 30 दिन हैं। सामान्यतः, ऐसे विवादों में पार्टियां 30 दिन की समाप्ति से पहले मामले को निपटाने के लिए टीडीसैट से संपर्क करती हैं ताकि सिग्नलों में कोई विघन न पड़े। यदि उपर्युक्त निवारक उपायों का इस्तेमाल किया जा चुका है और टीडीसैट से कोई राहत नहीं मिली है और पार्टियों के बीच बातचीत भी असफल हो गई है तो दर्शकों को उस नेटवर्क पर किसी ब्राडकास्टर के सिग्नल स्विच होने की सूचना दी जानी चाहिए। (कोफी)

परामर्श के मुद्दे

कंटेंट (विषय वस्तु) में एक्सेस

- क्या किसी ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के किसी एजेंट या किसी मध्यस्थ के लिए ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिसमें वे अनुरोध प्राप्त होने के भीतर सिग्नल मुहैया कराएं या अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण बताते हुए उसे स्वीकार कर दें ताकि टीवी चैनलों का वितरक बिना समय भंवाए किसी उपयुक्त मंच में इस मामले को उठा सके?
- क्या इस समय सीमा में टीवी चैनलों के उस वितरक जिसने अपने एजेंट या मध्यस्थ को सिग्नलों का अनुरोध किया है को हवाला देने के लिए ब्राडकास्टर द्वारा लिए गए समय को भी शामिल किया जाना चाहिए?
- क्या अन्तरसंयोजन विनियम में से अनिवार्य एक्सेस तथा नॉन-एक्सक्लूसिविटी अपेक्षा को हटा दिया जाए ताकि उन चैनलों को, किसी अन्य डिजिटल

प्लेटफार्म/सेवा या उस केबल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराए जाने की अनिवार्य अपेक्षा न हो जो केवल एक डिजीटल प्लेटफार्म/सेवा में ही उपलब्ध कराए जा रहे है?

- क्या विकल्प के तौर पर इन अपेक्षाओं को केवल चैनलों पर लागू किया जाए जो किसी विशेष तारीख से पहले बाजार में उपलब्ध हैं?

प्राप्त टिप्पणियां

1. यह स्थिति अब तक अलग-अलग पड़े सैटेलाइट कनटेंट को अपलिंक करने की प्रसारण विधि की प्रक्रिया के अभाव के कारण उत्पन्न हुई है। प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रवृत्तियों को रोकने की कार्यविधि विकसित की जानी है जिसमें अनुरोध पर कार्रवाई न करने के उन सभी कारणों को लिखित रूप में, एक अनुबंधित समय के भीतर, अवश्य संसूचित किया जाए ताकि आवेदक किसी उपयुक्त मंच पर इस मामले को उठा सके। दूरसंचार के मौजूदा तीव्र संसाधनों (टेलीफोन, ई-मेल, फैक्स आदि) के मददेनजर तय समय सीमा में ब्राडकास्टर के एजेंट द्वारा अपने प्रिंसिपल को सूचित किए जाने का समय शामिल होना चाहिए। ऐसे अनुरोध के लिए एक मानक फार्म का इस्तेमाल करना एक संभव हल हो सकता है, जिसकी परिशुद्धता से भरे जाने की जांच उपभोक्ता सेवा डेस्क पर की जा सकती है; इस बात की पावती दी जा सकती है कि आवेदन पत्र सभी संदर्भों से पूर्ण है और तब ऐसे पूर्ण आवेदन पत्रों को स्वीकार किए जाने की तारीख से समय सीमा लागू की जाए। मनाही के कारणों की लिखित सूचना में इस तथ्य-तथ्य का उल्लेख किया जाए कि प्रिंसिपल को अवगत करा दिया गया है। अन्तरसंयोजन विनियम में अपेक्षित अनिवार्य एक्सेस तथा नॉन-एक्सक्लूविटी की अपेक्षा को नहीं हटाया जाना चाहिए। यह अपेक्षा सभी चैनलों पर लागू होनी चाहिए चाहे भारतीय केबल टीवी के बाजार में उसके प्रवेश करने की तारीख कुछ भी हो। (कर्नल वी. सी. खरे (सेवानिवृत्त)-केबल टीवी पर्यवेक्षक)

2. आवेदकों के आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने की विधि सामान्यतया काफी लम्बी होती है और कई औपचारिकताओं जैसे पूर्ण प्रलेख, स्थल का दौरा आदि को पूरा किए जाने की आवश्यकता के कारण उनमें लगने वाला समय हर मामले में अलग-अलग होता है। इसे ध्यान में रखते हुए, कार्रवाई करने के लिए एजेंट/मध्यस्थ के लिए बाहरी समय-सीमा निरोपित करना अनुचित तथा अव्यावहारिक होगा। किसी नए उद्यमी के साथ दीर्घ व्यावसायिक संबंध बनाने के लिए अथक परिश्रम तथा जटिल व्यावसायिक संबंध स्थापित करने होते हैं। ये कार्यवाहियां आमतौर पर लंबी होती हैं। इस ध्यान में रखते हुए, स्टार इंडिया की राय है कि आवेदकों के आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने की कोई समय-सीमा नहीं होनी चाहिए। मौजूदा स्थितियों में विनियम के "मस्ट प्रोवाइड" तथा "नॉन-एक्सक्लूसिविटी" जैसे अति व्यापक उपबंधों की अन्य कारकों के अलावा इस कारण को मद्देनजर रखते हुए समीक्षा की जाने की आवश्यकता है कि इस समय सी एण्ड एस प्लेटफार्म पर उपभोक्ताओं के लिए 240 से अधिक चैनल उपलब्ध हैं। सी एण्ड एस लगभग 61 मिलियन उपभोक्ता गृहों में अपनी पहुंच के कारण ब्राडकास्टर्स के लिए एक वरीय प्लेटफार्म है। टीवी चैनलों के सभी वितरकों में सभी चैनलों की गैर-भेदभावपूर्ण एक्सेस को विनियम द्वारा अधिदेशित नहीं किया जाना चाहिए। स्टार इंडिया का मत है कि विनियामक तंत्र को उपभोक्ताओं के हित में तथा प्रतिस्पर्धा के लिए एक संतुलित मार्ग अपनाना चाहिए। स्टार इंडिया का मानना है कि इन अपेक्षाओं के अनुप्रयोग का आधार तारीख नहीं होना चाहिए। (स्टार)

3. सिगनलों की व्यवस्था करने के अनुरोध पर की जाने वाली कार्रवाई कई अलग-अलग कारकों पर निर्भर करती है जैसे अपेक्षित तकनीकी सूचना की व्यवस्था, वित्तीय व्यवहार्यता पर विचार करना, उस स्थल का निरीक्षण करना तथा आपूर्ति तथा वितरण की शर्तों पर समझौता करना। वास्तव में, इस कार्रवाई को अक्सर वितरक की ओर से विलंब किया जाता है। व्यावसायिक समझौते के लिए एक सीमित अवधि निर्धारित करना अव्यावहारिक है। अनिवार्य एक्सेस उपबंधों को हटा दिया जाना चाहिए। बाजार की विकृतियों के समाधान के लिए कीमतों को फ्रीज करना और अनिवार्य एक्सेस जैसे कुछ उपबंध हैं जो आज संपूर्ण विश्व में टेलीविजन विनियामक प्रणाली में शामिल हैं। अनिवार्य एक्सेस को सभी चैनलों के लिए समाप्त

कर दिया जाना चाहिए चाहे उस चैनल की भारत में चालू होने की तारीख कुछ भी हो।
(यूएसआईबीसी)

4. एक ऐसा पारदर्शी तंत्र होना चाहिए जो ब्राडकास्टरों या उनके एजेंटों को, उस केबल ऑपरेटर जिसे अपने सिगनल आगे रि-ट्रांसमिशन करने के लिए लाइसेंस देना अपेक्षित होता है, लाइसेंस देने से पहले उस केबल ऑपरेटर की विश्वसनीयता तथा व्यावहारिक प्रतिष्ठा का मूल्यांकन करने की अनुमति देता हो। यह तंत्र केबल ऑपरेटरों की जबाबदेही की न्यूनतम सीमा तय कर सके। यदि किसी केबल ऑपरेटर का संपर्क किसी अवांछनीय व्यक्ति से पाया जाता है तो ब्राडकास्टर उस ऑपरेटर को सिगनल देने से मना करने में समर्थ होना चाहिए। इस सादृश्य में, नए वैट रजिस्ट्रेशन के लिए आज किसी व्यवसायी को 1,00,000/-रु. तय की प्रतिभूति सरकार को मुहैया करानी होती है। बहरहाल, इस प्रतिभूति को कम करके 50,000/-रु. किया जा सकता है, यदि उसके पास निम्नलिखित से एक हो: फिक्सड लाइन का टेलीफोन; पासपोर्ट, परमानेंट एकाउंट नंबर (PAN)। इसी प्रकार की क्रियाविधि होनी चाहिए जिसमें कम से कम आयकर PAN नंबर या VAT (वैट) रजिस्ट्रेशन नंबर उस ब्राडकास्टर के सम्मुख प्रस्तुत करना अपेक्षित हो जिस पर सिगनल मुहैया कराने का दायित्व है। दूरसंचार विनियम 2004 के मददेनजर सिगनल की पेशकश गैर भेदभावपूर्ण आधार पर की जानी चाहिए परन्तु ये न्यूनतम वित्तीय व्यवहार्यता शर्तों पर होनी चाहिए जो पारदर्शी तथा उचित हो। अन्तरसंयोजन विनियमों में "मस्ट प्रोवाइड" दायित्व का कुछ एमएसओ और उनके संबद्ध पक्ष एलसीओ द्वारा अपनी सुविधा के अनुरूप गलत अर्थ लगाया जाता रहा है कि उनके पास जिसके लिए अपने व्यवसाय को बढ़ाने का उन्मुक्त अधिकार है ब्राडकास्टरों के प्रति उनकी कोई जबाबदेही नहीं है। प्रस्ताव है कि किसी वितरक द्वारा टेलीविजन चैनलों के सिगनलों के अनुरोध को या तो (क) उस अंतिम उपभोक्ता को सिगनल की रि-ट्रांसमिशन के अंतर्गत रखा जाए जो भुगतान करने में समर्थ हो तथा ब्राडकास्टर तथा वितरक के बीच हुए मौजूदा शर्तों के अनुसार उस विनिर्दिष्ट भौगोलिक-क्षेत्र में स्थित हो या (ख) उनके संचालन क्षेत्र पर आधारित एलसीओ को सिगनल रि-ट्रांसमिशन करने के अंतर्गत हो। इसके अलावा, सभी एमएसओ को अपने सभी उप-ऑपरेटरों, लिंक ऑपरेटरों तथा एलसीओ की सूची घोषित

करनी चाहिए और अपने प्रदत्त सब्सक्राइबर आधार के ब्यौरे मुहैया कराने में समर्थ होना चाहिए। अनिवार्य एक्सेस तथा नॉन एक्सक्लूसिविटी के उपबंधों को हटा देना चाहिए। मौजूदा बाजार की परिस्थितियों में सिगनल रिसीव करने के लिए उपभोक्ताओं के पास एक्सेस के कई साधन उपलब्ध है। इस प्रकार, बाजार शक्तियों को चैनलों की उपलब्धता का पता लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए और डिजीटल तथा एनालॉग चैनलों की उपलब्धता के बीच कोई मूलभेद नहीं होना चाहिए। (एमपीए)

5. कनटेंट के लिए अनिवार्य एक्सेस की कोई आवश्यकता नहीं है और बाजार शक्तियों को इन पहलुओं को तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे सब्सक्राइबरों को भी फायदा होगा। इसके अलावा, जहां तक पे चैनलों, और विशेष तौर पर स्पोर्ट्स चैनलों का संबंध है 'मस्ट कैरी' के उपबंध अवश्य होने चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स चैनल देश के खेलकूद तथा प्रतिभा के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। स्पोर्ट्स चैनलों की वृद्धि पर प्रतिबंध लगाने से स्वयं खेलकूद की वृद्धि पर प्रतिबंध लगेगा। (ईएसपीएन)

6. इस अधिनियम का उद्देश्य उन विसंगतियों को दूर करना है जो अभी तक दूर की जानी हैं। चूंकि, ब्राडकास्टर उनको अपने सिगनल मुहैया नहीं करा रहे हैं जिनके साथ पहले से ही पक्षपात किया जा रहा है बल्कि नए प्रतिभागियों को भी सिगनल देने से इन्कार किया जा रहा है। सिगनल उपलब्ध कराने का दायित्व खण्ड को और कड़ा बनाकर ब्राडकास्टर पर डाला जाना चाहिए। निर्धारित की गई समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और यह निश्चित किया जाए कि तीस दिनों से कम समयावधि के भीतर सिगनल उपलब्ध करा दिए जाएं। सिगनल के लिए अनुरोध करने वालों के लिए मानदण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए बजाय इसके कि ब्राडकास्टर प्रतिदिन नए मानदण्ड निर्धारित करे। यदि समय-सीमा का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है तो इस अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा और वास्तविकता यथापूर्व बनी रहेगी। समय-सीमा में उसके एजेंटों अथवा मध्यस्थों से संपर्क करने में लिया गया समय भी शामिल होना चाहिए। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां ब्राडकास्टर और उसके एजेंट/मध्यस्थ 30 दिनों से ज्यादा समय तक सिगनल उपलब्ध कराने के अनुरोध की

परवाह नहीं करते। इन मामलों में दण्ड लगाया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सिगनल उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए। अनिवार्य एक्सेस और गैर-अन्यत्रता आवश्यकता को पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एक प्लेटफार्म पर दूसरे की तुलना में अतिरिक्त लाभ होगा, जिससे बहुत से नेटवर्क पर असर पड़ेगा। (बीएनबी केबल्स)

7. जी हां। कंटेंट अनुरोध करने वाले सेवा प्रदाता के अनुरोध के निपटान के लिए 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को इस रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए—ब्राडकास्टर के एजेन्ट को अनुरोध करने के पश्चात् इसे अंतिम अनुरोध के रूप में लिया जाना चाहिए कि अनुरोध करने वाली पार्टी पर भारत में अथवा विदेश में किसी अन्य एजेंसी से संपर्क करने का दायित्व नहीं होना चाहिए; एजेन्ट को अनुरोध की पावती देनी चाहिए। एजेन्ट को ऐसे अनुरोध प्राप्त होने से एक माह के भीतर इन्टरकनेक्ट विनियम में यथा अनिवार्य गैर-भेदमूलक दरों पर कंटेंट में एक्सेस अवश्य मुहैया कराना होगा; रेगुलेटर के पास सभी इन्टरकनेक्ट दरें फाइल की जानी चाहिए, अपने एजेन्ट के माध्यम से ब्राडकास्टर को सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए, जैसे डिक्लेयर की व्यवस्था करना, या आवेदक पार्टी को रेगुलेटर के पास फाइल किए दर पर डिक्लिप्शन उपस्कर उपलब्ध कराना। यदि निर्धारित तिथि तक एजेन्ट द्वारा एक्सेस उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो रेगुलेटर को हस्तक्षेप करना चाहिए और कंटेंट की व्यवस्था के लिए अंतिम आदेश पारित कर देना चाहिए जो कि आवश्यक हो; कोई अन्य वाणिज्यिक औपचारिकता को, यदि आवश्यक हो तो, रेगुलेटर द्वारा निर्धारित किसी एजेंसी के माध्यम से पूरा कर लेना चाहिए और यदि इन कार्य में वह विफल रहता है तो डाउनलिकिंग मानदण्डों के आधार पर कार्रवाही भी की जानी चाहिए। कंटेंट के लिए अनुरोध करार की मानक शर्तों पर मानक फॉर्मेट पर किया जाना चाहिए। यदि इन मामलों पर ध्यान दिया जाए तो इससे बहुत से कानूनी मामले निपट जाएंगे और ग्राहकों की परेशानी तथा कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। चैनलों के आवश्यक प्रावधानों को तभी माना जा सकता है यदि हम मानें कि वह प्लेटफार्म जहां एक डिवाइस को एनेबल करके सब्सक्राइबर

की समस्या का डिजीटल रूप से समाधान हो सके तभी "अवश्य उपलब्ध कराया जाए" विनियम का लाभ मिल सकेगा।

केबल नेटवर्क में क्षमता की कमी की समस्या से निपटने के लिए अधिसूचना की तिथि के पश्चात् शुरू किए जाने वाले नए पे चैनलों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे डिजीटल मोड में ही हों। समय सीमा सिर्फ एक होनी चाहिए—जो कि ब्राडकास्टर के अधिसूचित एजेन्ट के लिए दी गई हो। कोई अन्य समय अथवा छूट नहीं दी जानी चाहिए। (एएससी)

8. इंटरकनेक्ट विनियम के खण्ड 3.4 के अनुसार ब्राडकास्टर/एमएसओ के किसी एजेन्ट अथवा किसी अन्य मध्यस्थ को टीवी चैनल के सिगनल उपलब्ध करने के अनुरोध को एक समुचित समय-सीमा के भीतर उत्तर देना चाहिए जो अवधि 30 दिन से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए चाहे एजेन्ट, वितरक से कुछ विवरण ही क्यों न मांगे। एजेन्ट को 30 दिनों की उक्त समयावधि के भीतर हां या नहीं का जवाब दे देना चाहिए ताकि वह अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए या तो ब्राडकास्टर के पास अथवा किसी उचित मंच से संपर्क कर सके। 30 दिनों की समग्र समय सीमा में ब्राडकास्टर द्वारा अपने एजेन्टों या मध्यस्थ से सिगनल हेतु अनुरोध के लिए संपर्क करने में लगा समय भी शामिल होगा। डीटीएच, आईपीटीवी आदि जैसे डिजीटल प्लेटफार्मों और केबल वितरण प्लेटफार्मों के बीच प्रभावी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए इंटरकनेक्ट विनियमन में गैर अनन्यता की आवश्यकता जारी रहनी चाहिए। यह आवश्यकता सभी चैनलों पर लागू होनी चाहिए चाहे उनको शुरू करने की तारीख कोई भी क्यों न हो डिजीटल प्लेटफार्मों और/अथवा डिजीटल प्लेटफार्मों की तुलना में केबल प्लेटफार्मों के बीच कोई अनन्यता नहीं होनी चाहिए। (सिटी केबल)

9. एजेन्ट/एमएसओ/ब्राडकास्टर को अनुरोध प्राप्त करने की तिथि से 30 दिनों तक की एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। इस समय सीमा में ब्राडकास्टर द्वारा अपने एजेन्टों या किसी मध्यस्थ से सिगनल हेतु अनुरोध संपर्क करने में लगने वाला समय भी

शामिल होगा। यह बलपूर्वक उल्लेख किया गया कि किसी भी स्थिति में अनन्य सामग्री की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वह एनालॉग या डिजीटल फारमेट में हो और एक एक प्रौद्योगिकी की तुलना में किसी और अन्य विशेष प्रौद्योगिकी में हो। इसकी ग्राहकों के हित और सीधे (वर्टीकल) एकाधिकार के युग में आवश्यकता है—(महानगरों में बाजार का 80% हिस्सा सीधे (वर्टीकल) एकीकृत नेटवर्कों के हाथ में है। ये आवश्यकताएं ऐसे सभी चैनलों पर लागू होंगी जो नए चैनलों को हटाए जाने पर भारत में डाउनलिक करने के इच्छुक हैं। ऐसी संभावना है कि यदि 'अवश्य उपलब्ध कराया जाए' प्रावधान से नए चैनलों को छूट मिलती है तो सामग्री को शेयर करके उपयोग करने से बचने के लिए ब्राडकास्टर अपनी लोकप्रिय सामग्री/प्रोग्रामों को नए चैनलों पर देने लगेंगे। इसके अलावा एक क्षेत्र में पंजीकृत केबल ऑपरेटरों की संख्या की किसी सीमा के बिना गैर-अनन्यता को बनाए रखना होगा। (आईएमसीएल)

10. खण्ड 3.4 और 3.6 के अंतर्गत उत्तर देने हेतु "30 दिनों से कम की समयावधि" को मौजूदा प्रणाली उचित रूप से कार्य कर रही है। इस समय सीमा में ब्राडकास्टर द्वारा टीवी चैनल के वितरक के अनुरोध को अपने एजेंट अथवा मध्यस्थ से सिगनलों के लिए किए गए अनुरोध में लगने वाला समय शामिल नहीं होना चाहिए। इन्टरकनेक्ट विनियम में आवश्यक अभिगम्यता और गैर-अनन्यता की आवश्यकता के प्रावधानों को हटाया नहीं जाना चाहिए। ऐसे किसी भी प्रयास का केबल टीवी उद्योग बड़े जोर-शोर से विरोध करेगा जिसमें डीटीएच, आईपीटीवी जैसे एक प्लेटफार्मों के लिए सामग्री सृजित हो और एनालॉग केबल/डिजीटल टीवी प्लेटफार्म खत्म होने की कगार पर आ जाए क्योंकि यह स्पष्टतः भेदभावपूर्ण और मनमाना है। इन आवश्यकताओं को सिर्फ ऐसे चैनलों पर ही लागू नहीं किया जाना चाहिए जो एक विशेष तिथि के पहले बाजार में उतरे हों। (हैथवे)

11. चूंकि ब्राडकास्टर द्वारा अपने डिकोडर के माध्यम से सिगनल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वचालित है उसे मात्र 2 घंटों के भीतर एक्टिवेट किया जा सकता है। स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए एजेंट/एमएसओ/ब्राडकास्टर को अनुरोध प्राप्त होने की

तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि उपलब्ध होनी चाहिए। 7 दिनों की समय सीमा में ब्राडकास्टर द्वारा चैनलों के वितरकों से संपर्क करने में और उसके द्वारा अपने एजेन्टों अथवा मध्यस्थ से सिगनलों के लिए अनुरोध करने में लगने वाला समय भी शामिल होना चाहिए। किसी भी स्थिति में अनन्य सामग्री की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वह एनालॉग या डिजीटल फॉरमेट हो या एक विशेष प्रौद्योगिकी की तुलना में किसी अन्य प्रौद्योगिकी पर हों। इसकी ग्राहकों के हित के लिए और सीधे (वर्टिकल) एकाधिकार के इस युग में आवश्यकता है। ऐसी आवश्यकताओं को ऐसे सभी चैनलों पर लागू किया जा सकता है जो भारत में डाउनलिक करने के इच्छुक हों। इसके अलावा एक क्षेत्र में पंजीकृत केबल ऑपरेटरों की संख्या की सीमा के बिना गैर-अनन्यता को बनाए रखना होगा। (सीओएफआई)

परामर्श के लिए मुद्दा

परिचालन का क्षेत्र

- क्या ब्राडकास्टर का सभी वितरकों को सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व केबल तब तक वैध है जब तक वाणिज्य करार में परिभाषित एमएसओ/एलसीओ परिचालन एक क्षेत्र तक प्रतिबंधित है।

प्राप्त टिप्पणियां

1. आईआरडी जारी करके हेड एण्ड पर एक्सेस उपलब्ध कराई जाती है। इंटरकनेक्ट करार के अंतर्गत करार में हेड एण्ड स्थल के पते पर आईआरडी विशेष रूप से आबंटित किया जाना चाहिए। तभी यह माना जाएगा की एक विशेष आईआरडी को एक विशेष हेड एण्ड और उसके परिचालन के क्षेत्र में आने वाली सीमा तक ही सीमित रखा गया है। (कर्नल वी. सी. खरे (सेवानिवृत्त)—केबल टीवी पर्यवेक्षक)

2. अंशदान करार के निष्पादन के बाद, निर्धारित क्षेत्र के बाहर सब्सक्राइबर्स को भुगतान करने की एमएसओ या एलएसओ की सेवा का प्रावधान (i) ब्राडकास्टर द्वारा प्राधिकृत नहीं है; (ii) एमएसओ/एलसीओ द्वारा भुगतान नहीं किया जाना है; तथा (iii) जिससे किसी अन्य एमएसओ/एलसीओ के रिट्रांसमिशन लाइसेंस में हस्तक्षेप करने की संभावना हो। कुछ एमएसओ और उनके संबद्ध एलसीओ द्वारा विनियम में "अवश्य उपलब्ध कराया जाए" के दायित्व का गलत अर्थ लगाया जा रहा है ताकि वे अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए उन्हें बेलगाम अधिकार मिल जाएं। अतः स्टार इंडिया का विचार है कि निर्धारित क्षेत्र में परिचालन के संबंध में ब्राडकास्टरों और उनके प्राधिकृत वितरकों/एजेन्टों पर "अवश्य उपलब्ध कराया जाए" दायित्व में उचित संशोधन किया जाए और लाइसेंसी और उसके संबद्धों/उप लाइसेंसियों के लिए यह बाध्यकर होगा कि वे अपने परिचालन के क्षेत्र तक अपने को सीमित रखें। ट्राई को एक नियम भी समाविष्ट करना चाहिए जो एमएसओ और एलसीओ को घोषित सब्सक्राइबर्स का ब्यौरा (नाम और पते सहित) उपलब्ध कराने को बाध्यकर बनाए। ऐसे प्रावधान के न होने के कारण एमएसओ और उनके संबद्ध एलसीओ ब्राडकास्टर के 'अवश्य उपलब्ध कराया जाए' दायित्व का दुरुपयोग कर रहे हैं। (स्टार)

3. ट्राई के 'अवश्य उपलब्ध कराया जाए' दायित्व का कुछ एमएसओ और केबल ऑपरेटरों द्वारा, चैनल आपूर्ति करार में निर्धारित भौगोलिक सीमाओं को न देखते हुए अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। यह आवश्यक हो गया है कि ट्राई यह स्पष्ट करे कि उसका ब्राडकास्टरों पर मौजूदा 'अवश्य उपलब्ध कराया जाए' दायित्व का अर्थ यह नहीं है कि वह एमएसओ और केबल ऑपरेटर को व्यावसायिक रूप से सहमति हुई निर्धारित क्षेत्र के बाहर अपनी सेवा के विस्तार की अदंडित अधिकार प्रदान करता है। (यूएसआईबीसी)

4. प्रत्येक एमएसओ/एलसीओ का वितरण का एक विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होगा, जिसके भीतर वह अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या को बढ़ाएगा। ट्राई ऐसी योजना की व्यवहार्यता की जांच कर सकती है जो एमएसओ को केबल अवसंरचना लगाने की अनुमति

देता है और फीस एकत्रित करने तथा क्षेत्र के वर्तमान परिचालन में लगे हुए मौजूदा 1-2 केबल ऑपरेटरों, जिनके पास मौजूदा नियंत्रण है को ही अवसंरचना के रखरखाव के अधिकार देता है, इस फ्रैंचाइज/लाइसेंस को कुछ फीस का भुगतान करने या गारंटी देने के बाद दिया जा सकता है। तेजी से बढ़ रही मांग की पूर्ति के लिए नए लाइसेंस देने की आवश्यकता के अलावा किसी भी नए ऑपरेटर को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इन मामलों में उन्हें ब्राडकास्टर को सूचित करना आवश्यक होगा तथा मौजूदा करारों की समीक्षा और उचित रूप में संशोधन किया जाना होगा। (एमपीए)

5. वाणिज्यिक करार में केबल ऑपरेटर के परिचालन के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निश्चित किया जाना चाहिए और ब्राडकास्टर का सभी केबल ऑपरेटरों को कंटेंट की एक्सेस उपलब्ध कराने को दायित्व तक वैध रहेगा जब तक वह केबल ऑपरेटर अपनी निर्धारित सीमा तक बने रहते हैं। अन्यथा केबल ऑपरेटर द्वारा अपने परिचालन के क्षेत्र से बाहर अनाधिकृत विस्तार करने के परिणामस्वरूप अव्यवस्था की स्थिति बन जाएगी। (ईएसपीएन)

6. करार को इस प्रकार बनाया जाए ताकि या तो उसमें परिचालन क्षेत्र पूर्व निर्धारित हो अथवा करार में एक समय आधारित बढ़ोतरी अर्थात् दिए गए क्षेत्र तथा ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती हो। डीटीएच ऑपरेटर जैसे अधिकतर एमएसओ और ऑपरेटर ऐसे वातावरण में कार्य करते हैं जहां भौगोलिक दृष्टिकोण से फैले हुए क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और ऐसे प्रावधान करार में शामिल किए जा सकते हैं। (एएससी)

7. यदि चैनल के वितरक के पास एक विशेष क्षेत्र में परिचालन हेतु वैध पंजीकरण है तो ब्राडकास्टर द्वारा कृत्रिम बाधाएं लगाकर उसे हटाया नहीं जा सकता क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ विकास में बाधा न बन सके। इस संबंध में एकमात्र मुद्दा परिचालन के विस्तारित क्षेत्र के लिए अतिरिक्त अंशदान फीस का भुगतान करना है, जिसका निपटान ब्राडकास्टर और चैनलों के वितरकों के बीच अतिरिक्त क्षेत्र के लिए "विचार-विमर्श के आधार पर स्वीकृत सब्सक्राइबर आधार" के द्वारा किया जा सकता है। चैनलों के वितरक द्वारा उस

क्षेत्र का विस्तार, जिसमें वह वैध पंजीकरण होने के नाते परिचालन के लिए प्राधिकृत है, को पाएरेसी अथवा अप्राधिकृत वितरण नहीं कहा जा सकता, और ऐसा होने पर ब्राडकास्टर 2 दिनों का नोटिस देकर अपने चैनलों को बन्द करने का पात्र नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिचालन के अतिरिक्त/विस्तारित क्षेत्र के लिए सब्सक्रिप्शन शुल्क पर बातचीत द्वारा निपटान किए जाने के लिए 30 दिनों की अवधि दी जाए, जिसके न होने की स्थिति में चैनलों के वितरक कानून के अनुसार समस्याओं के निपटारे के लिए माननीय टीडीसैट के समक्ष संपर्क करने के पात्र होंगे। (सिटी केबल)

8. आईएमसीएल का विचार है कि यदि आईएमसीएल शहर के ग्राहकों की सेवा करने का इच्छुक है तो उसे बिना किसी रुकावट के ऐसा करने की अनुमति दी जाए तथा ऐसी स्थिति में ब्राडकास्टर ऐसी शर्तें न लगा सकें जो कि एमएसओ को शहर के भीतर ही सीमित रखें। ब्राडकास्टर के लिए यह आवश्यक होगा कि वह शहर में कार्य करने वाले एमएसओ/एलसीओ की संख्या और उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए कनेक्शनों की संख्या के लिए उन्हें किए जाने वाले भुगतान के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करे और ऐसी सूचना को जनता के समक्ष सार्वजनिक करे ताकि जब कोई नया एमएसओ सेवा देना चाहे तो उसके साथ भेदभाव न हो और आज के वातावरण में प्रतिस्पर्धी एमएसओ के बीच एक पारदर्शी तरीके से कनेक्टिविटी का अंतरण हो सके। (आईएमसीएल)

9. जी नहीं। इससे प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा और अनुचित व्यवसाय व्यवहार बढ़ेगा। यह अंततः अभिदान शुल्क में संशोधन के अध्यधीन होगा जो परिचालन/बिलेबल क्षेत्र/आकार में यदि विकास होता है तो बढ़ेगा और यदि घटा होता है तो घटेगा। (हैथवे)

10. किसी भी एमएसओ/केबल ऑपरेटर, जो शहर में ग्राहकों की सेवा करने का इच्छुक है, को बिना किसी रुकावट के ऐसा करने की अनुमति होनी चाहिए और ब्राडकास्टर तब ऐसी कोई शर्तें नहीं रख सकेगा जिनसे उस शहर के क्षेत्र के भीतर ही उसे सीमित रखा जा सके।

ब्राडकास्टर को क्षेत्र में परिचालन करने वाले एमएसओ/एलसीओ की संख्या और उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए उनको किए जाने के भुगतान के संबंध में सूचना को बांटना चाहिए और ऐसी जानकारी को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि सेवा प्राप्त करने वाले नए एमएसओ के साथ वह भेदभाव न कर सकें तथा आज के वातावरण में प्रतिस्पर्धी एमएसओ के बीच एक पारदर्शी तरीके से कनेक्टिविटी का अंतरण हो सके। इससे सब्सक्राइबर्स को ब्राडकास्टरों की वेबसाइट से यह जानकारी मिल सकेगी कि एक विशेष क्षेत्र में किस एमएसओ/केबल ऑपरेटर से सिग्नल उपलब्ध हो रहे हैं। किसी क्षेत्र के सीमांकन को विनियामक/लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस के हिस्से के रूप में किया जाएगा। चूंकि अब तक कोई लाइसेंसिंग नहीं है, ब्राडकास्टर द्वारा क्षेत्र की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। यदि विभिन्न ब्राडकास्टर अलग-अलग क्षेत्रों में घुसपैठ करेंगे तो इससे असमंजस की स्थिति बन जाएगी।
(सीओएफआई)

परामर्श के मुद्दे

ब्राडकास्टर के एजेन्ट के रूप में एमएसओ

- क्या विनियम में किसी एमएसओ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्राडकास्टर के एजेन्ट के रूप में नियुक्ति करने की विशेष रूप से निषेध होनी चाहिए?

प्राप्त टिप्पणियां

1. जी हां, (कर्नल वी. सी. खरे (सेवानिवृत्त)—केबल टीवी पर्यवेक्षक)
2. सैद्धांतिक रूप से ब्राडकास्टर द्वारा प्रयोग किए गए चैनल के निर्धारण के दो कारक हैं; (i) आईआरडी उपलब्ध कराने की पूंजीगत लागत की तुलना में संभावित अभिदान शुल्क से राजस्व की वित्तीय समीक्षा; तथा (ii) स्वच्छंद सीमांत विस्तार का संभावित असर। किसी भी मामले में सेवा प्रदाता को गैर-भेदभावपूर्ण शर्तें उपलब्ध करानी होंगी और आवेदक वितरक को

दिया जाने वाला वाणिज्यिक प्रस्ताव समान होगा। इसके बाद सिगनल फीड मुहैया कराने वाले सेन्टर/मध्यस्थ कोई ऐसा एमएसओ हो सकता है, जो परिचालन के उस क्षेत्र, जहां के लिए आवेदन किया है, के भीतर प्रचालन कर रहा हो। जहां मौजूदा एमएसओ सिगनल फीड मुहैया कराने से मना कर दे वहां ब्राडकास्टर गैर-भेदभावपूर्ण शर्तों पर सीधे सिगनल दे देगा। (स्टार)

3. बाजार को उसके द्वारा स्वतः निर्धारित तरीके से चलने देना चाहिए। यदि कोई ब्राडकास्टर एक एमएसओ को एजेंट के रूप में नियुक्त करने का चयन करता है तो उसे ऐसे बाजार में अपने हित के विस्तार के लिए ही करना चाहिए। एक वितरण नेटवर्क स्थापित करने में लगने वाली बड़ी राशि को देखते हुए ऐसी संभावना है कि ब्राडकास्टर द्वारा नियुक्त एजेंट केवल उद्योग से ही होंगे। यदि एमएसओ को एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है तो इसका अर्थ होगा कि सभी केबल ऑपरेटर ब्राडकास्टर से सीधे सिगनल प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे, जो कि न तो वित्तीय दृष्टिकोण से व्यावहारिक है और न ही वाणिज्यिक आधार पर संचालने योग्य है। भारत में इस वक्त उपलब्ध 240 से ज्यादा चैनलों में से कोई भी चैनल नहीं है जिसे किसी एजेंट द्वारा एक चैनल के वितरण को सीमित करने पर 'जिसे बदला न जा सके' निर्धारित किया जा सके। (यूएसआईबीसी)

4. विनियम में यह स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट होना चाहिए कि एमएसओ को किसी ब्राडकास्टर को एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। (ईएसपीएन)

5. एमएसओ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उसे प्रतिद्वन्दी एमएसओ पर एक विकृत बढ़त मिल जाती है। (बीएनबी केबल्स)

6. एमएसओ की ब्राडकास्टर के एजेंट के रूप में नियुक्ति सैद्धांतिक तौर पर गैर-प्रतिस्पर्धी होगी। (एससी)

7. माननीय टीडीसैट ने सीटीवी के मामले में इस संबंध में पहले ही अपना निर्णय दे दिया है और इस फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक अपील लंबित है। इस संबंध में मुख्य मुद्दा है कि ब्राडकास्टर के एजेन्ट के रूप में एमएसओ के दायित्व और एमएसओ के रूप में उसके व्यवसाय, जो अधिक से अधिक केबल ऑपरेटरों को सिगनल प्रदान करना है, के बीच स्पष्टता: विरोधाभास है। ब्राडकास्टर न्यूनतम गारन्टी के आधार पर निचले स्तर पर एमएसओ की एक विशेष एजेन्ट के रूप में नियुक्ति कर रहे हैं, जिससे बहुत सी समस्याएं हो रही हैं और बाजार में असमंजस की स्थिति बन रही है। तदनुसार बहुत से केबल आपरेटरों को ब्राडकास्टर के सिगनल नहीं मिल रहे हैं क्योंकि एकाधिकार को बनाए रखने के लिए ये एमएसओ एजेन्ट एक अथवा अन्य कारण बताकर अपने प्रतिद्वन्दी केबल आपरेटरों को सिगनल उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। एमएसओ की एजेन्ट के रूप में नियुक्ति करना प्रतिस्पर्धा के लिए पूर्ण रूप से हानिकारक है और यह वास्तव में एकाधिकार को बढ़ावा दे रही है। मामलों को संदेह के दायरे से बाहर करने के लिए विनियम 3.3 में एक और परन्तुक जोड़कर इस प्रकार पढ़ा जाए, "बशर्ते कि मल्टी सिस्टम आपरेटर की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ब्राडकास्टर या उसके प्राधिकृत वितरक एजेंसी के एजेन्ट के रूप में नियुक्त नहीं की जा सकती।" (सिटी केबल)

8. चूंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय में सी टी वी की सिविल अपील में न्यायाधीन है, आई एम सी एल जिसमें मध्यस्थ है, अतः आईएमसीएल कोई स्पष्ट टिप्पणी करने का इच्छुक नहीं है बजाए इसके कि इंटरकनेक्ट विनियम को व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और ट्राई द्वारा स्टेकहोल्डरों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए। (आईएमसीएल)

9. वैसे भी एमएसओ को ब्राडकास्टर के संग्रहक के तौर पर कार्य करने का रूप दे दिया गया है। चूंकि सी नेटवर्क के संबंध में यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है, अतः हैथवे का मत है कि इस संबंध में न्यायालय के निर्णय का इन्तजार किया जाए और वे इसका पालन करेंगे। (हैथवे)

10. इन्टरकनेक्ट विनियम को व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करने और ट्राई द्वारा स्टैकहोल्डर्स के प्रश्नों का उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है। यदि वास्तविक प्रतिस्पर्धी बाजार का विकास करना है तो सेवा प्रदाता को एजेंट के रूप में नियुक्त न किया जाए।
(कोफी)

परामर्श के लिए मुद्दा

भुगतान में चूक करने वाले

- क्या विनियम में यह आवश्यक कर देना चाहिए कि सेवाओं के लिए अपने अनुरोध के साथ आवेदक वितरक को वर्तमान संबद्ध एम एस ओ से ऐसे वितरक से सिगनल फीड के माध्यम से या सीधे ब्रॉडकास्टर से सिगनल प्राप्त करने वाले एल सी ओ के संबंध में "कोई बकाया देय नहीं" का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे?

प्राप्त टिप्पणियां

1. जी हां। (कर्नल वी सी खरे (सेवानिवृत्त) – केबल टी वी उद्योग पर्यवेक्षक)
2. "अवश्य उपलब्ध कराया जाए" दायित्व से भुगतान में चूक करने वालों को नजरअंदाज करने वाले प्रावधान का इस प्रकार विस्तार किया जाना चाहिए कि उसमें ऐसे मामले शामिल हों जहां एक एमएसओ एलसीओ को सिगनल उपलब्ध कराने के लिए अपने परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने का इच्छुक हो और उसने अपने मौजूदा संबद्ध एमएसओ, या ब्रॉडकास्टर को भुगतान नहीं किया था, जहां एक एलसीओ या एलसीओ के समूह ने अपने स्वयं के हैड-एण्ड को स्थापित करने के लिए भुगतान नहीं किया था और

ब्राडकास्टर से सीधे सिगनल प्राप्त कर लिया था, और जहां टीवी चैनलों के वितरक के बोर्ड प्रमोटर किसी अन्य टीवी चैनल के भी प्रमोटर हैं, जिसने भुगतान करने में चूक की है। इसके अलावा ब्राडकास्टर के लिए परिचालनिक दृष्टिकोण से यह असंभव है कि वह यह जांच कर सके कि एक आवेदक-वितरक विनियम के अनुसार सेवा के प्रावधानों के पूर्व भी भुगतान करने में विफल रहा है। अतः स्टार इण्डिया सिफारिश करता है कि विनियम में एक प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए कि आवेदक-वितरक अपने अनुरोध के साथ ऐसे वितरक या सीधे ब्राडकास्टर से सिगनल फीड प्राप्त करने की इच्छा के संबंध में वर्तमान -संबद्ध एमएसओ से "कोई बकाया देय नहीं" का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। विनियम में यह भी प्रावधान हो कि यदि कोई एमएसओ नए एलसीओ को जो पहले किसी ब्राडकास्टर से संबद्ध था, को बिना "कोई बकाया देय नहीं" प्रमाण पत्र लिए बिना सिगनल उपलब्ध कराता है तो ब्राडकास्टर को ऐसे एक एमएसओ को वियोजित करने का अधिकार होना चाहिए। (स्टार)

3. इस विनियम का सही अर्थ निकलता है। यह साधारणतः सुनिश्चित करने में सरल है कि नियमित रूप से चूक करने वाले आपरेटरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। (यूएसआईबीसी)

4. भुगतान में चूक करने वाले सभी लोगों से कड़ाई से निपटने की आवश्यकता है, जिसके लिए विनियम में सभी आवेदकों-वितरकों के लिए ऐसे वितरकों से या ब्राडकास्टर से सीधे सिगनल फीड प्राप्त करने के इच्छुक एलसीओ के संबंध उनके वर्तमान - संबद्ध एमएसओ से "कोई बकाया देय नहीं" का प्रमाण पत्र सेवाओं के लिए उनके अनुरोध के साथ लगाना आवश्यक कर देना चाहिए। (ईएसपीएन)

5. जी हां, वितरकों के माध्यम से या सीधे ब्राडकास्टर से सिगनल फीड प्राप्त करने के इच्छुक एलसीओ के संबंध में उनके वर्तमान संबद्ध एमएसओ से "कोई बकाया देय नहीं"

प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवेदक—डिस्ट्रीब्यूबर के लिए आवश्यक कर दिया जाना चाहिए।
(बीएनबी केबल्स)

6. अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना समस्या का वास्तविक निपटान नहीं है, इससे मुकदमेबाजी को और बढ़ावा मिलेगा क्योंकि आउटगोइंग सेवा प्रदाता किसी न किसी बहाने से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में विलंब करेगा, जिससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी और अन्ततः पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ग्राहकों को सेवा प्राप्त होने से वंचित रहना पड़ेगा। यदि एनएसओ की इनपुट लागत समान रहती है तो एलसीओ का अंतिम मूल्य भी समान ही रहेगा और इस स्थिति में उपलब्ध कराई गई सेवा ही निर्धारण कारक रहेगी तथा इस स्थिति में बाजार को स्वतः निर्णय लेना चाहिए। (एएससी)

7. आवेदक—वितरक के लिए वर्तमान संबद्ध एमएसओ से प्राप्त "कोई बकाया देय नहीं" प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वास्तविक निपटान नहीं है और इससे सभी प्रकार की समस्याएं और मुकदमेबाजी बढ़ेगी क्योंकि मौजूदा एलसीओ किसी संबद्ध एलसीओ को खोना नहीं चाहेगा। अतः ऐसी संभावना है कि वह एलसीओ के स्थानांतरण से बचने के लिए झूठी और नकली बकाया मांग रखे। ऐसे परिदृश्य में एलसीओ से "कोई बकाया देय नहीं" प्रमाण-पत्र न होने की स्थिति में अन्य एमएसओ/एलसीओ को फीड उपलब्ध कराने में असमर्थ रहेगा, जिससे एलसीओ को मौजूदा एमएसओ के साथ ही बने रहने को बल मिलेगा। ऐसा विनियम उद्योग की प्रगति के लिए घातक होगा और इससे वस्तुतः एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा। (सिटी केबल)

8. कोई बकाया देय नहीं प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता से समस्या खड़ी हो जाएगी क्योंकि पार्टियों के बीच वास्तविक विवाद भी हो सकते हैं और स्थानांतरण करने वाला आवेदक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और प्रस्तुत करने में असफल रह सकता है, जिससे दूसरों के साथ व्यवसाय करने का उसका अधिकार प्रभावित हो सकता है। (आईएमवीएस)

9. प्राधिकरण के लिए इन्टरकनेक्ट विनियम में प्रस्तावित संशोधन करना एक स्वागत योग्य कदम होगा। इस गतिशील और व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस प्रणाली की सभी खामियों का निवारण हो जाएगा। (हैथवे)

10. कोई बकाया देय नहीं की अनिवार्यता से समस्या खड़ी हो जाएगी क्योंकि पार्टियों के बीच वास्तविक विवाद भी हो सकते हैं और स्थानांतरण करने वाला आवेदक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और प्रस्तुत करने में असफल रह सकता है और इससे अन्यो के साथ व्यवसाय करने का उसका अधिकार प्रभारित हो सकता है। (कोफी)

परामर्श के लिए मुद्दा

मौजूदा विनियम का विस्तार

सब्सक्राइबर आधार

- क्या सबस्क्रिप्शन करार की वैधता अवधि के दौरान सब्सक्राइबर आधार निश्चित रहना चाहिए ?
- यदि नहीं, तो सब्सक्राइबर आधार के आवधिक संशोधन के लिए क्या कार्य-पद्धति होगी?
- क्या करार पर हस्ताक्षर करते समय ब्राडकास्टर एमएसओ को एलसीओ (सब्सक्राइबर आधार/एकमुश्त भुगतान सहित)/हाउसहोल्ड की सूची उपलब्ध कराना अनिवार्य कर देना चाहिए?
- नए सदस्यों के लिए सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण कैसे किया जाएगा ?

प्राप्त टिप्पणियाँ

1. सब्सक्रिप्शन करार की वैधता अवधि के दौरान सब्सक्राइबर आधार निश्चित रहना चाहिए जब तक की उचित कारणों और औचित्य सहित करार संशोधन करने के प्रावधान मौजूद न हों । सब्सक्राइबर आधार को आवधिक सुधार के लिए एलसीओ सहित ब्राडकास्टर एजेंट द्वारा एलसीओ के क्षेत्र में प्रत्येक घर की गणना के आधार पर सत्यापन नहीं किया जाना चाहिए। आदर्शतः, करार पर हस्ताक्षर करते समय ब्राडकास्टर/एमएसओ को एलसीओ (सब्सक्राइबर आधार/एकमुश्त भुगतान सहित)/हाउसहोल्ड की सूची उपलब्ध कराना अनिवार्य कर देना चाहिए । नए सदस्यों के सब्सक्राइबर आधार का निर्धारण कैसे के कार्यान्वयन को बढ़ावा देकर, एक प्रौद्योगिक अनिवार्यता के रूप में आसान शर्तों पर एसटीबी खरीदने की व्यवस्था करके, जैसे कि टीवी के ऊपर आईपी और डीटीएच, और एसएमएस (सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में) एफटीए सामग्री को शून्य मूल्य देकर किया जाए। (कर्नल वी सी खरे (सेवानिवृत्त) - केबल टीवी उद्योग पर्यवेक्षक)
- 2. करार जारी रहने की स्थिति के दौरान सब्सक्राइबर आधार में बदलाव आ सकता है और तदनुसार सब्सक्रिप्शन फीस में संशोधन किया जाना चाहिए। एलसीओ के बदलने के कारण पेड सब्सक्राइबर आधार में कोई वृद्धि या कमी सिर्फ तभी की जा सकती है जब सब्सक्रिप्शन करार के हिस्से के रूप में संबद्ध एलसीओ द्वारा पेड सब्सक्राइबरों का एमएसओ द्वारा ब्रेक-अप देना अनिवार्य हो। चूंकि एमएसओ अपने संबद्ध एलसीओ और उनके पेड सब्सक्राइबर आधार की सूची उपलब्ध नहीं कराता, ब्राडकास्टर पेड सब्सक्राइबर आधार में किसी कमी का विरोध करने में अधिक रूढ़ीवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। विनियम में यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि एलसीओ/एमएसओ को अपने घोषित सब्सक्राइबरों (नाम और पते सहित) का विवरण एमएसओ को उपलब्ध कराएगा और एमएसओ ऐसी सूची को ब्राडकास्टर को उपलब्ध कराएगा। इससे एलसीओ बदलने की स्थिति में एमएसओ की सब्सक्रिप्शन फीस को बढ़ाने/घटाने में ब्राडकास्टर को सुविधा मिलेगी। यदि ब्राडकास्टर और एमएसओ/केबल आपरेटर के बीच सब्सक्राइबर की संख्या के बारे में

विवाद का कोई मामला हो तो ट्राई आगे आ सकता है और तात्कालिक आधार पर इस मामले को निपटने के लिए कोई कार्यविधि अपना सकता है। स्टार इण्डिया का सुझाव है कि ट्राई स्वतंत्र प्रतिष्ठित तृतीय पार्टी एजेंसी (जैसे एसी नीलसन) नियुक्त करें जो कि सब्सक्राइबर संबंधित मामलों से निपटे (विवाद की स्थिति में सर्वेक्षण करके)। विवाद की किसी स्थिति में, एमएसओ/केबल आपरेटर तृतीय पार्टी एजेंसी को अपने संबद्ध केबल आपरेटर और उनके संबंधित कनेक्ट सब्सक्राइबरों (उनके पूर्ण संपर्क ब्यौरे सहित) की सही और ठीक सूची उपलब्ध कराएगा। उसके बाद एक विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर स्वतंत्र प्रसिद्ध तृतीय पार्टी एजेंसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगी। दोनों पार्टियों के लिए सर्वेक्षण की रिपोर्ट अंतिम और बाध्यकारी होगी। हारने वाली पार्टी द्वारा सर्वेक्षण की लागत वहन करनी होगी। नए प्रवेशकों के मामले में निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र या एलसीओ की सूची जिसे करार की अवधि के दौरान एसएसओ कनेक्ट करनी का प्रस्ताव रखता है, के अनुसार उनके परिचालन के क्षेत्र को परिभाषित किया जाएगा। तदनुसार, निर्धारित क्षेत्र के आधार पर या परिचालन क्षेत्र के भीतर संबद्ध एलसीओ के वर्तमान सब्सक्रिप्शन राजस्व के आधार पर ब्राडकास्टर भेदभाव रहित प्रस्ताव दे सकता है। स्टार इण्डिया का मत है कि चूंकि नए प्रवेशकों की संख्या ज्यादा नहीं होती, नए प्रवेशकों के लिए विशेष रूप से किसी विनियम की आवश्यकता नहीं है। (स्टार)

3. सब्सक्राइबर आधार निर्धारित नहीं होने चाहिए। भारतीय केबल टेलीविजन सब्सक्राइबर आधार तीव्र दर से वृद्धि कर रहा है, लेकिन अभी भी पूरा क्षेत्र इस समय केबल टेलीविजन द्वारा सेवित नहीं है। मौजूदा सब्सक्रिप्शन करार के दौरान सब्सक्राइबर आधार को फ्रीज करना न तो आवश्यक है और न ही न्यायसंगत। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अथवा ट्राई को शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि सेवा प्रदाताओं द्वारा सब्सक्राइबर आधार मुहैया कराने के लिए उन पर दबाव बनाया जा सके। मंत्रालय अथवा ट्राई द्वारा प्रत्येक वर्ष कुछ दर्जन सेवा प्रदाताओं के "स्नैप लेखा-परीक्षा" को शुरू करने के लिए विशेष सैल का गठन करने पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि रिपोर्टिंग नियमों की समीक्षा का अनुपालन हो सके और बाजार में मौजूद अंडर-रिपोर्टिंग की राशि से संबंधित स्पष्ट तस्वीर प्राप्त हो सके।

सब्सक्राइबर संख्या की अंडर-रिपोर्टिंग कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और बाजार की कीमत को विकृत करता है। एलसीओ (सब्सक्राइबर आधार/एकमुश्त भुगतान सहित)/ब्राडकास्टर्स के लिए हाउसहोल्डर्स/एमएसओ की सूची मुहैया कराने के लिए करार पर हस्ताक्षर करते समय विनियम बनाना सही है। किसी उद्योग, केबल वितरण में विनियम में एक महत्वपूर्ण अध्याय को जोड़ने के लिए यह एक अत्यंत साधारण तरीका है जिसे आसानी से विनियमित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वितरकों और एमएसओ दोनों को सब्सक्राइबरों की संख्या जिसकी सेवा मुहैया करा रहे हैं, के संबंध में सही गणना मुहैया कराने के लिए बाध्य करना चाहिए। इसका निर्धारण आपरेटर के केबल अफिलिएटों और सब्सक्राइबरों की पूरी सूची के प्रावधान सहित उस क्षेत्र विशेष के आपरेटरों के परिचालन में आने वाली जनसंख्या से अनुमान लगाकर नए सदस्य के उत्पाद की प्रस्तावना और अपील (यूएसआईबीसी) की विधिवत अनुमति सहित उस क्षेत्र के केबल के प्रभाव का सर्वेक्षण होना चाहिए। (यूएसआईबीसी)

4. नए ग्राहकों के परिदृश्य में चल रही प्रक्रियाओं के आधार पर एमएसओ/एलसीओ को समर्थ होना चाहिए। इसी प्रकार ग्राहकों को एमएसओ/एलसीओ के विन्यास से चयन करने में समर्थ होना चाहिए। एमएसओ द्वारा तिमाही आधार पर ब्राडकास्टर्स को अपने सब्सक्राइबरों की एक सूची मुहैया करानी चाहिए। यह सूची हाउसहोल्ड पतों, सब्सक्राइबरों के नाम और संपर्क करने से संबंधित विवरणों सहित भौगोलिक वर्गीकरण के रूप में होनी चाहिए। यह सूची ब्राडकास्टर्स को यदि वे चाहते हैं तो सेवा गुणवत्ता की स्पाॅट जांच की अनुमति प्रदान करेगी। डाटा माईनिंग का यह स्तर सभी पार्टियों—ब्राडकास्टर्स, एमएसओ और एलसीओ को विशेष प्रोत्साहक प्रस्तावों के अभिकल्प तैयार करने में सहायता भी प्रदान करेगा। सूचियों में जोड़े गए नए सब्सक्राइबरों और सूची में से हटाए गए सब्सक्राइबरों का ब्यौरा तिमाही आधार पर दर्शाया जाए। मासिक आधार पर करार के हस्ताक्षर के समय अपने सब्सक्राइबर आधार सहित एलसीओ की सूची ब्राडकास्टर्स/एमएसओ को मुहैया कराना अनिवार्य कर देना चाहिए। इसे भुगतान दायित्व के संदर्भ में लगभग 50-60% की न्यूनतम गारंटी देनी चाहिए। नए प्रवेशकों के लिए

सब्सक्राइबर आधार उस क्षेत्र में केबल सेवाओं के प्रभाव के मौजूदा स्तर पर निर्धारित किया जाए। (एमपीए)

5. सब्सक्राइबर आधार का करार में उल्लेख किया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी/गिरावट को इस प्रकार से निपटाया जाना चाहिए जैसे (क) सभी एमएसओ/केबल ऑपरेटर्स के लिए अपने सब्सक्राइबर बेस की सूची मासिक आधार पर ब्राडकास्टर को उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए; (ख) एलसीओ के लिए भी इसी प्रकार की सूची फाइल की जानी चाहिए। (ग) यइ डाटा ट्राई के वेबसाइट पर भी उपलब्ध होने चाहिए ताकि पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके। नए चैनलों/इन्टैटों के मामले में सब्सक्राइबर आधार करार करने वाली दो पार्टियों (ईएसपीएन) के बीच बातचीत से संबंधित होना चाहिए। (ईएसपीएन)

6. सब्सक्राइबर आधार सब्सक्रिप्शन करार की वैधता के निबंधन के दौरान पुनः निर्धारित होनी चाहिए क्योंकि ब्राडकास्टरों द्वारा विशेष रूप से किसी बड़े आयोजन से पूर्व अपने सब्सक्राइबरों की संख्या को बढ़ाने के लिए भांति-भांति के अनुचित तरीके अपनाए जाते हैं। करार के हस्ताक्षर के समय सब्सक्राइबरों की सूची की व्यवस्था का दायित्व अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइबर आधार की न्यूनतम राशि सही रूप से निर्धारित होने चाहिए ताकि इससे भी संबद्ध पक्ष आहत न पहुंचे। (बीएनबीकेबल्स)

7. गैर एड्रेसिवल माहौल के मामले में करार की अवधि के दौरान सब्सक्राइबर आधार हमेशा निश्चित होना चाहिए और एड्रेसिवल माहौल के मामलों में यह सब्सक्राइबरों की वास्तविक संख्या पर आधारित होने चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि कीमत फ्रीज की अवधि के दौरान नेटवर्क से कुल बहिर्गमन को भी फ्रीज कर देना चाहिए। गैर एड्रेसिवल माहौल के मामले में आवधिक संशोधन उस क्षेत्र में हाऊसहोल्डों की संख्या में वृद्धि होने पर किसी प्रकार के नए निर्माण के आधार पर किए जा सकते हैं। करार पर हस्ताक्षर करने के समय सब्सक्राइबर आधार सहित एलसीओ सूची उपलब्ध होना कठिन है, बहरहाल, यह अनिवार्य

किया जा सकता है कि करार पर हस्ताक्षर करने के तीन महीने के भीतर प्रणाली से संबद्ध एलसीओ के नाम सहित सूची उपलब्ध कराई जा सकती है। नए इन्ट्रेंट के सब्सक्राइबर आधार को सेवा प्रदाता द्वारा न्यूनतम एंट्री स्तर के रूप में निश्चित किया जा सकता है। (एएससी)

8. ट्राई ने पूर्ववर्ती परामर्श नोट और दस्तावेजों में विधिवत रूप से यह मान्यता दी है कि गैर कैस क्षेत्र में इंटरकनेक्ट करार "नेगोशिएटिड सब्सक्राइबर बेस" के आधार पर होते हैं। चूंकि नेगोशिएटिड सब्सक्राइबर संख्या वितरण अंतर की देखभाल करता है और सब्सक्राइबरों के लिए समाविष्ट आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराता है, इसलिए सब्सक्रिप्शन करार की वैधता की अवधि से पहले इसे निश्चित किया जाना चाहिए। चूंकि नेगोशिएटिड सब्सक्राइबर आधार के आधार पर ब्राडकास्टर और टीवी चैनलों के वितरकों के बीच समझौते हो गया है, इसलिए एलसीओ आदि की सूची उपलब्ध कराना प्रासंगिक और जरूरी नहीं है क्योंकि ब्राडकास्टरों द्वारा इस सूची का गलत उपयोग किया जा सकता है और ब्राडकास्टरों द्वारा यह आरोप लगाते हुए करार के हस्ताक्षर के समय सूची में सब्सक्राइबर आधार के बारे में जो उल्लेख किया गया है उसकी अपेक्षा उक्त सूची में एलसीओ के आंकड़े काफी अधिक हैं और इसके लिए अधिक शुल्क की मांग करके टीवी चैनलों के वितरकों को परेशान किया जा सकता है। इसके विकल्प के रूप में जब गैर कैस क्षेत्रों के लिए ब्राडकास्टरों के साथ इंटरकनेक्ट करार होता है तब चैनलों के वितरकों (एलसीओ से एमएसओ) द्वारा सब्सक्राइबरों के विशेष नम्बर के संबंध में की गई घोषणा के आधार पर अंततः निगोसिएटेड नम्बर का रूप देना चाहिए। इस प्रकार एमएसओ से जुड़ने वाले नए एलसीओ के आधार पर घोषित किए गए सब्सक्राइबर आधार में यदि किसी प्रकार की वृद्धि हो या तो उस क्षेत्र में या नए क्षेत्र में होती है अथवा एमएसओ अपने परिचालन का विस्तार करता है तो इन सभी को सब्सक्राइबर आधार में शामिल किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जब एलसीओ एमएसओ को छोड़ देता है तब घोषित सब्सक्राइबर आधार तदनुसार कम कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, जब कभी प्रवसन की प्रक्रिया होता है तब घोषित किए गए सब्सक्राइबर आधार में किसी प्रकार की वृद्धि होने अथवा घोषित किए

एए सब्सक्राइबर आधार में किसी प्रकार की कमी होने दोनों की स्थिति में उक्त के संबंध में उचित समाधान करने चाहिए और घोषित किए गए सब्सक्राइबर आधार को अपवार्ड और डाऊनवार्ड दोनों रूप में संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि इस मामले को आवधिक अंतराल पर समाशोधन प्रक्रिया के जरिए निपटाया जा सकता है और तदनुसार समायोजन किया जा सकता है। नए प्रवेशकों के लिए एक मात्र प्रणाली यह है कि किसी विशेष अवधि के लिए पे ब्राडकास्टर्स के साथ निगोसिएटेड सेटलमेंट किए जाएं जिससे ग्राउण्ड स्तर पर चैनलों के वितरक के वास्तविक निष्पादन के आधार पर उक्त अवधि की समाप्ति पर उसकी समीक्षा की जा सके। (सीटी केबल)

9. ब्राडकास्टर्स को संबंधित घोषणा-पत्र की सूची सहित एलसीओ की सूचियां उपलब्ध कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एमएसओ जैसे आईएमसीएल वास्तविक सब्सक्राइबर आधार एलसीओ का ब्यौरा मुहैया नहीं कराने का मुख्य कारण यह है कि एमएसओ के साथ एलसीओ भी अपने काल्पनिक सब्सक्राइबर आधार के आधार पर निगोसिएट करता है और मासिक सब्सक्रिप्शन शुल्क का पूर्व निर्धारित कीमत का भुगतान करता है। वास्तव में कोई भी एमएसओ इसकी सच्चाई और एलसीओ के प्रामाणिक सब्सक्राइबर आधार से अवगत नहीं है। दूसरी ओर यदि कतिपय सब्सक्राइबर आधार को विनियम की व्यवस्था में महत्वपूर्ण और आवश्यक समझा गया था तो एड्रेसिबिलिटी के न होने पर एलसीओ द्वारा सेवा कर/मनोरंजन कर की घोषणा अथवा स्वतः घोषणा करके इस प्रकार का उपयोग ही एक मात्र व्यवहार्य प्रक्रिया है (जैसाकि आईएमसीएल द्वारा अपेक्षित हो और जब तक यह प्रतिकूल न हो अन्यथा एक मामले से दूसरे मामले के आधार पर) नए प्रवेशक के लिए सब्सक्राइबर आधार एमएसओ के लिए न्यूनतम 300 कनेक्शन और एलसीओ के लिए न्यूनतम 50 कनेक्शन होने चाहिए। (आईएमसीएल)

10. किसी भी व्यवसाय की गतिशीलता हमेशा स्थिर नहीं होती है। बहरहाल, करार की अवधि के दौरान स्थामित्व और औचित्य को बनाए रखने के लिए इस पर सहमति हुई है कि निगोसिएटेड सब्सक्राइबर आधार को स्थिर और फिक्सड बनाए रखने के लिए अनुमति

देनी चाहिए। यदि इसे मासिक आधार पर अथवा अल्प समय/अवधि के आधार पर अस्थिर बनाए रखने के लिए अनुमति दी जाती है तो इसके परिणामस्वरूप अधिक विरोध और मतभेद पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा, निगोसिएटेड सब्सक्राइबर आधार किसी विशेष चैनल अथवा चैनलों के समूह अथवा चैनलों के समूह/मांग के अनुसार एक या दो चैनलों सहित गैर मूविंग चैनलों के अंतर्गत एक चैनल की मांग को क्रियांकित करना है। कैसे इसका एकमात्र हल है। किसी भी मामले में प्राधिकरण यदि कोई विचार प्रकट करता है जो मौजूदा परामर्श दस्तावेज आधारित और इसके तहत विचाराधीन होता है तब किराए के बिल के आधार के साथ-साथ डीलरों जैसे एमएसओ/एलसीओ के लिए वितरण अन्तर से संबंधित उठाए गए मुद्दों के लिए इसमें बिना किसी विलंब के एड्रेस्ड की आवश्यकता पड़ती है। मौजूदा परामर्श पेपर के माध्यम से विवादों को कम करने का प्राधिकरण का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा यदि इसमें आवधिक आशोधन किया जाता है। यदि निगोसिएटेड सब्सक्राइबर आधार जैसाकि 1 अक्टूबर, 2004 को ट्राई भी सिफारिशों में मान्यता दी गई है) होता है तो एलसीओ और हाऊसहोल्डों से संबंधित सब्सक्राइबरों की सूची मुहैया कराने का कोई औचित्य नहीं हो। इसके अलावा, एमएसओ अपने बैल्यूमो से केवल निगोसिएटेड शुल्क का एकमुश्त प्राप्त करेगा जैसाकि पे ब्राडकास्टर एमएसओ से प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, यह स्थिति हो गई है कि एमएसओ निगोसिएटेड सब्सक्राइबरों के लिए लोकप्रिय पे ब्राडकास्टरों से भुगतान करने वाले/सब्सक्राइबरों/एलसीओ घोषणा से प्राप्त धनराशि की अपेक्षा अधिक सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान कर रहा है। नए प्रवेशकों के लिए सब्सक्राइबर आधार को निगोसिएटेड और/अथवा सहमत सब्सक्राइबर के आधार पर निर्धारित किया जाए। (हैथवे)

11. सब्सक्राइबर करार की वैधता अवधि के दौरान सब्सक्राइबर आधार को निश्चित रहनी चाहिए जोकि एक वर्ष है। सब्सक्राइबर आधार में प्रत्येक वर्ष करार के नवीकरण के समय अथवा करार के एक वर्ष पूरा होने के बाद संशोधन किया जाना चाहिए। ब्राडकास्टरों को संबंधित घोषणा-पत्र की सूची सहित एलसीओ की सूचियां उपलब्ध कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एमएसओ द्वारा एलसीओ के सब्सक्राइबरों की संख्या का विवरण

उपलब्ध कराने का मुख्य कारण है कि वह एमएसओ के साथ एलसीओ भी अपने काल्पनिक सब्सक्राइबर आधार के आधार पर निगोसिएट करता है और मासिक सब्सक्रिप्शन शुल्क की पूर्व निर्धारित कीमत का भुगतान करता है। वास्तव में कोई भी एमएसओ/एलसीओ के सच्चे और प्रामाणिक सब्सक्राइबर आधार से अवगत नहीं है। दूसरी ओर यदि कतिपय सब्सक्राइबर आधार को विनियम की व्यवस्था में महत्वपूर्ण और आवश्यक समझा गया था तो एड्रेसिबिलिटी के न होने पर एलसीओ द्वारा सेवा कर/मनोरंजन कर की घोषणा अथवा स्वयं घोषणा करके इस प्रकार का उपयोग ही एक मात्र व्यवहारिक प्रक्रिया है। नए प्रवेशक के लिए सब्सक्राइबर आधार एमएसओ के लिए न्यूनतम 300 कनेक्शन और एलसीओ के लिए न्यूनतम 50 कनेक्शन होने चाहिए। ब्राडकास्टर्स की ग्रामीण योजना के तहत सब्सक्राइबरों को 300 की न्यूनतम संख्या और शहरी बाजार में 500 के आधार पर बॉक्स देने की परिपाटी रही है जिसकी अनुमति दी जा सकती है। (कोफी)

परामर्श के लिए मुद्दे

मल्टी सिस्टम अपারেटर

- क्या केबल आपरेटर जिसे मल्टी सिस्टम आपरेटर के रूप में परिभाषित किया गया है के लिए सब्सक्राइबरों की संख्या का किसी न्यूनतम संख्या और अन्य मापदंड का उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि वह ब्राडकास्टर्स से सीधे सिगनल प्राप्त करने का पात्र हो जाए?

प्राप्त टिप्पणियां

1. जी नहीं। (कर्नल वी सी खरे (सेवानिवृत्त)—केबल टीवी उद्योग पर्यवेक्षक)
2. एक एमएसओ के अंतर्गत सब्सक्राइबरों की संख्या विभिन्न कारणों (आकार, भौगोलिक स्थिति आदि सहित) पर निर्भर होती है। अतः सब्सक्राइबरों की संख्या के आधार पर एमएसओ को परिभाषित करना काफी कठिन है। अतः ब्राडकास्टर्स द्वारा भेदभाव रहित आधार पर एमएसओ को परिभाषित करने की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। (स्टार)

3. सभी वितरकों और एमएसओ (सब्सक्राइबर की संख्या, तकनीकी मापदंडों, वित्तीय आवश्यकताओं) के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में एकरूपता होनी चाहिए, लेकिन इसके आगे पूरी तरह वाणिज्यिक निर्णय होना चाहिए कि क्या वे अपने सिगनलों को सीधे मुहैया कराना चाहते हैं। (यूएसआईबीसी)

4. जैसाकि अधिनियम में उल्लेख किया गया है "एमएसओ" को सब्सक्राइबरों की संख्या के न्यूनतम के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए और केबल आपरेटर के लिए अन्य मापदंडों को "मल्टी सिस्टम आपरेटर" के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि ब्राडकास्टरों से सीधे सिगनल प्राप्त करने के पात्र हो जाए। (ईएसपीएस)

5. सब्सक्राइबरों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे इस सेक्टर में नए प्रवेशकों के आगमन ब्लॉक हो जाएंगे और मौजूदा केबल ऑपरेटर जो एमएसओ बनने की आकांक्ष रखते हैं, की उम्मीदों पर भी पानी फिर जाएगा। अतः इससे मौजूदा एमएसओ और शक्तिशाली तथा प्रभावी बन जाएंगे, जिससे एकाधिकार बाजार का सृजन होगा और ग्राहक इससे आहत होंगे। (बीएनबी केबल्स)

6. भारत की विस्तृत डेमोग्राफी के कारण के कारण एमएसओ के रूप में परिभाषित किए जाने वाले केबल आपरेटर की संख्या का विशेष रूप से उल्लेख करना कठिन है। मौजूदा समय में परिभाषा की आवश्यकता पूरी तरह सैद्धांतिक है क्योंकि वर्तमान एमएसओ बड़ी सीमा तक हेड एण्ड रीच पर आधारित होकर करार करते हैं और उसके बाद उसे एक करार में समेकित करते हैं। इसको ब्राडकास्टर के ऊपर छोड़ा जा सकता है। (एससी)

7. एमएसओ का सही तकनीकी परिभाषा है कोई कंपनी/संगठन है जो विभिन्न क्षेत्रों अथवा पूरे राज्य अथवा देश में मल्टीपल हेडेन्डों पर परिचालित है। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में स्वतंत्र केबल आपरेटर भी हैं जो सिंगल हेड एण्ड (कंट्रोल रूम) के रूप में परिचालित हैं और सब्सक्राइबरों को सीधे सेवा मुहैया कराने के साथ-साथ अन्य एलसीओ जिसका कार्य ग्राहकों को सिगनल मुहैया कराना होता है को सिगनल फीड भी उपलब्ध कराते हैं। ब्राडकास्टरों से सीधे सिगनल प्राप्त करने के लिए योग्य अथवा पात्रता प्राप्त

करने के लिए एमएसओ/स्वतंत्र एलसीओ को 3000 कनेक्शनों के न्यूनतम समग्र सब्सक्राइबर आधार समूह सहित कम से कम 25 केबल आपरेटरों को अपने नेटवर्क से जोड़ना चाहिए। (सिटी केबल)

8. ब्राडक्रास्टर्स, एमएसओ से शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 500 कनेक्शनों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 300 कनेक्शनों के लिए मांगता है। चूंकि इनके द्वारा इस आदर्श को व्यवसाय में अपना लिया गया है इसलिए इसे जारी रहने दिया जाए। (आईएमसीएल)

9. अन्तरसंयोजन विनियम में प्रस्तावित संशोधन प्राधिकरण के लिए स्वागत योग्य कदम है यहां तक कि एक व्यक्ति/एलसीओ, एमएसओ के रूप में दावा प्रस्तुत करता है और मौजूदा प्रणाली को अव्यवस्थित करने की कोशिश करता है। एमएसओ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और यह एक जटिल व्यवसाय है क्योंकि यह सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। अतः प्रस्ताव है कि एमएसओ के रूप में पात्रता के लिए न्यूनतम 50 एलसीओ और कम से कम 5,000 सब्सक्राइबर आधार होना चाहिए (हैथवे)

10. ब्राडक्रास्टर्स, एमएसओ के लिए शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 500 कनेक्शनों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 300 कनेक्शनों की मांग करते हैं। चूंकि इनके द्वारा इस आदर्श को व्यवसाय में अपना लिया गया है इसलिए इसे जारी करने की अनुमति दी जाए। (कोफी)

परामर्श के लिए मुद्दे

करारों का नवीकरण

- क्या मौजूदा ठेका की समाप्ति से पूर्व करारों के नवीकरण के लिए किसी प्रकार की समय-सीमा निर्धारित की गई है ताकि यदि करार का नवीकरण नहीं किया जा सका तो मौजूदा संविदा की समाप्ति के बाद उन चैनलों को बंद करने के संबंध में सब्सक्राइबरों को अग्रिम नोटिस के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके।
- किसी ठेके की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद समझौते के दौरान ठेका को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए?

प्राप्त टिप्पणियाँ

1. जी हां। यह चैनलों को बंद करने के लिए जारी किए गए नोटिस की अवधि से लगभग 4 सप्ताह अधिक होना चाहिए। किसी ठेके की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद समझौते के दौरान संविदा को आगे बढ़ाने की स्थिति केवल तब उत्पन्न हो सकती है जब सेवा को यहां तक की करार की वैधता अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी बाधित नहीं किया गया हो। सेवा को जारी रखने और पिछले करार की समाप्ति की तारीख से पूर्व प्रभावित नए निगोसिएटेड दरों के लेवी के लिए तर्क रहना चाहिए। जब कभी सेवा बाधित होती है तब सेवा की बहाली की तारीख से नई दरों को लागू किया जाना चाहिए (कर्मल वी सी खरे (सेवानिवृत्त)—केबल टी वी उद्योग पर्यवेक्षक)

2. एमएसओ/केबल ऑपरेटरों, जो अपने करार के नवीकरण करना चाहते हैं, को उनकी मौजूदा करार की अवधि की समाप्ति से कम से कम दो महीने पहले लिखित अनुरोध भेजा जाना चाहिए। लिखित अनुरोध के साथ एमएसओ/केबल ऑपरेटर द्वारा (i) डाकघर लाइसेंस (ii) प्राधिकृत व्यक्ति के फोटोग्राफ (iii) पते का प्रमाण (iv) फोटो पहचान-पत्र (v) चार्टर दस्तावेज (vi) प्राधिकरण का पत्र (vii) कोई बकाया नहीं से संबंधित प्रमाण पत्र और (viii) ऐसे दस्तावेजों जोकि ब्राडकास्टरों द्वारा मांगी जा सकती है, से संबंधित विभिन्न सूचना/दस्तावेज भिजवाए जाने चाहिए। एक नए संविदा के निष्पादन के बिना संविदा को बढ़ाने के प्रयास को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि उनकी सेवा को अनुमति दी जाती है तो यह ब्राडकास्टर द्वारा अप्राधिकृत एमएसओ/केबल ऑपरेटर हेतु सिगनल की वैधता पर असर डालेगी। (स्टार)

3. जी नहीं, ट्राई द्वारा मौजूदा करारों के नवीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। यह एक व्यवसाय दर व्यवसाय प्रक्रिया है और इसे विनियमित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, करारों के नवीकरण की समय-सीमा निर्धारित करना प्रवर्तन के उपग्रहों को शुरू करके अपरिहार्य रूप से आवश्यक होंगे। इस प्रकार के उपाय को नवीकरण प्रक्रियाओं के स्टॉलिंग के माध्यम से एक पार्टी अथवा अन्य के द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। संविदा की समाप्ति के बाद समझौते के दौरान

संविदा को बढ़ाने के लिए या तो मूल संविदा के रूप से अथवा तदर्थ आधार पर व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा विनियम, जो विशेष शर्तों की लागू करने के है, लाभदायी नहीं होगा और इसलिए विनियम लिखित रूप में इस प्रकार होना चाहिए ताकि उसमें अवधि को अनिवार्य रूप के बढ़ाने के उपबंध हो। संविदा की समाप्ति के बाद ऐसा विनियम अपरिहार्य रूप में एक पक्ष अथवा अन्य के पक्षधर होगा। (यूएसआईबीसी)

4. मौजूदा ठेकों की अवधि की समाप्ति से पूर्व करार का नवीकरण के लिए अधिनियम/नियमों में निश्चित समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए ताकि यदि करार का नवीकरण नहीं किया जा सकता तो मौजूदा करार की समाप्ति के बाद उन चैनलों के काटे जाने के संबंध में सब्सक्राइबर्स को पर्याप्त अग्रिम सूचना मिलनी चाहिए। मौजूदा ठेका की समाप्ति के बाद बातचीत के लिए तीन महीने का समय दिया जाना चाहिए और इस अवधि के दौरान आपरेटर (एमएसओ/एलसीओ) द्वारा जब तक ठेका का नवीकरण नहीं हो जाता है अथवा सेवाओं को बंद नहीं कर दिया जाता है अंतिम सहमत सब्सक्राइबर आधार पर उन अवधि जिसके तहत वे ब्राडकास्टर से सेवाएं प्राप्त किया हो, के लिए चैनलों के उस समय के मौजूदा दर पर भुगतान किया जाना चाहिए। (ईएमपीएन)

5. जी हां, पुराने ठेका की समाप्ति के पहले के करारों का नवीकरण के लिए निश्चित समय-सीमा का निर्धारण होना चाहिए ताकि सब्सक्राइबर परेशान न हो और वे किसी चैनल को जारी रखने के मामले में पर्याप्त अग्रिम सूचना प्राप्त कर सकें। (बीएनबी केबल)

6. करार का नवीकरण पिछले करार की समाप्ति से कम से कम एक महीने पहले किया जाना चाहिए। यदि पिछले करार की वैधता अवधि के भीतर करार को बंद नहीं किया जाता है और उस क्षेत्र में परिवार के किसी नए निकाय नहीं होता तब तक पिछले करार को वैध माना जाना चाहिए और अगले तीस दिन में उसे बंद नहीं किया जाता है तब विनियामक को आदेश जारी कर देना चाहिए जोकि अगले तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर आधारित हो और इस अंतरिम अवधि में ब्राडकास्टर अथवा इसके वितरक सेवाओं को बंद करने के लिए किसी प्रकार के कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। (एससी)

7. आदर्शतः करार 3 वर्षों की अवधि के लिए होने चाहिए और वाणिज्यिक शर्तों के संबंध में 12 महीनों की अवधि की समाप्ति के बाद पुनः विचार किया जा सकता है। वाणिज्यिक शर्तों के निपटारे के लिए 12 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले और कम से कम 30 दिन पहले बातचीत शुरू कर देनी चाहिए और उक्त 12 महीनों की अवधि की समाप्ति के पहले उसका निपटारा करने के प्रयास किये जाने चाहिए। यदि ब्राडक्रास्टर द्वारा कतिपय अनुचित शर्तें लगाई जाती हैं तो चैनलों के वितरक जो इससे निजात पाने के लिए इच्छुक हो को 12 महीनों की अवधि की समाप्ति के बाद तत्काल टीडीएसएटी से संपर्क करना चाहिए। यदि ट्राई द्वारा मानक करार विनिर्दिष्ट किया जाता है तो इस प्रकार के अधिकांश मतभेदों को दूर किया जा सकता है और नवीकरण के कार्य में तेजी लाई जा सकती है। 12 महीनों की अवधि/करार के बीत जाने के बाद भी, जैसे भी उपर उल्लेख किया गया है, यदि विश्वास पर लेन-देन चलता रहता है, तो नई अवधि के लिए नए वाणिज्यिक शर्तों को पूरा करने तक इसे जारी रखा जा सकता है और चैनलों को काटा नहीं जाएगा और जैसे ही नए वाणिज्यिक शर्तों को पूरा किया जाता है, वे स्वतः नई अवधि की शुरुआत की तारीख से लागू हो जाएंगे। (सीटी केबल)

8. करार और उसके नवीकरण की समय सीमा एक वर्ष से कम और उसके बाद आपसी सहमति के बगैर नहीं होगी। ऐसा कोई विधिक प्रावधान नहीं है कि करार एक वर्ष पश्चात समाप्त होगा और इसका नवीनीकरण भी नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अन्तर संयोजन करार का उल्लंघन माना जाएगा। लाइसेंसी द्वारा अन्तर संयोजन करार पर हस्ताक्षर करते ही यह लाइसेंस अवधि के लिए वैध होगा और इसको किसी प्रकार से काटा जाना पर अपवाद होगा न कि नियम और इसकी अनुमति तभी दी जाएगी जब अन्य सभी प्रयोग इसे निपटाने में असफल हों। यदि ये संविदाएं दीर्घकालिक संविदाएं नहीं हैं तो यह व्यवसाय अनिश्चित होगा और इस व्यापार में निवेश करना कभी भी सुरक्षित नहीं होगा और इससे न केवल सेवा प्रदाताओं बल्कि उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा यदि अपने सेवा प्रदाता प्रति वर्ष बदलते रहेंगे। कई न्यायिक मामलों में यह देखा गया है जब कभी भी करार में नवीनीकरण होता है, ब्रोडक्रास्टर्स राजस्व बढ़ाने अन्यथा सेवाएं न देने या संविदा का नवीनीकरण न करने की धमकी देते हैं यह ब्रोडक्रास्टर्स की ओर एक प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार भी है, क्योंकि वे एक वर्ष के लिए सब्सक्राइबर

आधार की निर्धारित संख्या तथा सब्सक्राइबर्स की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन न करने के करार पर हस्ताक्षर पर जोर डालते हैं। वे नए करारों पर भी हस्ताक्षर करने पर जोर डालते हैं। यदि कोई करार है तो यह लाइसेंसिंग के लिए या प्राधिकृत वितरण के लिए होना चाहिए तथा भुगतान समय-समय पर घोषित किए गए सब्सक्राइबर आधार के आधार पर होना चाहिए न कि वार्षिक संविदा के आधार पर। संविदा को बढ़ाने के लिए यह उचित होगा कि समझौता-वार्ता 60 दिन पूर्व शुरू की जाए ताकि समझौता-वार्ता के लिए दिए गए 30 दिन और यदि पार्टियां करार तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाती तो इस 30 दिन के अंदर टीडीसेट से संपर्क किया जा सके। (आईएमसीएल)

9. जब तक पुराने करार या मौखिक करार लागू हैं तब तक इस कार्य को जारी रखा जाना चाहिए। यदि समझौता वार्ता पूर्णतः विफल हो जाती है तो उस मामले में ब्राडक्रास्टर्स/एमएसओ से एमएसओ/एलएसओ, जैसा भी मामला हो, को एक महीने का नोटिस दिया जाना आवश्यक है और यदि प्रभावित पार्टी के अधिकारों का हनन होता है तो प्रभावित पार्टी न्याय के लिए संबंधित फोरम से संपर्क कर सकती है। उस समय तक अन्तरसंयोजन क्षेत्र से जुड़ी पार्टियों को वार्ता के माध्यम से करार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्राधिकरण को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए कि मौखिक व्यवस्था/मौखिक करार सिस्टम में मूल्य श्रृंखला के बीच आपसी संबंध निर्धारित करने के लिए समझौते के एक भाग के रूप में होना चाहिए। करार कम से कम तीन वर्ष तक लागू रहना चाहिए तथा सब्सक्राइबर्स की दर तथा संख्या या परस्पर वार्ता द्वारा सहमत एकमुश्त आवधिक अंशदान शुल्क या चैनलों की संख्या, जैसा भी मामला हो, ऐसे वाणिज्यिक कार्यकलापों को 12/18 महीने के उपयुक्त अंतराल पर पुनः सही किए जाने की आवश्यकता है। (हैथवे)

10. किसी करार की समय सीमा तथा उसका नवीकरण एक वर्ष से कम नहीं होना चाहिए तथा इसके पश्चात इसे आपसी समझौते से बढ़ाया जा सकता है। ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है कि करार एक वर्ष बाद समाप्त हो जाते हैं तथा उनका नवीकरण भी नहीं किया जा सकता क्योंकि यह "मस्ट प्रोवाइड" अन्तरसंयोजन विनियम की अवहेलना है। आदर्शतः लाइसेंसधारी जब एक बार अन्तरसंयोजन करार पर हस्ताक्षर कर लेता है तो यह लाइसेंस की अवधि तक मान्य होना चाहिए तथा किसी प्रकार का वियोजन अपवाद के रूप

में होना चाहिए न कि नियम के रूप में तथा इसकी अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए यदि विवाद सुलझाने के सभी तरीके निष्फल हो जाएं। यदि ये संविदाएं लंबी अवधि की संहिता नहीं हैं तो यह व्यवसाय अनिश्चित होगा तथा इस व्यवसाय में किया गया निर्णय कभी भी सुरक्षित नहीं होगा और न केवल सर्विस प्रदाता बल्कि उपभोक्ता को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा यदि प्रति वर्ष सर्विस प्रदाता को बदलना पड़ा। बहुत से कोर्ट केसों से यह स्पष्ट है कि जब कभी किसी करार का नवीकरण करना होता है, तो ब्राडक्रास्टर सेवा बंद किए जाने या संविदा का नवीकरण करने से इकार करने की धमकी से राजस्व में वृद्धि करने के लिए नोटिस भेज देते हैं। ब्राडक्राटरों की ओर से यह भी एक प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार है चूंकि वे एक वर्ष के लिए सब्सक्राइबर्स की निर्धारित संख्या तथा सब्सक्राइबर्स की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन न करने के करार पर हस्ताक्षर करने का आग्रह करते हैं। वे नए करारों पर हस्ताक्षर करने का आग्रह करते हैं। यह अनुभव किया गया है कि यदि करार होता है तो यह लाइसेंसिंग या प्राधिकृत वितरण के लिए होना चाहिए तथा भुगतान घोषित किए गए सब्सक्राइबर आधार के आधार पर होना चाहिए। संविदा को आगे बढ़ाने के लिए, यह उचित होगा कि समझौता वार्ता 60 दिन पूर्व शुरू की जाए ताकि समझौता-वार्ता के लिए 30 दिन दिए जाते हैं और 30 दिन तक यदि पार्टियां कोई करार करने में सफल नहीं हो तो टीडीसैट से संपर्क किया जा सके।
(सीओएफआई)

परामर्श के लिए मुद्दा

एफ टी ए चैनलों का पै-चैनलों में बदलाव

- क्या एफ टी ए चैनलों को पे-चैनलों में बदलने के लिए अग्रिम नोटिस जारी किया जाना चाहिए ताकि यदि सेवा-प्रदाता करार नहीं कर पाता है तो एफ टी ए चैनलों को पे-चैनलों में बदले जाने की तारीख से वियोजित किए जाने के संबंध में सब्सक्राइबर्स को पर्याप्त समय पूर्व अग्रिम नोटिस मिल जाए?

प्राप्त टिप्पणियाँ

- 1 जी हां, कम से कम तीन माह । (कर्नल वी सी खरे (सेवानिवृत्त) केबल टी वी उद्योग पर्यवेक्षक)
- 2 एफ टी ए चैनलों को पै-चैनलों में परिवर्तित इसलिए किया जाता है ताकि ब्राडकास्टर एसएसओ/केबल आपरेटरों से अंशदान राजस्व का संग्रहण कर सकें। अतः ब्राडकास्टरों के लिए यह उपयुक्त होगा कि चैनलों का रूपांतरण करने से पूर्व वे एमएसओ/केबल आपरेटरों से बातचीत कर लें। यदि ब्राडकास्टर और एमएसओ/केबल ऑपरेटर कसर करने में सफल नहीं हो पाते, तो विनियम के खंड 4. 1 (क) के अनुसार ब्राडकास्टर और उपभोक्ता को एक सप्ताह का नोटिस दिया जाना चाहिए (स्टार)
3. यह मान लेना सुरक्षित होगा कि ब्राडकास्टर और एमएसओ/केबल आपरेटर निशुल्क से पे चैनल में रूपांतरण की तारीख से पर्याप्त समय पूर्व वाणिज्यिक समझौता-वार्ता कर लेंगे। बहरहाल, जो पार्टियां रूपांतरण के कसर तक नहीं पहुंच पाती, उन्हें उनके मौजूदा करार की समाप्ति पर निशुल्क चैनलों के लिए समझौता-वार्ता करने हेतु छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि ट्राई नोटिस अवधि का निर्धारण करना चाहता है तो 7 दिन की अवधि पर्याप्त होगी। (एमपीए)
4. इस अधिनियम में एफटीए चैनलों को पे-चैनलों में परिवर्तित करने के लिए 2 माह का अग्रिम नोटिस दिए जाने का उल्लेख होना चाहिए ताकि यदि सर्विस प्रदाता कोई करार नहीं कर पाते हैं तो सब्सक्राइबर्स को पे-चैनलों में रूपांतरण की तारीख से चैनलों के काटे जाने के संबंध में पर्याप्त नोटिस दिया जा सके। (ईएसपीएन)
5. बेसिक सेवाओं के टैरिफों में किसी वृद्धि से बचने के लिए पे चैनल में परिवर्तित होने वाले एफटीए चैनलों के एसटीबी पर कैस के माध्यम से ट्रांसमिट करना होगा। चूंकि इसे पीछे की तिथि से प्रभावी नहीं किया जा सकता, अतः इसे भविष्य में बेसिक टीयर

में पे चैनलों की बढ़ती संख्या से बचने/को रोकने के लिए किया जाना चाहिए विशेषकर पे टियर की अनुपलब्धता के कारण। इससे निम्न आय वाले ग्राहकों का बोझ भी हल्का होगा क्योंकि वे उच्च आय वाले ग्राहकों की लागत को काफी कम रहे हैं क्योंकि प्रत्येक नये चैनल का भार सभी सब्सक्राइबर्स पर समान रूप से डाला जाता है। इसमें वे भी शामिल हैं जो इन्हें देखते भी नहीं हैं। इस उद्देश्य के लिए और ग्राहकों को बाधा-रहित सेवा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम छः माह का नोटिस अग्रिम में निर्धारित किया जाना चाहिए। उल्लिखित अवधि न्यूनतम है जिसके दौरान ग्राहक अपना विकल्प दे सकेंगे और सेवा प्रदाता एसटीबी रोल आउट करने के लिए पे टियर सेवा रोल आउट करने के लिए बाक्सों की संख्या/आवश्यक निवेश का आकलन कर सकेगा। इससे वास्तविक रूप से ट्राई को मौजूदा तथाकथित (बाधित)बेसिक सेवा टियर को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी, जबकि बाजार की शक्तियों द्वारा पे टियर मूल्यों का निर्धारण किया जाएगा, जिससे आपरेटरों को कैस रिजीम को धीमे-धीमे अपनाने में सहायता मिलेगी न कि उन्हें इस रिजीम में लादा जाएगा, अतः स्वैच्छिक कैस के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। (ओस्टेल)

6. जी हां एफटीए चैनल से पे चैनल में परिवर्तित होने के लिए 2 महीने का नोटिस दिया जाना निर्धारित किया जाए ताकि करार करने के लिए समुचित समय रहे और ऐसा करने में चूक के मामले में उन चैनलों को हटाने के संबंध में सब्सक्राइबर को पर्याप्त नोटिस मिल जाएगा। (बीएनबी केबल्स)
7. सामान्य तौर पर एफटीए से पे चैनल में बदलाव का चैनलों द्वारा काफी पहले नोटिस दिया जाता है। बहरहाल, उन्हें आम जनता को न्यूनतम 6 महीने पहले मासिक अंतरालों पर यह बता देना चाहिए कि वे पे चैनल में परिवर्तित हो रहे हैं। इससे ग्राहकों को समझने में सहायता मिलेगी कि यदि वे सेवाएं लेना जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए और ज्यादा भुगतान करना होगा। चैनलों को रेगुलेटर के पास अधिकतम फूटकर मूल्य और उसके वितरण मार्जिन सहित उनके निर्धारित दरों का ब्यौरा देना चाहिए। (एससी)
8. मौजूदा एफटीए चैनल जो पे चैनल में परिवर्तित होना चाहता है को न्यूनतम 3 माह का अग्रिम नोटिस देना चाहिए ताकि चैनलों के वितरक ऐसे चैनलों के साथ करार पर

समझौता कर सकें और ग्राहक भी यह जान सकें कि एक विशेष चैनल के लिए उन्हें भुगतान करना होगा और इसके परिणामस्वरूप उनके केबल बिल में मासिक वृद्धि होगी। इसके साथ-साथ ट्राई के समक्ष एक टैरिफ घोषणा दायर करने की भी आवश्यकता होगी, जिसे ट्राई द्वारा अपनी वेब साइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
(सिटी केबल)

9. छ: माह का अग्रिम नोटिस (आईएमसीएल)

10. जी हां प्रत्येक तीन महीनों में सिर्फ एक बार ही अर्थात् प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 सितम्बर और 1 जनरी को तीन महीनों का अग्रिम नोटिस में ताकि प्रणाली के बारे में पूर्व में ही जानकारी हो जाए और सूचना प्रणाली में प्रत्येक कड़ी तक पहुंच जाएं। (हैथवे)

11. छ: माह का अग्रिम नोटिस (कोफी)

परामर्श के लिए मुद्दा

संदर्भ इंटरकनेक्ट प्रस्ताव (आरआईओ)

- क्या सक्रिय प्लेयर के आदर्श सब्सक्रिप्शन करार की शर्तों और निबंधन को अनुमोदित करने और ब्राडक्रस्टिंग और केबल टीवी सेवाओं में उनकी गतिविधियों में विनियमित करने के लिए ट्राई द्वारा आर आई ओ जारी किया जाना चाहिए? यदि हां, तो ऐसे आदर्श सब्सक्रिप्शन करार के लिए क्या तत्व होने चाहिए ?

प्राप्त टिप्पणियां

1. जी हां। सुझाए गए कुछ तत्व होने चाहिए जैसे करार से संबंधित चैनलों/प्रोग्रामों की विस्तृत सूची, करार की तिथि पर सब्सक्राइबर आधार, अंतिम उपभोक्ता के उल्लेख के लिए प्रत्येक चैनल के मोल-भाव दर और वितरक से प्रभारित की जाने वाली थोक दर, बाधाएं डालने वाले कारणों को बताना, यदि कोई हो तो, विवादों का निपटारा और बाधाओं के मामले

में दायित्व, अनाधिकृत वितरण/पाइरेसी के विरुद्ध निवारक उपाय और उनके मामले आने पर उठाए जाने वाले कदम, माध्यस्थता के लिए व्यवस्था और करार समाप्त होना, ब्राडकास्टर की वचनबद्धता और वितरक की क्षतिपूर्ति, सामग्री और विज्ञापन संहिता का पालन न करने के किसी मामले में, ब्राडकास्टर द्वारा सेवा में व्यवधान के मामले में सब्सक्राइबर को दी जाने वाली धन वापसी, अनौचित्यपूर्ण व्यवधान के विरुद्ध रोकथाम के लिए ब्राडकास्टर से बैंक गारन्टी लेना और यदि ब्राडकास्टर द्वारा विनियम को तोड़ा जाता है तो डाउनलिकिंग पंजीकरण को रद्द करने के लिए व्यवस्था/ऐसे किसी परिदृश्य की कल्पना करना काफी कठिन है जहां ब्राडकास्टर/वितरक के रिश्ते विवाद रहित होंगे अतः इस पर विचार किया जाना है कि "इन करारों को कौन स्टोर करेगा?" ट्राई के मौजूदा कर्मचारी इस कार्यभार को वहन करने में समर्थ नहीं हैं। अतः ट्राई के अधीन एक केबल टी वी विनियम स्कंध या पर्याप्त संख्या में क्षेत्रीय कार्यालयों सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सीआरएआई (भारतीय केबल टी वी विनियम प्राधिकरण) स्थापित किया जाए। (कर्नल वीसी खरे (सेवानिवृत्त) केबल टी वी उद्योग पर्यवेक्षक)

2. ब्राडकास्टर एम एस ओ और केबल आपरेटर के साथ अपने हितों की सुरक्षा के लिए वाणिज्यिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए मुक्त होना चाहिए। ऐसे हित, जो कि ट्राई द्वारा पूर्व में मौखिक रूप से रिकार्ड किया गया है, अथवा सब्सक्रिप्शन करार के रूप में लिखित में दे दिया है। राज्य शासित सेवा प्रदाता के इन्कम्बेंट एकाधिकार होने के कारण ट्राई द्वारा टेलीकॉम आपरेटरों के लिए आर आई ओ जारी किया गया। हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि प्रसारण के मामले में यह स्थिति नहीं है। अतः आरआईओ जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ट्राई का मत है कि सब्सक्रिप्शन करार खत्म करने के पूर्व पार्टियों को विचार-विमर्श करने के लिए विहंगम दृश्य उपलब्ध कराना अत्यावश्यक है। (स्टार)

3 सब्सक्रिप्शन करार के लिए ट्राई के अनुमोदन की भूमिका नहीं हेनी चाहिए। यह सरकार द्वारा सेक्टर के लिए एक पूर्ण रेगुलेटरी रिजीम शुरू करने के समान है और इसे कुछ देशों में सी एवं एस सेक्टर में रेगुलेटर की भूमिका के स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वास्तविक रूप से बाजार के विकास के लिए और निवेशक द्वारा एक दिए गए बाजार के वास्तविक मूल्य को समझने के लिए वाणिज्यिक करारों में किसी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए (यूएसआईबीसी)

4. ये करार वाणिज्यिक करार हैं तथा इस करार की शर्तों को पार्टियों की निजी इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। करार पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने का न तो किसी को अधिकार होना चाहिए न ही किसी के पास शक्ति। (ईएसपीएन)

5. यह इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पहलु है और एकाधिकार समाप्त करने की जिम्मेदारी ब्राडकास्टर्स को सौंपी जानी चाहिए तथा एमएसओ एक क्षेत्र में एक से अधिक आपरेटर नियुक्त करें ताकि उपभोक्ता किसी एक आपरेटर की दया का पात्र न बनें। (बीएनबी केबल्स)

6. दूरसंचार क्षेत्र में लागू तथा प्रभावी बताए गए अनुसार एक संदर्भ अन्तरसंयोजन करार होना चाहिए। परिभाषित मूल तत्व इस प्रकार के होने चाहिए: ब्राडकास्टर/एमएसओ द्वारा अन्तरसंयोजन दरों की घोषणा करना तथा ट्राई की वेबसाइट में उनका प्रकाशन; ऐसी दरों का गैर-मूलभेदक अनुप्रयोग; हस्ताक्षरित करार कर आश्रय लेने से पूर्व एक माह की अवधि के भीतर कनटेंट मुहैया कराने के सिद्धान्त; डिकोडरों में अनिवार्य फिंगर प्रिंटिंग के पायरेसी रोधी उपाय करना जो मुहैया कराए जाते हैं; किसी विशेष ऑपरेटर के लिए फोर्सड एड्रसेबल मैसेजिंग अनिवार्य बनाना तथा स्क्रीन आदि चलाने पर रोक लगाना; भुगतान, लेखाकन के लिए बैंक एक्सेस बनाना तथा सभी ब्राडकास्टर्स तथा एमएसओ को अनिवार्य रूप से प्राधिकृत करना; एफसीसी द्वारा निर्धारित समान पैटर्न पर सभी ब्राडकास्टर्स तथा एमएसओ द्वारा मासिक तथा वार्षिक रिटर्न भरना तथा ऐसे सभी डाटा को सभी स्टोक होल्डरों द्वारा एक्सेस किए जाने के लिए बैंक पर डालना। (एएससी)

7. माननीय टीडीसैट ने स्टार इंडिया बनाम इंडसइंड मीडिया नामक याचिका सं. 41सी/2004 में, अन्तरसंयोजन विनियम के अंतर्गत अनिवार्य अपेक्षा के रूप में ब्राडकास्टर्स तथा एमएसओ/केबल ऑपरेटर के बीच लिखित करार के निष्पादन को अधिदेशित किया है। यह सुझाव दिया जाता है कि ट्राई को गैर-कैस क्षेत्र के लिए मानक करार का मसौदा तैयार करने तथा अधिसूचित करने की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए जिसे एक मॉडल करार के रूप में सभी स्टोकहोल्डरों द्वारा अपनाया जा सकता हो तथा जिसे ट्राई द्वारा अनुबंधित उक्त मॉडल करार के अनुसार, अपने करार को डिजाइन तैयार कर सके। करार में अन्तरसंयोजन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए जैसे क्षेत्र, सब्सक्राइबर आधार, वितरण का तरीका,

अप्राधिकृत वितरण, कन्टेंट जिम्मेवारियां आदि। ट्राई द्वारा मानक करार तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू करते ही इस संबंध में विस्तृत इनपुट मुहैया कराए जा सकते हैं। सिटी केबल का विचार है कि मानक करार को न केवल केबल वितरण के लिए बल्कि अन्य वितरण प्लेटफार्मों के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए। (सिटी केबल)

8. डोमिनेंट प्लेयरों को विनियमित करने के लिए आरआईओ जारी किया जाना चाहिए तथा आरआईओ में प्राधिकरण की स्थिति/शक्तियां; मांगा गया क्षेत्र; दर; भुगतान अवधि; कितने वर्ष; पारदर्शिता तथा प्रतियोगिता बढ़ाना तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देना आदि जैसे तत्व शामिल होने चाहिए। जब तक आरआईओ को अंतिम रूप दिया जाता है तथा आरआईओ को तैयार करने का उद्देश्य तय किया जाता है, तब तक जो मुद्दे ध्यान में रखे जाने हैं, वे हैं: एमएसओ को केबल ऑपरेटरों/फ्रेंचाइजों की कार्रवाईयों के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता; एक न्यूनतम गारंटी उपबंध नहीं होना चाहिए; बातचीत के जरिए तय हुए सब्सक्राइबर आधार के मामले में सब्सक्राइबरों के ब्यौरे/सूची, की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और करार की निर्धारित अवधि के दौरान सब्सक्राइबर आधार में बढ़ोतरी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए; वास्तविक सब्सक्राइबर आधार में हुए करार के मामलों में, मानो 3 मासिक संशोधन (अप या डाउन) निर्धारित किए जाएं जिसमें दोनों ओर से मानो 5% की अधिकतम सीमा हो; औद्योगिक टाउनशिप को करार से हटाया नहीं जाना चाहिए; सेवा क्षेत्र के भीतर विस्तार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए; सेवा क्षेत्र की परिभाषा में सीमांकित सेवा क्षेत्र के मौजूदा तथा नए दोनों घरों को शामिल किया जाना चाहिए; करार प्रौद्योगिकी की दृष्टि से तटस्थ होना चाहिए; कनेक्शन काटे जाने की परिस्थितियां निर्धारित की जाएं; पायरेसी के मामलों को छोड़कर, जहां नोटिस अवधि सात दिन की होनी चाहिए; अन्य सभी मामलों में 30 दिन की एक समान नोटिस अवधि निर्धारित की जाए; यह स्पष्ट किया जाए कि सेवा क्षेत्र के भीतर विस्तार पायरेसी नहीं है; नक्शों की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए; ब्राडकास्टर्स को एमएसओ के खाते/रिकार्ड देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए; अन्य पार्टियों के साथ एमएसओ का संविदात्मक संबंध रखना ब्राडकास्टर्स का विषय नहीं होना चाहिए; कन्टेंट के लिए लाइसेंस लेना ब्राडकास्टर्स की जिम्मेवारी होनी चाहिए; "मस्ट प्रोवाइड खण्ड" में यह स्पष्ट रूप से उपबंधित किया जाए कि इच्छुक सब्सक्राइबरों को 30 दिन की अवधि के भीतर चैनल/कनेक्टीविटी मुहैया कराई जाएगी जिस

अवधि में ब्राडकास्टर्स या एमएसओ, जैसा भी मामला हो, के एजेंटों के साथ सभी समझौते, बातचीत करने की अवधि शामिल होगी तथा समूह के किराए के बिल को सभी कोटियों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। (आईएमसीएल)

9. जी हां। उपभोक्ताओं/एण्ड सब्सक्राइबर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए, करार करने के अधिकारों तथा दायित्वों सहित भारतीय संविदा अधिनियम के मूल सिद्धांतों को ही शामिल किया जाए। (हैथवे)

10. डोमिनेंट प्लेयर्स को विनियमित करने के लिए आरआईओ जारी किया जाना चाहिए तथा आरआईओ में प्राधिकरण की स्थिति/शक्तियां; मांगा गया क्षेत्र; दर; भुगतान अवधि; कितने वर्ष; पारदर्शिता तथा प्रतियोगिता बढ़ाना तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देना आदि जैसे तत्व शामिल होने चाहिए। जब तक आरआईओ को अंतिम रूप दिया जाता है तथा आरआईओ को तैयार करने का उद्देश्य तय किया जाता है, तब तक जो मुद्दे ध्यान में रखे जाने हैं, वे हैं: एमएसओ को केबल ऑपरेटर्स/फ्रेंचाइजों की कार्रवाईयों के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता; एक न्यूनतम गारंटी उपबंध नहीं होना चाहिए; बातचीत के जरिए तय हुए सब्सक्राइबर आधार के मामले में सब्सक्राइबर्स के ब्यौरे/सूची, की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और करार की निर्धारित अवधि के दौरान सब्सक्राइबर आधार में बढ़ोतरी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए; वास्तविक सब्सक्राइबर आधार में हुए करार के मामलों में, मानो 3 मासिक संशोधन (अप या डाउन) निर्धारित किए जाएं जिसमें दोनों ओर से मानो 5% की अधिकतम सीमा हो; औद्योगिक टाउनशिप को करार से हटाया नहीं जाना चाहिए; सेवा क्षेत्र के भीतर विस्तार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए; सेवा क्षेत्र की परिभाषा में सीमांकित सेवा क्षेत्र के मौजूदा तथा नए दोनों घरों को शामिल किया जाना चाहिए; करार प्रौद्योगिकी की दृष्टि से तटस्थ होना चाहिए; कनेक्शन काटे जाने की परिस्थितियां निर्धारित की जाएं; पायरेसी के मामलों को छोड़कर, जहां नोटिस अवधि सात दिन की होनी चाहिए; अन्य सभी मामलों में 30 दिन की एक समान नोटिस अवधि निर्धारित की जाए; यह स्पष्ट किया जाए कि सेवा क्षेत्र के भीतर विस्तार पायरेसी नहीं है; नक्शों की व्यवस्था करने की कोई

आवश्यकता नहीं होनी चाहिए; ब्राडकास्टर्स को एमएसओ के खाते/रिकार्ड देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए; अन्य पार्टियों के साथ एमएसओ का संविदात्मक संबंध रखना ब्राडकास्टर्स का विषय नहीं होना चाहिए; कनटेंट के लिए लाइसेंस लेना ब्राडकास्टर्स की जिम्मेवारी होनी चाहिए; "मस्ट प्रोवाइड खण्ड" में यह स्पष्ट रूप से उपबंधित किया जाए कि इच्छुक सब्सक्राइबर्स को 30 दिन की अवधि के भीतर चैनल/कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी जिस अवधि में ब्राडकास्टर्स या एमएसओ, जैसा भी मामला हो, के एजेंटों के साथ सभी समझौते, बातचीत करने की अवधि शामिल होगी तथा समूह के किराए के बिल को सभी कोटियों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। (कोफी)

परामर्श के लिए मुद्दा

अंतिम छोर पर एकाधिकार

- अंतिम छोर पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि ग्राहकों को विकल्प मिल सके?
- क्या परिचालन के उन क्षेत्रों में विनियामक फ्रेमवर्क संस्थापित किए जाने चाहिए और क्या अन्य ऑपरेटरों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए?

प्राप्त टिप्पणियां

1. यह कहना गलत है कि एलसीओ का एकाधिकार है। केबल नेटवर्क को चलाने के लिए पंजीकरण के इच्छुक व्यक्ति के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। निकट भविष्य में, केबल टीवी नेटवर्कों पर दर्शकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे डीटीएच और आईपीटीवी उपलब्ध होंगे ताकि वे केबल टीवी, आईपीटीवी और डीटीएच में से किसी एक का चुनाव कर सकें। वैसे क्षेत्रों जैसे टेलीकॉम सर्कलों की जब तक नीलामी नहीं हो जाती, तब तक निवेशकों जिनके पास वित्तीय समर्थ्य हो, परिचालन के क्षेत्रों का निर्धारण के लिए विनियामक फ्रेमवर्क और ऑपरेटरों की संख्या का पता लगाना व्यावहारिक नहीं हो सकता है। डाक घरों में पंजीकरण

कराने की प्रणाली में पंजीकरण प्रमाण-पत्र के हिस्से के रूप में रिप्रजेनटेटिव स्केच सहित आवेदक के परिचालन क्षेत्र का उल्लेख किया जा सकता है। पंजीकरण प्राधिकारी प्रत्येक पंजीकृत हुए व्यक्ति के परिचालन क्षेत्र से संबंधित मानचित्र/रेखाचित्र तथा उस क्षेत्र में पंजीकृत हुए एक से अधिक व्यक्तियों, यदि कोई हो, को दर्शाते हुए जारी कर सकता है।

(कर्मल वीसी खरे (सेवानिवृत्त) केबल टीवी उद्योग पर्यवेक्षक)

2. इस मुद्दे को अन्य वितरण प्लेटफार्म के आगमन पर जब आंशिक रूप से संबोधित किया गया हो, तो अंतिम छोर पर एकाधिकार को केवल स्पष्ट लाइसेंसिंग रिजीम का निर्धारण करके एड्रेस किया जा सकता है। ट्राई द्वारा विनियामक फ्रेमवर्क जिसमें टेलीकॉम की तरह पूरे भारत में विभिन्न प्रदेशों में केबल ऑपरेटरों की लाइसेंसिंग को शामिल किया जाएगा, को लागू करने पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए। ट्राई या तो पूरे भारत में अथवा भारत के किन्हीं खास क्षेत्रों में केबल के लिए लाइसेंस धारकों की नियुक्ति के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित कर सकता है। इन क्षेत्रों का सीमांकन राज्यवार, शहरवार आदि के रूप में किया जा सकता है। टेलीकॉम मामले की तरह ही ट्राई प्रत्येक परिचालक क्षेत्र के लिए एक या अधिक केबल ऑपरेटरों को अनुमति दे सकता है। केबल ऑपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क से यह सुनिश्चित होगा कि लंबित अवधि के लिए निवेश करने के इच्छुक केवल गंभीर ऑपरेटर ही इस बाजार में परिचालन करेंगे। (स्टार)

3. "अंतिम छोर" एकाधिकार को डीटीएच सैटेलाइट टीवी सेवा के माध्यम से पहले ही हटा लिया गया है। ट्राई द्वारा भारत में केबल ऑपरेटरों के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क का विकास करने के लिए तत्काल पहल की जानी चाहिए ताकि ऑपरेटरों पर अपने सब्सक्राइबर आधार और परिचालन के क्षेत्र के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए दबाव बनाया जा सके। लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के न होने पर, यथावत स्थिति ही इस परामर्श में ट्राई द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त, अंतिम छोर पर अधिक निवेश की आवश्यकता और संपिंडन कम हो जाता है क्योंकि निवेशक विखंडित, अपारदर्शी बाजार से दूर भागते हैं। (यूएसआईबीसी)

4. वास्तव में, डीटीएच सैटेलाइट टेलीविजन सेवा पहले से ही "अंतिम छोर" केबल ऑपरेटरों के लिए प्रभावशाली प्रतिस्पर्धा मुहैया करा रहा है और कुछ क्षेत्रों में समग्र पे टीवी सब्सक्राइबर्स के 15% तक सेवा प्रदान करते हुए सब्सक्राइबर्स की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि कर रहा है। ट्राई द्वारा इस विशेष मुद्दे पर परामर्श के माध्यम से प्रतिस्पर्धा के स्तर के संबंध में विचार किया जाना। (एमपीए)
5. टेलीक्रॉम सेक्टर की तरह इस उद्देश्य के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रणाली में प्रत्येक क्षेत्र के लिए दो से तीन लाइसेंसधारक हो। एलसीओ स्तर पर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने का यह बेहतर संभावित तरीका है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए विनियामक फ्रेमवर्क का निर्धारण किया जाए। (ईएसपीएन)
6. कैरिज अथवा इसकी शर्तों का विनियमित करने के लिए किसी प्रकार के विनियम की सिफारिश नहीं की जाती। (एएससी)
7. डीटीएच, ब्राडबैंड और एचआईटीएस के लांच होने से, अंतिम छोर ऑपरेटर का तथाकथित मौजूदा वस्तुतः एकाधिकार अधिक समय तक नहीं बना रहेगा। इस प्रकार के परिदृश्य में इससे संबंधित किसी प्रकार का विनियम अनावश्यक है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि परिचालन के किसी क्षेत्र में मल्टीपल ऑपरेटरों के होने से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और अंततः इससे ग्राहकों को फायदा पहुंचेगा। किसी क्षेत्र में ऑपरेटरों की संख्या को सीमित करने अथवा प्रतिबंध लगाने से इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करना होगा, यह अलाभप्रद होगा, इसलिए ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए। (सिटी केबल)
8. विनियामक के पास अब इतना समय नहीं है कि वे परिचालन के क्षेत्र और ऑपरेटरों की संख्या का उल्लेख करना कर सके क्योंकि ऐसा करना बहुत जटिल कार्य होगा चूंकि परिचालन के क्षेत्र अथवा ऑपरेटरों की संख्या चिह्नित नहीं है। जैसे दक्षिण दिल्ली में 5-7 एमएसओ हैं और स्वतंत्र ऑपरेटर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में

किसी का एकाधिकार नहीं है। फरीदाबाद जैसे स्थान भी हैं जहां वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी का प्रत्येक अंतिम छोर सहित प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्यक्ष एकाधिकार है और अभी तक यहां कोई भी एमएसओ प्रवेश करने में समर्थ नहीं हुआ है। इस समय नए प्रवेशकों के लिए कंटेंट सही प्रकार से और निरपवाद रूप से उपलब्ध है और अंतिम छोर पर एकाधिकार यथावत रहेंगे। वास्तव में आईएमसीएल की धारणा है कि किसी भी प्रकार का एकाधिकार नहीं है क्योंकि हजारों की संख्या में ऑपरेटर हैं दूसरी ओर जब अन्तरसंयोजन विनियम नहीं था तब तीन से चार डीटीएच प्लेटफार्म प्रदाताओं जो केबल ऑपरेटरों की हजारों की निर्धारित संख्या के लिए विशेष कमेंटेंट मुहैया कराना चाहेंगे, के लिए अन्तर्विहित एकाधिकार हो सकता है। (आईएमसीएल)

9. केवल वैकल्पिक प्लेटफार्म जैसे डीटीएच, आईपीटीवी आदि के रूप में विकल्प चुनने की सुविधा है, चूंकि बाजार में काफी प्रतिस्पर्धा है इसलिए अंतिम छोर पर तथाकथित एकाधिकार कात्पनिक है। परिचालन के क्षेत्रों और ऑपरेटरों की संख्या का उल्लेख करना गैर प्रतिस्पर्धात्मक हो सकता है और इससे प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, यह केन्द्रीय कानून अर्थात् केबल टीवी अधिनियम जो एक विशेष पोस्ट ऑफिस के क्षेत्राधिकार/क्षेत्र में परिचालन के लिए लाइसेंस मुहैया करता है, के प्रतिकूल होगा। जब तक उसके पास अपेक्षित डाक घर लाइसेंस है और मनोरंजन कर पंजीकरण/सेवा कर पंजीकरण है और किसी स्थानीय एमएसओ से जुड़ने का संबंध है और इस संबंध में अपनी सच्चाई पूर्ण घोषणा प्रस्तुत करता है कि आयकर अधिनियम (नया सरल) के तहत वैध परमानेंट एकाउंट नंबर है तो इस विनियम को केन्द्रीय सरकार के किसी कानून विरुद्ध नहीं माना जा सकता और वह अपने कुल घोषित सब्सक्राइबर आधार के लिए सिगनल मुहैया कराए जाने का पात्र है। (हैथवे)

10. विनियामकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह परिचालन के क्षेत्र और ऑपरेटरों की संख्या का उल्लेख करें क्योंकि यह लाइसेंसिंग का एक हिस्सा है। वास्तव में अंतिम छोर पर कोई एकाधिकार नहीं है क्योंकि केबल टीवी नेटवर्क को शुरू करने के लिए केबल

ऑपरेटर्स की कितनी भी संख्या का डाक घर में पंजीकरण कराया जा सकता है। एमएसओ/ब्राडकास्टर के स्तर पर एकाधिकार का सृजन वहां होता है जहां समझौते और गठजोड़ के रूप में कार्य होते हैं। जब तक नए प्रवेशकों को कंटेंट सही और निपवाद रूप से उपलब्ध होंगे जब तक अंतिम छोर का एकाधिकार रहेगा। (कोफी)

परामर्श के लिए मुद्दा

कैरिज शुल्क विनियम

- क्या केबल नेटवर्क पर कैरिज शुल्क का विनियमन होना चाहिए? यदि हां, तो वह किस आधार पर होना चाहिए तथा कैरिज प्रभारों की गणना किस प्रकार होनी चाहिए?
- यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा तरीका होना चाहिए कि कैरिज शुल्क की सीलिंग में वृद्धि नहीं हुई है?

प्राप्त टिप्पणियां

1. केबल नेटवर्क पर कैरिज शुल्क का विनियमन नहीं होना चाहिए। कैरिज शुल्क पे-टीवी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से प्रभारित राजस्व का अधिकतम होना चाहिए। संभवतः एफटीए के लिए कैरिज शुल्क पे-टीवी के लिए लगाए गए अधिकतम प्रभार का 25 % तक रखा जा सकता है। यह अधिक अच्छा होगा कि इसे नेटवर्क मालिकों पर ही छोड़ दिया जाए क्योंकि यह हेड एंड उपस्करों, नेटवर्क हार्डवेयर तथा आईएस 13420 की अनुरूपता की डिग्री की गुणवत्ता से भी संबंधित है। (कर्नल वीसी खरे (सेवानिवृत्त) केबल टी वी उद्योग पर्यवेक्षक)
2. चैनल सप्लायर तथा एमएसओ के बीच संबंध बाजार की शक्तियों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए तथा इसमें चैनल सप्लायर या कैरिज के लिए मूल्य विनियम का कोई औचित्य नहीं है। बहरहाल, स्टार इंडिया का विचार यह है कि विनियम समानता में यह अपेक्षा की जाती है कि जब चैनल सप्लायर की लागत फ्रीज हो जाती है तथा अंशदान शुल्क अभी उपलब्ध है तो कैरिज/प्लेसमेंट शुल्क पर सीलिंग लगाकर मूल्य स्थिर कर दिए जाने चाहिए।

ऐसी सीलिंग का उल्लेख प्रति सब्सक्राइबर रूप में होना चाहिए जैसी कि एमएसओ द्वारा घोषणा की गई है। ऐसा इस विषमता को दूर करने के लिए आवश्यक है कि जब ब्राडकास्टर्स का राजस्व फ्रीज हो जाता है तो ब्राडकास्टर्स की लागत (कैरिज शुल्क के संदर्भ में) किसी भी अनुपात में तथा किसी भी फ्रीक्वेंसी में बढ़ाई जा सकती है। एमएसओ के लिए यह अपेक्षित है कि वे अपने कैरिज करार की प्रतियां ट्राई के पास जमा कराएं ताकि सीलिंग लिमिट के अंतर्गत उनके भुगतान का सत्यापन किया जा सके। ट्राई कैरिज शुल्क पर लगाई गई ऐसी सीलिंग को हटाने का ठीक उसी समय विचार कर सकती है जब चैनल स्प्लाई तथा सब्सक्रिप्शन दरों पर लगाई गई मूल्य वृद्धि की रोक को वापिस लिया जाएगा। कैरिज शुल्क ब्राडकास्टर द्वारा बड़े एमएसओ को घोषित प्रति सब्सक्राइबर आधार पर किया जाएगा। इस प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि कैरिज शुल्क की सीलिंग नहीं बढ़ाई गई है। (स्टार)

3. चैनल स्प्लायर तथा एमएसओ के बीच संबंध बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अतः विनियम के दूसरी ओर मूल्य विनियमन का कोई औचित्य नहीं है अर्थात् चैनल स्प्लाई तथा कैरिज दरों को पार्टियों के बीच वाणिज्यिक वार्ता पर छोड़ दिया जाना उत्तम होगा। (यूएसआईबीसी)

4. चैनल स्प्लायर तथा एमएसओ/केबल ऑपरेटर के बीच संबंध प्रोग्रामिंग स्प्लाई में प्रतिस्पर्धा की डिग्री दर्शाते हुए बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाना सुरक्षित होगा। अतः ट्राई द्वारा चैनल या कैरिज दरों पर मूल्य विनियम अधिरोपित करने का कोई औचित्य नहीं है। (एमपीए)

5. केबल नेटवर्क पर कैरिज शुल्क इस प्रकार लगाए जाने चाहिए: (क) कैरिज शुल्क की राशि तर्कपूर्ण आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए ताकि नए प्रवेशक हतोत्साहित न हों। (ख) कैरिज शुल्क की राशि का निर्धारण चैनल प्रारंभ होने के शुरुआती महीनों में औचित्यपूर्ण होना चाहिए विशेषकर अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए तथा (ग) चैनल प्रारंभ होने के दो-तीन वर्षों बाद नए प्रवेशकों से प्रभार वसूल नहीं किए जाने चाहिए। (इएसपीएन)

6. कैरिज शुल्क का विनियमन एक अवांछनीय घटना है जोकि केबल तंत्र की सीमित क्षमता के कारण केबल ऑपरेटर्स द्वारा लागू किया गया है। इसके द्वारा एड्सेबल सिस्टम शुरू किया जाना संभावित है। इस समय, एसपी कैरिज या इसकी शर्तों के विनियमन की सिफारिश नहीं करता। (एसपी)

7. यह पूर्णतः अतार्किक होगा कि चैनल के विज्ञापन राजस्व को सुनिश्चित करने के लिए कैरिज/प्लेसमेंट शुल्क के विनियमन हेतु कोई प्रयास किया जाए। टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों तथा उनकी दरों पर कोई नियंत्रण/प्रतिबंध नहीं है। ये मांग और सप्लाई जैसी बाजार की शक्तियों द्वारा शासित हैं तथा लोकप्रियता और चैनलों की पहुंच पर भी आधारित हैं। जबकि दूसरी ओर चैनलों की लोकप्रियता तथा उनकी पहुंच चैनल की दृश्यता पर आधारित होती है। इस दृश्यता को सुनिश्चित करने के लिए ब्राडकास्टर्स द्वारा केबल ऑपरेटरों को शुल्क अदा किया जा रहा है। कैरिज/प्लेसमेंट शुल्क पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता तथा इसे किसी विनियम के द्वारा नियंत्रित करने की अपेक्षा डिजीटलीकरण को प्रोत्साहित करके केबल नेटवर्क पर क्षमता संवर्धन करना वास्तव में उचित एवं व्यावहारिक है। अतः कैरिज शुल्क ब्राडकास्टर्स तथा चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच आपसी वार्ता द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए तथा प्राधिकरण की ओर से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। (सिटी केबल)

8. केबल नेटवर्क पर कैरिज शुल्क का विनियमन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इस व्यवसाय में कैरिज का प्रवेश टीआरपी के लिए हुआ है। कंटेंट कैरियर/ब्राडकास्टर प्लेसमेंट शुल्क अदा करने के लिए सहमत हो गए हैं ताकि उन्हें अच्छी टीआरपी मिले, जिसके बदले में उन्हें अच्छे विज्ञापन मिलेंगे। वे केबल ऑपरेटरों को प्लेसमेंट शुल्क अपने विज्ञापन हिस्से में से ही अदा कर रहे हैं और यदि चैनलों पर विज्ञापन दिखाने पर कोई रोक नहीं लगती तो यही स्थिति उनके द्वारा अदा किए जाने वाले हिस्से पर भी लागू होगी। यदि वे चैनलों पर या फ्री टु एयर चैनलों पर विज्ञापनों के लिए नियंत्रण लगाया जाता है तो वे एमएसओ या केबल ऑपरेटरों को कैरिज शुल्क अदा नहीं करेंगे क्योंकि प्लेसमेंट शुल्क अदा करने का कोई आधार नहीं होगा। यदि ब्राडकास्टर अपने नेटवर्क पर केबल नेटवर्कों की अच्छी फ्रीक्वेंसी के कारण अधिक विज्ञापन प्राप्त करते हैं तो केबल ऑपरेटरों को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वे उनके राजस्व से अपने हिस्से की मांग करें। आज स्थिति यह है कि केबल ऑपरेटर बिना कुछ प्राप्त किए (अर्थात् एमआरपी पर लाभ, एमएसओ बिल, एमआपी पर संग्रहण तथा भुगतान) ब्राडकास्टर्स को अपने नेटवर्क का प्रयोग करने की अनुमति दे रहे हैं।

9. जी नहीं। कैरिज शुल्क का किसी भी प्रकार का विनियमन विवादों में वृद्धि ही करेगा। कैरिज शुल्क समझौते का विषय है तथा इसे बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए अन्यथा पारदर्शिता में कमी आएगी/बुराईयों/कदाचार को बढ़ावा मिलेगा। (हैथवे)
10. केबल नेटवर्क पर कैरिज शुल्क का विनियमन नहीं किया जा सकता चूंकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इस व्यवसाय में कैरिज का प्रवेश टीआरपी के लिए हुआ है। केबल नेटवर्क पर कैरिज शुल्क का विनियमन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इस व्यवसाय में कैरिज का प्रवेश टीआरपी के लिए हुआ है। कंटेंट कैरियर/ब्राडकास्टर प्लेसमेंट शुल्क अदा करने के लिए सहमत हो गए हैं ताकि उन्हें अच्छी टीआरपी मिले, जिसके बदले में उन्हें अच्छे विज्ञापन मिलेंगे। वे केबल ऑपरेटरों को प्लेसमेंट शुल्क अपने विज्ञापन हिस्से में से ही अदा कर रहे हैं और यदि चैनलों पर विज्ञापन दिखाने पर कोई रोक नहीं लगती तो यही स्थिति उनके द्वारा अदा किए जाने वाले हिस्से पर भी लागू होगी। यदि वे चैनलों पर या फ्री टु एयर चैनलों पर विज्ञापनों के लिए नियंत्रण लगाया जाता है तो वे एमएसओ से या केबल ऑपरेटरों को कैरिज शुल्क अदा नहीं करेंगे क्योंकि प्लेसमेंट शुल्क अदा करने का कोई आधार नहीं होगा। यदि ब्राडकास्टर अपने नेटवर्क पर केबल नेटवर्कों की अच्छी फ्रीक्वेंसी के कारण अधिक विज्ञापन प्राप्त करते हैं तो केबल ऑपरेटरों को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वे उनके राजस्व से अपने हिस्से की मांग करें। आज स्थिति यह है कि केबल ऑपरेटर बिना कुछ प्राप्त किए (अर्थात् एमआरपी पर लाभ, एमएसओ बिल, एमआपी पर संग्रहण तथा भुगतान) ब्राडकास्टरों को अपने नेटवर्क का प्रयोग करने की अनुमति दे रहे हैं। (कोफी)

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2006

F. No. 6-4/2006-B & CS.—In exercise of the powers conferred by Section 36, and sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of Sub-section (1) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with the Notifications No. 39 [No. S.O. 44(E) and 45(E)] dated 9-1-2004 issued from File No. 13-1/2004-Restg. by the Government of India under clause (d) of Sub-section (1) of Section 11 and proviso to clause (k) of Sub-section (1) of Section 2 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby amends the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004 (13 of 2004) (hereinafter called the "Principal Regulation"), as follows, namely :—

1. Short title and commencement:

- (i) This regulation shall be called "The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Third Amendment) Regulation, 2006" (10 of 2006).
- (ii) This regulation shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 2 of the Principal Regulation, after sub-clause (n), the following new sub-clauses and the entries relating thereto shall be inserted as sub-clauses (o) to (r), namely :-

- "(o) **"RIO"** means the Reference Interconnect Offer published by a Party, prescribing conditions by fulfilling which other Parties would be entitled to obtain interconnection from that party;
- (p) **"subscriber base"** means the number of subscribers -
 - (i) as agreed to by two service providers in a non-addressable system on the basis of which payments are made by one service provider to the other, or
 - (ii) as reflected by the Subscriber Management System, where addressable systems are employed.
- (q) **"subscriber line report"** or **"SLR"** means a monthly statement wherein, in a non-addressable system, a multi system operator and a cable operator agree upon the subscriber base for that month.
- (r) **"subscriber management system"** or **"SMS"** means a system or device which, in an addressable system, stores the subscriber records and details with respect to name, address, etc. as well as information regarding the hardware being utilized by the subscriber, channels /bouquets of channels subscribed to by the subscriber, price of such channels or bouquets of channels as defined in the system, the activation / deactivation dates and time for any channel or bouquet of channels, a log of all actions performed on a subscriber's record, invoices raised on each subscriber and the amounts paid by the subscriber for each billing period."

3. In clause 3 of the Principal Regulation -

- (a) after the second proviso to sub-clause 3.2, the following explanation and the entries relating thereto shall be inserted:-
"Explanation

The applicant distributors of TV channels intending to get signal feed from any multi-system operator other than the presently-affiliated multi system operator, or from any agent/ any other intermediary of the broadcaster/multi system operator, or directly from broadcasters shall produce along with their request for services, a copy of the latest monthly invoice showing the dues, if any, from the presently-affiliated multi system operator, or from any agent/ any other intermediary of the broadcaster/multi system operator who collects the payment for providing TV channel signals."

- (b) after sub-clause 3.2 and the entries relating thereto, the following new sub-clause and the entries relating thereto shall be inserted as sub-clause 3.3, namely:-

“3.3 Any broadcaster/multi system operator or any agent/ any other intermediary of the broadcaster/multi system operator, who collects the payment for providing TV channel signals to any distributor of TV channels, shall issue monthly invoices to the distributor of TV channels. The monthly invoice shall clearly specify the arrears and current dues along with the due date for payment of the same.

Explanation

Any claim for arrears should be accompanied by proof of service of invoices for the period to which the arrears pertain.”

- (c) the existing clause 3.3 and the entries relating thereto shall be renumbered as clause 3.4 and the existing clause 3.4 and the entries relating thereto shall be deleted.
- (d) after sub-clause 3.4, the following new sub-clause and the entries relating thereto shall be inserted as sub-clause 3.5, namely:-

“3.5 Any broadcaster/multi system operator or any agent/ any other intermediary of the broadcaster/multi system operator to whom a request for providing TV channel signals is made, should either provide the signals on mutually agreed terms to the distributor of TV channels who is seeking signals, or specify the terms and conditions on which they are willing to provide TV channel signals, in a reasonable time period but not exceeding sixty days from the date of the request. In case, the broadcaster/multi system operator or any agent/ any other intermediary of the broadcaster/multi system operator to whom a request for providing TV channel signals is made, turns down the request for TV channel signals, the reasons for such refusal must also be conveyed within sixty days from the date of the request for providing TV channel signals so as to enable the distributor of TV channels to agitate the matter at the appropriate forum.

Explanation

The time limit of sixty days shall also include time taken by the broadcaster to refer the distributor of TV channels, who has made a request for signals, to its agent or intermediary and vice versa.”

- (e) the existing sub-clause 3.5 and the entries relating thereto shall be renumbered as sub-clause 3.6 and the existing sub-clause 3.6 and the entries relating thereto shall be deleted.
- (f) In the re-numbered sub-clause 3.6, the existing explanation and the entries relating thereto shall be substituted by the following explanation and the entries relating thereto, namely: -

“Explanation

“Similarly based distributor of TV channels” means distributors of TV channels operating under similar conditions. The analysis of whether distributors of TV channels are similarly based includes consideration of, but is not limited to, such factors as whether distributors of TV channels operate within a geographical region and neighbourhood, have roughly the same number of subscribers, purchase a similar service, use the same distribution technology.

For the removal of doubts, it is further clarified that the distributors of TV channels using addressable systems including DTH, IPTV and such like cannot be said to be similarly based vis-à-vis distributors of TV channels using non addressable systems. ”

- 4 In the Principal Regulation, in place of the existing clause 4 and the entries relating thereto, the following clause and the entries relating thereto shall be substituted, namely:-

“4. Disconnection of TV channel signals

4.1 No broadcaster or multi system operator shall disconnect the TV channel signals to a distributor of TV channels without giving three weeks notice to the distributor clearly giving the reasons for the proposed action.

Provided that a notice would also be required before disconnection of signals to a distributor of TV channels if there was an agreement, written or oral, permitting the distribution of the broadcasting service, which has expired due to efflux of time.

Provided further that no notice would be required if there is no agreement, written or oral, permitting the distribution of the signals.

4.2 No distributor of TV channels shall disconnect the re-transmission of any TV channel without giving three weeks notice to the broadcaster or multi system operator clearly giving the reasons for the proposed action.

4.3 A broadcaster/ multi system operator/ distributor of TV channels shall inform the consumers about such dispute to enable them to protect their interests. Accordingly, the notice to disconnect signals shall also be given in two local newspapers out of which at least one notice shall be given in local language in a newspaper which is published in the local language, in case the distributor of TV channels is operating in one district and in two national newspapers in case the distributor of TV channels is providing services in more than one district. The period of three weeks mentioned in sub-clauses 4.1 and 4.2 of this regulation shall start from the date of publication of the notice in the newspapers or the date of service of the notice on the service provider, whichever is later.

Explanation

1. *In case the notice is published in two newspapers on different dates then the period of three weeks shall start from the latter of the two dates.*

2. *Broadcaster/multi system operator/ distributor of TV channels may also inform the consumers through scrolls on the concerned channel(s). However, issue of notice in newspapers shall be compulsory.*

4.4 The notice in the newspapers must give the reasons in brief for the disconnection."

5. In the Principal Regulation, as amended from time to time, the existing clause 7 and the entries relating thereto shall be renumbered as clause 14.
6. After clause 6 of the Principal Regulation as amended from time to time and the entries relating thereto, the following new clauses and the entries relating thereto shall be inserted as clauses 7 to 13, respectively, namely:-

"7. Conversion of a Free To Air channel/ Pay Channel

7.1 The nature of any channel, i.e., Free To Air or Pay will normally remain the same for a period of one year. Any broadcaster of a Free To Air channel intending to convert the channel into a Pay Channel or any broadcaster of a Pay channel intending to convert the channel into a Free To Air channel shall inform the Authority and give public notice in the manner specified in clause 4.3, one month before the scheduled date of conversion.

8. Time Period for Renewal of existing agreements

8.1 Parties to an interconnection agreement for supply of TV channel signals shall begin the process of negotiations for renewal of existing agreement at least two months before the due date of expiry of the existing agreement.

Provided that if the negotiations for renewal of the interconnection agreement continue beyond the due date of expiry of the existing agreement then the terms and conditions of the existing agreement shall continue to apply till a new agreement is reached or for the next three months from the date of expiry of the original agreement, whichever is earlier. However, once the parties reach an agreement, the new commercial terms shall become applicable from the date of expiry of the original agreement.

Provided further that if the parties are not able to arrive at a mutually acceptable new agreement, then any party may disconnect the retransmission of TV channel signals at any time after the expiry of the original agreement after giving a three weeks notice in the manner specified in clause 4.3. The commercial terms of the original agreement shall apply till the date of disconnection of signals.

9. Finalising Subscriber Base at the time of first agreement

First agreement between Multi System Operator and Cable Operator

9.1 In non-addressable systems, while executing an interconnection agreement for the first time between a multi system operator and a cable operator, the parties to

the agreement shall take into account the subscriber base of the cable operator on the basis of the Subscriber Line Report (SLR) where such SLR exists. Where such SLR does not exist, this shall be negotiated on the basis of the evidence provided by the two parties on the subscriber base, including the subscriber base of similarly placed cable operators and local survey.

Explanation

The Subscriber Line Report (SLR) is only an indicative basis for arriving at the subscriber base and the subscriber base as mutually agreed by the two parties could be more than or less than the number indicated by the SLR.

First agreement between Multi System Operator and Broadcaster

9.2 In non-addressable systems, while executing an interconnection agreement for the first time between a multi system operator and a broadcaster, the multi system operator shall furnish a list of the cable operators who will be getting signals from its network along with their subscriber base. The parties to the agreement shall take into account the subscriber base of cable operators connected to the multi system operator while negotiating the subscriber base of the multi system operator. For the consumers proposed to be directly served by the multi system operator, the procedure as laid down in sub-clause 9.1 of this regulation shall be followed.

10. Variation of Subscriber Base during validity of agreement

Between Multi System Operator and Cable Operator

10.1 In non-addressable systems, the subscriber base agreed upon by the parties at the time of execution of the interconnection agreement between a multi system operator and a cable operator shall remain fixed during the course of the agreement except in exceptional circumstances that warrant an increase or decrease in the subscriber base. In such an eventuality, it is for the service provider seeking a change in the subscriber base to provide reasons and accompanying evidence including local survey for the proposed change.

Between Multi System Operator and Broadcaster

10.2 In non-addressable systems, the subscriber base agreed upon by the parties at the time of execution of the interconnection agreement between a multi system operator and a broadcaster shall remain fixed during the course of the agreement except in exceptional circumstances that warrant an increase or decrease in the subscriber base. In such an eventuality, it is for the service provider seeking a change in the subscriber base to provide reasons and accompanying evidence including local survey for the proposed change.

Provided that this sub-clause shall not apply to changes in the subscriber base of a multi system operator on account of any cable operator joining or leaving the multi system operator.

Provided further that any change in the subscriber base of a multi system operator, which is the basis of payment to a broadcaster, on account of any cable operator joining or leaving the network of the multi system operator shall be equal to the subscriber base of the cable operator, joining or leaving the network.

11. Finalising Subscriber Base at the time of Renewal of agreement**Between Multi System Operator and Cable Operator**

11.1 In non-addressable systems, negotiations on revision of subscriber base at the time of renewal of interconnection agreement between a multi system operator and a cable operator shall take into account the changes in subscriber base of the cable operator over the past three years, as well as the changes in subscriber base of other cable operators operating in the area in which the cable operator is operating and its adjoining areas for the current period.

Between Multi System Operator and Broadcaster

11.2 In non-addressable systems, negotiations on revision of subscriber base at the time of renewal of interconnection agreement between a multi system operator and a broadcaster shall take into account the changes in subscriber base of the multi system operator over the past three years, as well as the changes in subscriber base of other multi system operators operating in the area in which the multi system operator is operating and its adjoining areas for the current period.

12. Monthly Subscriber Base Statement

12.1 In non-addressable systems, the multi system operators shall furnish the updated list of cable operators along with their subscriber base to the broadcasters on a monthly basis.

13. Reference Interconnect Offer

13.1 All broadcasters shall submit within 90 days of issue of this Regulation, copies of their Reference Interconnect Offers (RIO) describing, inter-alia, the technical and commercial conditions for interconnection for non-addressable systems to the Authority. The same shall be published by the broadcasters and a copy shall also be put up on their websites after the terms and conditions of the draft reference interconnect offer are submitted to the Authority. The reference interconnect offer so published by the broadcaster shall form the basis for all interconnection agreements to be executed thereafter.

13.2 A published reference interconnect offer may undergo any change only after prior intimation to the Authority. Interconnection agreements shall be entered into by all broadcasters based on the reference interconnect offers so published, provided, however, that by mutual agreement, the parties concerned may modify and/or add to the terms and conditions stipulated in the published reference interconnect offer for entering into an individualised agreement.

13.3 The Authority may intervene at any stage to direct amendment or deletion of any clauses of the Reference Interconnect Offers, if the clauses are found to be in violation of the law, regulations, directions or orders."

7. This regulation contains at Annex A, an Explanatory Memorandum containing the reasons for amendments to the Principal Regulation.

By Order,

RAKESH KACKER, Advisor (B & CS-I)

[ADVT.-III/IV/142/2006/Ext.]

Annex A**Explanatory Memorandum**

1. The distribution of cable TV in India was unregulated since its inception in early 1990s. This was sought to be regulated by TRAI by issue of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation 2004 (13 of 2004). This Regulation was issued on 10.12.2004, i.e. more than one and a half years ago. Some new issues have cropped up during this period. The experience of this period has shown that some issues relating to the Interconnect Regulations require clarification. Some disputes and litigation have also arisen on account of implementation of Interconnect Regulations. Thus a need was felt to clarify as well as expand the scope of Interconnect Regulations so as to minimize the doubts and disputes/ litigation.

Disconnection of TV channel signals

2. The two notice periods prescribed in the regulation led to a number of disputes regarding the notice period applicable in specific cases. By having a single notice period, these disputes can be avoided. Moreover, there would be no advantage by way of a shorter notice period, in suppressing the true reasons for issue of notice to disconnect signals and the consumers would get to know the real issues in the dispute. The notice period should be sufficient for the affected parties to be able to approach the appropriate forum to plead for intervention and to give the consumers an opportunity to approach the necessary forum to ensure that their interests do not suffer on account of the dispute. At the same time, no notice need be provided in the cases of theft of signals as is already the case.

3. Moreover, the interests of consumers as well as the broadcaster/ multi system operator also get adversely affected if the distributor of TV channels decides to switch off signals of a particular channel due to some dispute with the broadcaster/ multi system operator. Accordingly, to protect their interests it is necessary that they get similar advance notice regarding discontinuation of TV channel signals. Therefore, the requirement of giving advance notice to disconnect signals has been extended to the distributors of TV channels also.

4. The purpose of having a public notice is to give the consumers an opportunity to approach the necessary forum to ensure that their interests do not suffer on account of a dispute to which they have not contributed in any way. However, the very purpose gets defeated if the public notice is not issued at the time of giving notice to the service provider and is issued much later leaving very little time for consumers to agitate the matter at appropriate forum. Accordingly, it is necessary that the consumers get the notice before the notice period begins. Considering the fact that cable TV has reached even remote parts of the country, the notice period should be sufficient to enable the affected parties to approach the appropriate forum.

5. The reach of vernacular language newspapers in the country is more than the reach of English language newspapers. To have the maximum coverage, it is necessary that the public notice should be published in the local language in a local language newspaper also.

6. The notice to the service provider concerned should clearly inform the service provider about the reasons for proposed disconnection. The notice should specify the terms & conditions of the agreement which have been allegedly violated and the details of such violation rather than cryptically mentioning violation of the agreement as the reason for issue of the notice. This is necessary so as to pin point the issues of dispute, so that the affected service provider can take steps either for rectifying the violation or to approach appropriate forum for redressal. Similarly, the public notice should also have the reasons for proposed disconnection in brief.

Access to content

7. The purpose of laying down a time limit for responding to a request for signals gets defeated if the distributor of TV channels making a request for signals is referred by the broadcaster/ multi system operator to its agent/ intermediary or vice versa just before the expiry of the time limit and the time limit starts afresh. Moreover, it is easy for a service provider to respond to the request before the expiry of the time limit by asking for some details and then prolong the process by asking for supplementary details. Hence, it is necessary to lay down a time limit wherein either the signals are provided to the distributor of TV channels or the specific terms & conditions are informed on fulfillment of which the signals are to be provided.

Multi System Operator as an agent of the broadcaster

8. The TDSAT judgment in the case of Sea TV Network Ltd. has been challenged before the Hon'ble Supreme Court of India. Therefore, it would not be appropriate for the Authority to make any regulation in this regard. Thus, whether the Regulations should specifically prohibit appointment of an MSO, directly or indirectly, as an agent of a broadcaster and related issues will be covered by the eventual decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter. Therefore, the Authority has decided not to proceed further in this regard and to wait for the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the matter, which shall be binding on all concerned.

Default in payments

9. Sometimes LCOs switch from their affiliated MSO when they are either unable or unwilling to pay their outstanding dues to their affiliated MSO. This results in bad debts for their affiliated MSOs leading to the latter's inability to pay broadcasters for the LCOs portion of dues. Broadcasters are also unable to recover these dues from the MSO to whom such defaulting LCO gets affiliated. On the other hand, in the absence of regular issue of invoices, the LCOs are suddenly confronted with huge arrears, which they have

no means of paying. The problem can be tackled by ensuring that the LCOs are issued invoices on a monthly basis clearly showing the arrears as well as the current dues. In such a situation, if an LCO wants to switch to a new MSO, then the latest invoice would clearly show the level of arrears outstanding against the LCO. At the same time this will protect the LCO from unexpected and unforeseen arrears being suddenly thrust upon him.

Area of operation and Subscriber base

10. The term subscriber base is rather vague in the absence of addressability, as it is impossible to know the real number of subscribers being served by a service provider in non-CAS areas. Thus, it is not possible to have agreements based on the actual subscriber base. Hence, the negotiations for fixation of subscriber base for an interconnect agreement depend crucially on area proposed to be served by the distributor of TV channels. However, the actual number of subscribers is reflected by the Subscriber Management System (SMS) wherever addressable systems are deployed. Thus, the subscriber base in such a situation is accurately reflected by the SMS.

As mentioned in para 8 above, the TDSAT judgment in the case of Sea TV Network Ltd. has been challenged before the Supreme Court of India and the matter regarding determination of subscriber base of cable operators and MSOs has been raised in the appeal before the Supreme Court. However, the Supreme Court vide its interim order dated 2.3.2006 had specifically permitted the Authority to proceed with its exercise on devising a system for ascertaining the subscriber base of distributors of TV channels. The Supreme Court had observed that:-

"... Further, pendency of these matters shall not stand on the way of the Central Government if it so chooses, to implement the CAS or of the TRAI in devising any system to identify and arrive at the correct number of subscribers of each distributor of TV channels.... "

In view of this observation of the Hon'ble Supreme Court the Authority has proceeded to lay down a system to identify and arrive at the correct number of subscribers of each distributor of TV channels.

The Authority had recognized in its recommendations on issues relating to Broadcasting and Distribution of TV channels dated 1.10.2004 that a gradual transition to addressability is a must and that it cannot be done immediately throughout the country. In these recommendations, the Authority had recommended mandating a register of subscribers to be maintained by the cable operators and multi system operators. The Authority had recommended that:-

"...All cable operators and multi system operators shall maintain a register of subscribers containing the names of the subscriber, address, monthly fee charged and number of channels received. The register shall be furnished for inspection to the Authorised Officer whenever he considers it expedient to inspect such register to find out if there has been a violation of any regulation..."

In the absence of addressability and register of subscribers, it is very difficult to ascertain the number of subscribers of a distributor of TV channels. In spite of this limitation, the Authority has provided a methodology to arrive at the subscriber base of each distributor of TV channels.

11. The primary reason for disputes arising on account of expansion of area is that without addressability, it is impossible to know the actual subscriber base and area is the basis on which a subscriber base is arrived at. Any change in area of operation has direct bearing on the negotiations with respect to subscriber base. However, the expansion of area by a multi system operator on account of giving feed to a cable operator operating outside the existing area of operation of the multi system operator can be taken care of by negotiations based on the Subscriber Line Report (SLR). Similarly, the expansion of area of operation by a cable operator will also get reflected through the Subscriber Line Report (SLR).

Multi System Operator

12. The disputes regarding insistence of distributors of TV channels with very small subscriber base on getting signals directly from the broadcasters can be reduced by laying down a minimum subscriber base on the basis of area of operation of the distributor of TV channels, below which an operator will not be able to get signals directly from the broadcasters. However, this figure can be notified only after detailed analysis of city-wise data for different broadcasters regarding number of subscribers being served by the multi system operators with the smallest subscriber base in different parts of the country. For the present, laying down such a figure has not been found feasible by the Authority. The same may be laid down at a later date, if found feasible, by the Authority after analysis of relevant data.

Renewal of agreements

13. Renewal of agreements is smooth in most of the cases, but the problems arise when the negotiations for renewal extend beyond the date of expiry of the original agreement. To govern the terms and conditions for continuation of signals beyond the expiry date of the original agreement, the original agreement can be extended till an agreement is reached regarding the terms and conditions for renewal. However, it must be recognized that the new commercial terms will apply retrospectively from the date of expiry of the original agreement. If however, no agreement is reached, then either party can disconnect the signals after giving the statutory notice as provided in Regulation 4 of these regulations. The terms and conditions of original agreement would govern the relationship between the two parties till the date of disconnection of signals. It is believed that the parties should be able to reach a new agreement within three months of expiry of the old agreement (after five months of negotiations). However, in case negotiations carry on beyond this period, then some new interim arrangement regarding terms and conditions should be worked out between the parties and terms and conditions of the old agreement would not get automatically extended beyond this period.

Conversion to Pay/ Free To Air

14. The nature of any channel, i.e., Free To Air or Pay should not change very frequently and should normally remain the same for a period of one year. The broadcasters intending to convert their Free To Air Channels into Pay channels and vice versa should give advance notice to the Authority as well as to the general public. This would be important in the context of CAS areas as the multi system operators will have to make necessary changes in their Subscriber Management Systems. In the context of non-CAS areas it would inform the consumers about likely changes in their payout for cable services and possible non-availability of the channel.

Reference Interconnect Offer

15. There have been demands from different quarters regarding introduction of a regulation on Reference Interconnect Offer on the lines of "The Telecommunication Interconnection (Reference Interconnect Offer) Regulation dated 12th July 2002." This gives the flexibility to the broadcasters to draft the Reference Interconnect Offer in such a way so as to take care of their concerns. The provision for possible intervention by the Authority will ensure that the Reference Interconnect Offer does not contravene any statute. This will lead to a reduction in litigation about the way the standard agreements are drafted by the broadcasters. Service providers can by mutual agreement deviate from the provisions of such an RIO. This is intended to give flexibility to the service providers to take into account the special commercial circumstances that may exist in a particular area or agreement. It is also desirable to have similar RIOs for MSOs. However given the large number of such MSOs, it is not practically feasible for the Authority to undertake this exercise.

Monopoly in the last mile

16. The issue of monopoly in the last mile is likely to be addressed to a certain extent by increased competition due to new platforms such as DTH and IPTV. Two DTH service providers are already providing their services, and the roll out of IPTV services in the country is also expected in the near future. Therefore, for the present, the Authority has decided to watch the progress of competition from the new platforms and intervene at a later stage, if found necessary.

Carriage fee regulation

17. Regulation of carriage fees has been opposed by all the multi system operators as well as the Cable Operators Federation of India. It has been suggested that such regulation would lead to multiplicity of disputes. Regulation of carriage fee in the present circumstances is very difficult as it also implies regulation of positioning. In different parts of the country, there are different viewership patterns. The capacities of cable networks also vary a great deal. Thus, the levels of carriage fee are different in different parts of the country depending upon demand and supply gap.

Presently, there are more than 6000 multi system operators, which follow different systems of accounting. Payment of carriage fee is very often done in cash or in kind. Thus, it is not possible to find out the actual payments being made towards carriage fees. The carriage fee is a temporary phenomenon and is likely to disappear with the advent of digital cable systems.

The issue of carriage fee was also examined by the Authority in its recommendations on issues relating to Broadcasting and Distribution of TV channels on 1.10.2004. The Authority had observed that:-

"6.5 On the issue of 'Must Carry of TV Channels' the existing scenario of capacity constraint in carrying signals in analogue mode and its consequences of competition for space on the Cable Spectrum has been kept in view. Since digitalisation is a long-term goal, no fresh regulation on 'Must Carry Obligations' is proposed apart from the ones already there in the Cable Act and Rules. As and when capacity is augmented the 'must carry' regulation will be introduced. For the present therefore there will be no regulation on carriage charges."

In its recommendations on Digitalisation of Cable Television dated September 14, 2005, the Authority had recommended that licencing should be introduced for offering of digital services after a cut-off date. It was also recommended that the licences for digital service should have only a provision for non-discriminatory carriage of channels on the basis of the existing DTH licence conditions which require that the licensee shall provide access to various content providers/channels on a non discriminatory basis.

Consultation on draft Regulation

18. The Authority began its process of examination of the relevant issues by issuing a Consultation Note on 21.3.2006 so as to have the necessary document for discussing them. Thereafter a Consultation Paper was formulated after taking into account the comments and other inputs provided by the stakeholders on the consultation note dated 21.3.2006. Issues relating to the Register of Interconnect Agreements (Broadcasting and Cable Services) Regulation 2004, dated 31.12.2004 were also included. This consultation paper was released on May 11, 2006. A number of comments have been received and these have been carefully analysed. Since the number of comments is very large, the gist of the comments have been briefly summarized, section by section in the Annexe to this Explanatory Memorandum. Open House Discussions were also held in Mumbai on June 16, 2006 and in Delhi on June 19, 2006. All these comments as well as the comments made during the course of the Open House Discussions have been carefully considered before coming to the conclusions as reflected in the amendments to the Regulations.

Annexe to Explanatory Memorandum on "The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Third Amendment) Regulation, 2006".

Gist of comments received on the consultation paper on interconnection issues relating to broadcasting and cable services.

INDEX OF STAKEHOLDERS FURNISHING COMMENTS

Sl.No.	Name	From where
1	Col V C Khare (Retd) - Cable TV Industry Observer	Mumbai
2	Star India Pvt. Ltd. (Star)	New Delhi
3	US India Business Council (USIBC)	Washington, USA
4	Motion Picture Association (MPA)	Singapore
5	ESPN Software India Pvt. Ltd. (ESPN)	Gurgaon, Haryana
6	Ortel Communications Ltd. (Ortel)	Orissa
7	Shri Alok Sahal, B.N.B. Cables (B.N.B. Cables)	Kolkata
8	ASC Enterprises Ltd (ASC)	Noida
9	Siti Cable Network Limited (Siti Cable)	New Delhi
10	Indusind Media & Communications Ltd. (IMCL)	Mumbai
11	Hathway Cable & Datacom Pvt. Ltd. (Hathway)	Mumbai
12	Cable Operators Federation of India (COFI)	New Delhi

Issue for Consultation

Amendment of Existing Regulations

Two Notice Periods

- Whether there should be only one notice period for the notice to be given to a distributor of TV channels prior to disconnection of signals?
- If yes, what should be the notice period and whether this should apply to unauthorized retransmission/ piracy cases also?
- If not, what changes should be made in the regulation to avoid disputes as to which notice period is applicable? In particular, how should unauthorized distribution be defined?

Comments Received

1. Notice period should be only one and such notices should be scrolled on news channels of the broadcasters, besides the Distributors scrolling on their networks. Unauthorized retransmission/piracy, if detected should be litigated under IPC because it can never be with consent of authorized distributor. If there be only one notice period, disputes will not arise. If signal is detected in networks not belonging to network of distributor, the distribution shall be deemed to be un-authorized. (Col V C Khare (Retd) - Cable TV Industry Observer)

2. There should be one notice period only for authorized distributor of TV channels. The notice period for disconnection of signals of authorized distributor of TV channels (including on account of payment defaults) should be one week. The unauthorized distributor of TV channels should not be given any prior notice for disconnection and their signals should be disconnected forthwith without any notice. It is suggested that 'unauthorized distributor of TV channels' be defined and Clause 4.1 of the Regulation be amended as "unauthorized distributor of TV channels" means any distributor of TV channels, which has failed to renew agreement, as per TRAI regulations, and/or undertakes/abets any of the following such as extend beyond area of operation provided in the agreement; connect new operators (other than the operators specified in the agreement) without prior written authorization; block, modify or tamper with the signals or add an overlay on the feed; tape and/or reproduce content without prior written consent; and remove IRDs from the installation address without prior written consent. Clause 4.1 of the Regulations be amended as "No broadcaster or multi system operator shall disconnect the TV channel signals to a distributor of TV channels without giving one week's notice indicating brief reasons for the proposed action. Provided that unauthorized distributor of TV channels may be disconnected forthwith without notice". Assuming the TRAI is not keen to change the notice periods, it is suggested that the definition of 'unauthorized distributor of TV channels' (as above) be incorporated and Clause 4.1 of the Regulations be amended as "No broadcaster or multi system operator shall disconnect the TV channel signals to a distributor of TV channels without giving

one month notice indicating brief reasons for the proposed action. Provided that in case of unauthorized distributor of TV channels, the notice period shall be two working days giving reasons to the unauthorized distributor of TV channels for such action". (Star)

3. Any discussion of notice periods for disconnection of signals should be applicable only with regard to authorized distributors of TV channels. TRAI should further clarify its definition of 'unauthorized distributor of TV Channels' to capture the various ways in which signals are obtained and put to use without authorization. For authorized distributors of TV Channels for which termination of the distribution agreement is sought, the notice period should be a contractual matter between the broadcaster and the operator. Consistent with the norms in other markets around the world, TRAI should consider a less intrusive regulatory path. (USIBC)

4. The present scheme envisages a 30-day notice period. However broadcasters create content at a cost, broadcast their signals at further costs and provide the signal to the cable operator. The Cable operator's payment obligation starts 30 days after they begin to receive the signals on the 1st of the month. Thus they already have a 30 - day notice as part of the existing contractual arrangement. Given this, the notice period needs to be reviewed. There should be a different notice period in proposed CAS Areas and for non-CAS areas as the environments are addressable and non-addressable respectively. (MPA)

5. The changes required to be made in the regulation to avoid disputes can be; (a) any oral agreements between the parties should be discouraged; (b) No notice should be required to be served to the cable operators/ MSOs promoting unauthorized retransmission and (c) For any other dispute, there should be only one notice period which should be defined clearly. (ESPN)

6. Only one notice period should be given prior to the disconnection of signals to the distributor of TV channels. The notice period should be minimum of 30 days and should apply to Unauthorized Retransmission/piracy cases also since the customers would suffer without any fault of theirs if the notice period is of few days as is the case now. (B.N.B. Cables)

7. There needs to be different notice periods for different reasons. Reasons can be attributed to 1) Commercial consideration: Non Payment, out standings etc, distributing the signals in the area or the place they are not intended to like for Public Viewing with an intention to earn entry fee. (in case of a major sporting event) in which case 30 days notice should apply; 2) Piracy of the signals; Redistribution on cable networks, using an unauthorized decoders and 3) Misuse of the equipment provided for decryption of the signals: Use of the card splitters to access more services than the authorized services. The present regulations prescribe a period of one month for disconnection of signals due to commercial reasons while it is 2 days for piracy. The same is appropriate as criminal acts involving piracy cannot be permitted to be going for a month which will lead to high revenue losses as well as undermining of competitive networks such as DTH. An example can be given of using a DTH/IPTV decoder on a cable network. The ease of

mobility in the case of the DTH will make it more susceptible to such cases and DTH service providers can act fast by switching off the decoder over the air within minutes of the piracy being reported. The common technique is the finger printing mechanism. The definition of unauthorized distribution should inter-alia include the use of any cross service devices (such as IPTV or DTH Boxes on a cable Plant); use of any card splitters whereby one decoder is tampered with to deliver multiple channels; connection of signals to any networks outside of the contracted ones without prior confirmation and transport of decoders to any address, area or location other than where they are authorized to operate from. (ASC)

8. The present provisions of giving two Notice periods – one for alleged default in payment and another for piracy should continue. However, 2 days notice as prescribed at present in case of piracy is too short. The notice period in case of alleged piracy should be increased from present two days to minimum 7 days to enable the distributors of channels to seek relief from TDSAT in case of motivated and frivolous notices. The piracy can be defined as: where a distributor of channels is distributing signals from a decoder which is unauthorized i.e. distributor of channels does not have any arrangement with the broadcasters and is not taking the feed from an authorized distributors of channels (MSO/operator) and where a distributor of channels has been switched off by a broadcaster because of some dispute and that distributor of channels continues to distribute signals in his service areas without entering into any arrangement with the broadcaster/ any other MSO. Only in these cases the notice of 7 days should be applicable and in all other cases the notice of 30 days must be given by the broadcasters. Alternatively it should be provided that the notice of piracy should provide clear-cut 2 working days to enable the aggrieved party to seek redressal from TDSAT. The working days in this context should be defined to mean the days on which TDSAT and TRAI function and Saturday, Sunday & public holiday should be specifically excluded. (Siti Cable)

9. There should be only one notice period of 30 days and this should apply to all cases (it should not be confused with 'unauthorized distribution' as no notice is required for such cases). The person/party who has signed an agreement or has made payment to the broadcasters cannot be accused of unauthorized distribution since he is a licensee /authorized distributor of a broadcaster and distribution outside area is a commercial dispute arising out of the agreement for which Dispute Settlement Tribunal (TDSAT) is the final authority. Broadcasters are using commercial disputes on subscriber numbers to get more revenue from MSOs. For such disputes the judgment of Telecom Tribunal should be sought for instead of one sided arbitrary decision taken by broadcasters. Unauthorized distribution should be defined in two parts: (i) if an MSO has been switched off by a broadcaster for his authorized IRDs but he is still transmitting signals of that particular broadcaster through some other MSO/ICO without signing any agreement with either of them and (ii) a person who is distributing signals of broadcasters without having any arrangement either directly from the broadcaster or through any MSO/cable operator.(IMCL)

10. Current regime of two notice periods is fair as there are numerous judgments emanating out of the Interconnection Regulation dated 10th December, 2004. Consistency in any regulation and regime should be maintained to avoid any confusion. Clarification needs to be brought by the Authority on two day's notice period for unauthorised distribution of TV channels. Notice should be two working days excluding the

date of publication in the print / scroll on the TV channels and excluding date which happens to be public holiday / Saturday / Sunday as if any person / entity affected by the act of disconnection / alleged piracy should have a time to defend his position before the Authority / Tribunal. (Hathway)

11. There should be only one notice period of 30 days and this should apply to all cases. For 'unauthorized distribution', no notice should be required if there is no previous business relationship with the party. The person/party who has signed an agreement or has made payment to the broadcasters cannot be accused of unauthorized distribution since he is a licensee/authorized distributor of a broadcaster and distribution outside area is a commercial dispute arising out of the agreement for which Dispute Settlement Tribunal (TDSAT) is the final authority. Commercial disputes on subscriber numbers, asking for arbitrarily enhanced payments and disputes regarding area of operation to get more revenue from the existing affiliate MSOs/Cable Operators by the broadcasters should not be treated as unauthorised distribution. For such disputes the judgment of Telecom Tribunal should be sought for instead of one sided arbitrary decision taken by broadcasters. Unauthorized distribution should be defined in two parts: i) if an MSO has been switched off by a broadcaster for his authorized IRDs but he is still transmitting signals of that particular broadcaster through some other MSO/Cable Operators without signing any agreement with either of them and (ii) a person who is distributing signals of broadcasters without having any arrangement either directly from the broadcaster or through any MSO/cable operator. (COFI)

Issue for Consultation

Notice to disconnect

- **Whether the notice period should be counted from the day of issue of public notice?**
- **Whether the option available to broadcasters/ MSOs to give public notice by running a scroll on the channels should be done away with?**
- **In cases where the Broadcasters have not switched off their channels whether the MSOs and the Cable Operators should be required to give notice to the consumers before switch off of any channel?**

Comments Received

1. Notice should first be served, in writing, upon the distributor, acknowledged and then publicized. In such a case, notice period shall reckon from the date of public notice. The public notice could state the date already acknowledged by the distributor. The option available to broadcasters/MSOs to give public notice by running a scroll on the channels should not be done away with. Warning to viewers on the network, hooked to Headend, must be issued by the Headend operators i.e. MSO/Distributor. [Col V C Khare (Retd) - Cable TV Industry Observer].

2. The notice period should be counted from the day of issue of public notice. The scroll on the channels is an effective way of communicating to the viewing consumer of the intent of the broadcaster. Therefore, it should definitely not be done away with. In fact, it is suggested that the TRAI permit the broadcasters to use the same scroll to provide notice to distributor of TV channels as well as viewing consumers. The notice

period should be applicable not only for broadcasters and/or MSOs, but all entities involved in the distribution of channels to the end consumers, including last mile operators. MSOs and Cable Operators should not be allowed to arbitrarily disconnect signals. In view thereof, it is recommended that the TRAI incorporate a Clause 4.1A of the Regulations as "No distributor of TV channels shall disconnect the TV channel signals from a broadcaster or multi system operator without giving one week notice to the broadcaster and consumers indicating brief reasons for the proposed action." The notice period for switch-off of signals of any channel by the distributor of TV channels should be the same as applicable to the broadcasters/MSOs. Clause 4.2 of the Regulations be amended as "Broadcaster/distributor of TV channels shall inform the consumers about the dispute to enable them to protect their interests. Accordingly, the notice to discontinue signal shall also be given in two local newspapers in case the distributor of TV channels is operating in local area and in two national papers in case the distributor of TV channels is providing services in a wide area. Alternatively, consumers can be informed through scroll on the concerned channel(s). The distributor of TV channels must carry the scroll in the concerned channel(s)". Further, such MSOs and cable operators should then not be entitled to the benefits of the 'Must Provide' regulations, since they are in breach of the regulations issued by the TRAI. (Star)

3. The notice period should simply be counted from the day of issuance of the public notice. Furthermore, there is already a de facto 30 day period built in due to the time lag between the receipt of the signal and the regularly timed payment. Broadcasters should be allowed to continue the practice of offering a scroll. If the cessation of service is not due to criminal responsibility, but rather a business decision to stop delivering a particular channel, such decisions are typically made well in advance of the cancellation of such service, providing for time to notify consumers of a pending change in service. MSOs and cable operators currently disconnect the signals of broadcasters with no notice to either consumers or the broadcasters. Notice periods between broadcasters and operators are best left to contractual agreement, but parity requires that TRAI's regulations be made reciprocal. With regard to a regulated notice period between cable operators and subscribers, there is some justification for regulatory intervention given that the consumer lacks leverage with his last mile service provider to negotiate in this regard. Therefore the requirement that consumers receive notification from MSOs and cable operators prior to the switching off of signals should be there. (USIBC)

4. For all declaration related disputes for the first one month after CAS is introduced in an area the notice period can be 30 days. After the first month, all piracy related disconnection can take effect immediately to prevent further piracy. In case of disconnection for causes not related to piracy, the notice period could be 7 days during which the scroll may be inserted into the signal to warn the consumers of the impending disconnection. The scope of "Unauthorized exhibition" should be well-defined in the contract that a broadcaster enters in to with the MSO/LCO. (MPA)

5. The notice period should be counted from the day of issue of public notice. Notifying the consumers by means of Newspapers (National /Daily) turns out to be an expensive affair and hence, the option available to the broadcasters/MSOs to give public notice by running a scroll on the channels should not be done away with. Rather there should be a period prescribed during which the scrolls can be run on the channel(s). The cable operator/ MSO should not have the right to switch off the channels if the broadcaster is providing the same. This action of the operator/ MSO will hold the

consumer at ransom and should be discouraged at all costs. Also, if there is a “must provide” regulation there should be a “must carry” regulation for the cable operators/MSOs also. (ESPN)

6. Yes the notice period should be counted from the day of public notice. The option of running a scroll should be done away with. The consumers should be informed of any kind of switch off be it from the Broadcasters or the MSOs or the cable operators since this act is formulated with a view to protect the interests of the consumers. (B.N.B. Cables)

7. Ideally speaking the notice period should start from the day service provider in writing informs the user, and the public notice should be mandated to be brought in within seven days of the issuance of the notice to the user. Running of scrolls on channels is an avoidable nuisance. The decoders used should have a forced messaging capability with addressability so that only a particular operator is warned of the impending disconnection. Even inexpensive decoders now support such addressable messaging and it is strongly recommended to the Authority to do away with stock tickers and making forced messaging which is displayed on the screens in a particular area a mandatory feature. In case the MSO or the Cable operator or any service provider wishes to switch off any service on his own, he should give the notice to the subscribers before switching off. It is fair to the Broadcaster or the Service provider that he is aware that his services will not be available to a particular section of the consumers in an area and it can make alternative arrangement for the delivery of the services in the area either through a different platform or by different technology. (ASC)

8. Notice period should be counted from the date of the issuance of the public notice in the newspapers. The broadcaster should not have the option to give public notice by running scroll on the channel and it should be mandated that the notice for proposed disconnection should be given through newspaper only. It is not possible for the MSO and the Cable Operators to give advance notice to consumers before switching off any channel because with more than 100 channels being delivered by most of the operators now and with increasing pressure on the capacity of the networks with launch of new channels there is bound to be some shuffling of channels or else no new channels will ever get distributed. Also an MSO might be forced to shut off a channel for technical reasons as well such as bad audio or video quality etc. (Siti Cable)

9. Notice period from the date it appears in papers or received by MSO/service provider. It is alright to give public notices by running scroll on channels as otherwise broadcasters use some obscure newspaper to advertise which not many subscribers read in the network (though on the other side once such advertisements are placed, it is defamatory for the MSO/cable operator and subscriber creates a problem while paying their dues). MSOs and cable operators are required to inform the consumers before they switch off any of channels and this can be a part of an agreement between the stakeholders i.e. the notice period and information. In other words, if a consumer needs to be informed then MSOs can put a scroll on the network informing in advance of change before 3 days and if any MSO wants to switch off any broadcaster forever then 30 days. If broadcaster gives notice to any MSO of 30 days, invariably in most of the cases, whether the intervention of TDSAT is sought or the matter is settled between the parties, in that case giving such notices on scroll or in papers becomes meaningless. The viewer should be informed of any broadcaster going off on any network if the above remedies have been exhausted for i.e. there is no relief from TDSAT and the talks have failed between the parties. (IMCL)

10. The notice period should exclude the date of issue of public notice and should also exclude likely date of disconnection / deactivation of signals. The option available to broadcasters/ MSOs to give public notice by running a scroll on the channels should not be done away with. MSOs and the Cable Operators should not be required to give notice to the consumers before switching off of any channel. Some times the Broadcasters give notice as a threat only and there is no intention on the part of them to disconnect / deactivate signals, so as to make the MSO's/ LCO's submit to them. (Hathway)

11. Notice period should be counted from the date it appears in papers or received by MSO/Cable Operator. Giving public notice by running scroll on channel should not be done away with as otherwise broadcasters use some obscure newspaper to advertise which not many subscribers read in the network. However, it is felt that such advertisements can be defamatory for the MSO/cable operator as they may give a wrong impression in the minds of the subscribers of that network that their cable operator is not giving his dues to the broadcaster. Whereas in reality it may be a superficial dispute between broadcaster and the cable operator to get more revenues as it happens every day. MSOs and cable operators are required to inform the consumers before they switch off any of channels and this can be a part of an agreement between the stakeholders i.e. the notice period and information. In other words, if a consumer needs to be informed then MSOs can put a scroll on the network informing in advance of change before 7 days and if any MSO wants to switch off any broadcaster forever then 30 days. Generally in such disputes, parties approach TDSAT for redressal before the 30 days period is over so that there is no disruption in the signals. Viewer should be informed of any broadcaster going off on any network if the above remedies have been exhausted for i.e. there is no relief from TDSAT and the talks have failed between the parties. (COFI)

Issue for Consultation

Access to content

- Whether a time limit should be laid down for the agent or any other intermediary of a broadcaster/multi system operator to either provide signals to any distributor of TV channels once a request is made or to decline the request giving reasons for the same so as to enable the distributor of TV channels to agitate the matter at the appropriate forum without loss of time?
- Whether the time limit should also include time taken by the broadcaster to refer the distributor of TV channels who has made a request for signals to its agent or intermediary?
- Whether the provisions for mandatory access and the non exclusivity requirement in the Interconnect Regulation be removed so that there is no mandatory requirement for channels that are provided to only a digital platform/ service to be made available to any other digital platform / service or on the cable platform?
- Alternatively should these requirements be applied only to channels that have entered the market before a particular date?

Comments Received

1. This situation is fallout of non-existence of Broadcasting Law and the precedence of hithertofore uplinks of offshore satellite content. A procedure to curb anti-

competitive practices has to be evolved, wherein reasons for not complying with the request must be communicated in writing, within a stipulated time, so that the applicant may agitate the matter to the appropriate forum. In the present state of speedy telecommunications (telephony, E-mail, FAX and so on) time limit fixed should include the time for the agent of the broadcaster to communicate with their principal. One possible solution could be use of a standard form for such request, scrutiny at customer service desk for completeness of the form, issue of an acknowledgement that the application is complete in all respects and then apply the time limit from the date of acceptance of such complete applications. In written intimation of reasons for denial, the fact that the principal has been appraised can also be mentioned. The provisions for mandatory access and non-exclusivity requirement in the Interconnect Regulation should not be removed. The requirements should be applicable to all channels irrespective of the date of their entry into the Indian cable TV market. [Col V C Khare (Retd) - Cable TV Industry Observer]

2. The process to address the applicant's request is generally quite lengthy and the time taken varies from case to case as many formalities such as complete documentation, site visit etc. are needed to be undertaken. In view thereof, the imposition of an outer time limit for the agent/intermediary to react would be unfair and impractical. Entering into a long standing business relationship with a new entity requires due diligence and establishment of complex commercial relationships. These processes are generally lengthy. In view thereof, Star India is of the strong opinion that there should not be any time limit to address the applicant's request. In the present environment, there is a need to review the overly broad "Must Provide" and "Non-Exclusivity" provisions of the Regulation for the reasons, among others, that there are presently over 240 channels available to consumers on the C&S platform. C&S is the preferred platform for broadcasters given its reach of approximately 61 million consumer homes. Non-discriminatory access of all channels to all distributors of TV channels should not be mandated by the Regulation. Star India believe that the regulatory mechanism should adopt a balanced approach to consumer interest and competition. Star India believe that date should not be the basis for application of these requirements. (Star)

3. The process, upon request for the provision of signals, varies depending on a variety of factors such as the provision of the requisite technical information, consideration of financial viability, a site inspection, and negotiation of the terms of supply and distribution. In practice, the process is often extended by delays on the part of the distributor. It is impractical to set a limited period for a commercial negotiation. The mandatory access provisions should be removed. Mandatory access, along with the price freeze, comprises some of the most market-distorting television regulatory regimes currently in place anywhere in the world. Mandatory access should be ended for all channels, irrespective of the channel's date of commencement in India. (USIBC)

4. There should be a transparent mechanism in place, which allows broadcasters or their agents to evaluate the creditworthiness and business reputation of a cable operator before they are required to licence their signal to the cable operator for further re-distribution. This mechanism could establish a minimum threshold of accountability for cable operators. If any cable operator is found to have links with undesirable persons, the broadcaster should be able to refuse signals to that operator. As an analogy, a new VAT registration today requires a trader to provide a surety to the Government up to Rs. 100,000. However, the surety can also be reduced by Rs. 50,000, should the trader have

the following: a fixed line telephone, a passport, a Permanent Account Number. A similar mechanism should be put in place whereby at least an Income tax PAN number or VAT registration is required before the broadcaster is obliged to provide signals. The Telecommunications Regulations 2004 in spirit should offer signals on a non-discriminatory basis but also on minimum financial viability threshold terms, which are transparent and reasonable. The "must provide" obligation in the Interconnect Regulations has been conveniently misinterpreted by some MSOs and their affiliate LCOs to mean that they have unfettered rights to expand their business without accountability to broadcasters. It is suggested that a request for signals to television channels by a distributor should be either under (a) for re-transmission of signals to the ultimate customer who has the ability to pay and is located in a specific geographic area as per existing terms between the broadcaster and the distributor, or (b) for re-transmission of signals to designated LCOs based on their current area of operation. Further, all MSOs should declare their list of sub-operators, link operators and LCOs and be able to provide details of their paid subscriber base. The provisions for mandatory access and non-exclusivity should be done away with. The prevailing market conditions include availability of several access modes for consumers to receive signals. Thus market forces should be allowed to dictate availability of channels and there should be no discrimination between availability of digital and analog channels. (MPA)

5. There is no requirement of Mandatory access to content and market forces should be allowed to determine these aspects. This will benefit the subscribers also. Also, as far as the pay channels are concerned and especially in the case of sports channels there must be a provision of must carry as Sports Channels also play an important role in developing sports and talent for the country. Restricting a Sports Channels growth would be restricting the growth of the sports itself. (ESPN)

6. The very purpose of this act to do away with discrimination is still to be achieved since the Broadcasters are not providing their signals to those who were already being discriminated but the new entrants are also denied the signals. The onus of providing the signals should be put on the Broadcasters by making this clause more stringent. The time frame set should be strictly adhered to and it should be seen that signal is provided within a period not exceeding thirty days. A criterion should be fixed for those requesting for the signal rather than Broadcasters coming up with their new criteria ever day. If the time frame is not followed strictly the very purpose of this act is defeated and the ground reality remains as it is. The time limit should also include the time taken for referral to its agent or intermediary. There are instances where the Broadcasters and Agent/intermediaries do not bother responding to the request for providing their signals for more than 30 days. In these cases penalty should be imposed and the signal should be provided forthwith and formalities completed then. The mandatory access and non-exclusivity requirement should not be done away with as this may result in extra benefit for one platform over another which may affect lots of Networks. (B.N.B. Cables)

7. Yes there should be a time frame of 30 days for closing the request of the service provider who is asking for the content. The process needs to be defined as - once a request is made to the agent of the broadcaster it should be taken as the final request there would be no onus on the party making the request to contact any other agency in India or overseas; the Agent must provide an acknowledgement of the request; the agent must provide access to content at non-discriminatory rates as mandated under the interconnect regulation within one month of such request; all interconnect rates must be filed with the

Regulator; the broadcaster through its agent must fulfill all conditions such as provision of decoder, or decryption equipment to the applicant party at the rates filed with the regulator; in case access is not provided by the Agent by the due date the Regulator should intervene and pass an order which is final and binding for provisioning of the content; any other remaining commercial formalities should, if necessary be completed through any agency designated by the regulator and in case of a default, the action under the downlinking norms also need to be initiated. The request for the content can be in standard format with standard terms in the agreement. If these issues can be addressed, it will save lot of litigation and suffering to the consumers. The mandatory provision of the channels can be acceptable if we say that any platform where the subscriber can be digitally addressed directly by an enabling device will have the benefit of the must provide regulation. In order to tackle the problem of capacity constraints in the cable networks, any new pay channel launched after a notified date should mandatory be delivered in digital mode. The Time limit should be only one - which is made to the notified agent of the broadcaster. No other time or allowances should be given. (ASC)

8. As per clause 3.4 of the Interconnect Regulation any agent or any other intermediary of a broadcaster / MSO must respond to the request for providing signals of a TV channel in a reasonable time period but not exceeding 30 days of the request. This must be strictly adhered to even if the agent seeks certain details from the distributor. The agent should say either yes or no within the aforesaid time limit of 30 days to enable the distributor of channels to approach either broadcaster or appropriate forum for redressal of its grievance. The overall time limit of 30 days should also include time taken by the broadcaster to refer the request for signals to its agent or intermediary. Non-exclusivity requirement in the Interconnect Regulation should be continued to ensure effective competition between cable distribution platform and digital platforms such as DTH, IPTV etc. The requirement should apply to all channels irrespective of their date of launch. There should not be any exclusivity either amongst the digital platforms and /or in digital platforms vis-à-vis cable platforms. (Siti Cable)

9. A time limit of 30 days from the date of request received by an Agent/MSO/broadcaster should be laid down. This time limit should include the time taken by the broadcaster to refer the distributor of TV channels, who has made a request for signals, to its agent or intermediary. It is emphatically stated that under no circumstances should exclusive content be allowed whether on analogue or digital format and on any one particular technology vis-a-vis another. This is required in the consumer interest and in an era of vertical monopoly (80% market share in metros is in the hands of vertical integrated networks). These requirements be applied to all such channels who wish to downlink in India if the new channels are excluded, there is a likelihood that broadcasters will switch their popular content/programme to new channels to avoid must sharing of content if new channels are exempted from 'must provide.' Further non exclusivity should be retained with no limit to the number of registered cable operators in a given area. (IMCL)

10. The existing system of "not exceeding 30 days time frame" to respond under clause 3.4 and 3.6 is currently working fine. The time limit should not include time taken by the broadcaster to refer the distributor of TV channels who has made a request for signals to its agent or intermediary. The provisions for mandatory access and the non-exclusivity requirement in the Interconnect Regulation should not be removed. Cable TV

industry will vehemently oppose to any such attempt to create niche content only for one platform like DTH, IPTV, leaving Analog Cable / Digital Cable TV Platform in the lurch as it is ex-facie discriminatory and arbitrary. These requirements should not be applied only to channels that have entered the market before a particular date. (Hathway)

11. Since process of providing signals by broadcasters through their decoder is completely automated, it can be activated in just 2 hours, a maximum period of 7 days from the date of request received by an Agent/MSO/broadcaster should be provided for acceptance or refusal. The 7 days time limit should also include time taken by the broadcaster to refer the distributor of TV channels who has made a request for signals to its agent or intermediary. Under no circumstances should exclusive content be allowed whether on analogue or digital format and on any one particular technology vis a vis another. This is required in consumer interest and in an era of vertical monopoly. These requirements may be applied to all such channels who wish to downlink in India. Further non exclusivity should be retained with no limit to the number of registered cable operators in a given area. (COFI)

Issue for Consultation

Area of operation

- **Whether the obligation of the broadcaster to provide access to content to all distributors should be valid only as long as the MSO/ LCO operations are restricted to the area as defined in the commercial agreement?**

Comments Received

1. Access is provided at the Headend through issue of IRDs. The IRD should, under the interconnect agreement, be specifically allocated to the address of the Headend location in the agreement. Only then the feed from a particular IRD can be deemed to be restricted to the area covered by a particular Headend and its radius of operation. [Col V C Khare (Retd) - Cable TV Industry Observer]

2. The provision of service by the MSO or LCO, subsequent to execution of the subscription agreement, to paying subscribers outside the demarcated area (i) is not authorized by the broadcaster; (ii) is not paid for by the MSO/LCO; and (iii) potentially infringes on the retransmission licence of another MSO/LCO. The "Must Provide" obligations in the Regulations have been misinterpreted by some MSOs and their affiliated LCOs to require unfettered rights to expand their networks. Therefore, Star India believe that the Regulations should be appropriately amended to recognize that the "Must Provide" obligations on broadcasters and their authorized distributors/agents applies with regard to demarcated areas of operation and that there is an obligation for the licensee and his affiliates/sub-licensees to restrict themselves within the area of operation. The TRAI should also incorporate a regulation that obligates the MSOs and LCOs to provide the details (including names and address) of declared subscribers. In the absence of such provision, the MSOs and their affiliated LCOs are misusing the 'Must Provide' obligation of the broadcasters. (Star)

3. TRAI's 'must provide' obligations continue to be misinterpreted by some MSOs and cable operators as affording them the right to expand their networks without regard to

the geographical boundaries stipulated in the channel supply agreements. It is imperative that the TRAI clarify that its existing 'must provide' obligations on broadcasters is not meant to empower the MSOs and cable operators to expand service with impunity beyond the demarcated area commercially agreed. (USIBC)

4. Each MSO/LCO should have a specific geographic area of distribution within which they can expand their number of subscribers. TRAI could examine the feasibility of a scheme, which allows the MSO's to put in the cable infrastructure and gives the right to collect fees and maintain the infrastructure only to the existing 1-2 cable operators who are currently operating in the area and have control of the ground. This franchise/ license could be granted against payment for some fees or upon giving a guarantee. No new entrants would be granted licenses except for new licensees deemed necessary to service rapid market expansion. In such cases they need to inform the broadcasters and existing contracts would have to be reviewed and amended suitably. (MPA)

5. The area of operation of the cable operators should be clearly defined in the commercial agreement and the obligation of the broadcaster to provide access to content to all cable operators should be valid till the time the cable operators are restricted to these areas. Otherwise, unauthorized expansion of area of operation by the cable operators may result in a situation of chaos. (ESPN)

6. The agreements can be drafted to either have an area of operation as predefined or the agreement can have a time linked increase in the area of provision as well as growth of customers within the given area. Most MSO and operators such as DTH operators operate in an environment where services are provided in large geographically dispersed areas and such provisions can be covered by agreements. (ASC)

7. If the distributor of a channel has a valid registration to operate in a particular area the same cannot be curtailed by placing artificial restrictions by the broadcasters as it would act as a impediment to the growth as well as competition. The only issue in this regard is the payment of additional subscription fee for the extended area (s) of operation, which can be settled between broadcasters and distributors of channels on a "negotiated subscriber base" for the additional area. The extension of area by a distributor of channels in which he is authorized to operate by virtue of having valid registration for that area, cannot be termed as piracy or unauthorized distribution entitling a broadcasting to switch off its channels by giving a notice of 2 days. In such an event a period of 30 days is to be given to arrive at the negotiated settlement of subscription fee for the additional/ extended area of operation failing which the distributor of channels is entitled to approach Hon'ble TDSAT for settlement of the disputes in accordance with law. (Siti table)

In IMCL's view, if IMCL wishes to serve consumers in a city, it be allowed to do so without hassles and the broadcasters then cannot impose conditions which restrict the MSO within the area of that city. Broadcasters need to share information regarding the number of MSOs/LCOs operating in an area and paying them for the number of connections for receiving their services and should put this information in public domain so that they can not discriminate when new MSOs seek service and there is transfer of

connectivity between the competing MSOs in today's environment in a transparent manner. (IMCL)

9. No. This will tantamount to the restrictive trade practice and will lead to unfair business practices. It is ultimately subject to revision in subscription fees either on the higher side if there is growth or lower side if there is loss of operational / billable area / size. (Hathway)

10. Any MSO/Cable Operator who wishes to serve consumers in a city, be allowed to do so without hassles and the broadcasters then can not impose conditions which restrict the MSO/Cable Operator within the area of that city. Broadcasters need to share information regarding the number of MSOs/LCOs operating in an area and paying them for the number of connections for receiving their services and should put this information in public domain so that they cannot discriminate when new MSOs seek service and there is transfer of connectivity between the competing MSOs in today's environment in a transparent manner. This will also help subscribers to know from the website of the broadcasters as to availability of their signals from MSO/Cable Operator of a particular area. Any area demarcation has to be done as a part of license by the regulator/licensing authority. Since there is no licensing as of now, no area restriction can be made by a broadcaster. If different broadcasters resort to different areas, there will be a chaos on the ground. (COFI)

Issue for Consultation

MSO as an agent of Broadcaster

- Whether the Regulations should specifically prohibit appointment of an MSO directly or indirectly, as an agent of a broadcaster?

Comments Received

1. Yes. [Col V C Khare (Retd) - Cable TV Industry Observer]
2. Principally there are two factors which determine the choice exercised by broadcasters; (i) the financial analysis of capital cost of providing IRDs vs. the subscription revenue expectation; and (ii) the potential impact of unfettered territorial expansion. In either case, the service providers would have to provide non-discriminatory terms and the commercial offer to the applicant-distributor would be the same. It follows that the agent/intermediary providing signal feed could be an MSO operating within the area of operations applied for. Where the existing MSO refuses to provide signal feed, the broadcasters would give signals directly on non-discriminatory terms. (Star)
3. The market should be allowed to operate in its own course. Should a broadcaster choose to appoint an MSO as its agent, it would only do so with the interest of expanding their share of the market. Given the huge costs involved in setting up a distribution network, it is likely that the agents appointed by a broadcaster would be from the cable trade. If the MSO cannot be appointed as an agent, it would mean that all cable operators would be entitled to take direct signals from the broadcaster, which is not financially viable, nor commercially manageable on the ground. With over 240 channels now available in India, no channel can be determined "irreplaceable" should any agent limit a channel's distribution. (USIBC)

4. The Regulations should clearly specify that an MSO cannot be appointed as an agent of a broadcaster. (ESPN)
5. MSO should not act directly or indirectly as an agent as it gives them unhealthy edge over their rival MSOs. (B.N.B. Cables)
6. The appointment of MSO as an agent of Broadcaster is inherently anti-competitive. (ASC)
7. The TDSAT has already adjudicated this matter in Sea TV's case and an appeal against this judgment is pending in the Supreme Court. The main issue in this regard is that there is an apparent conflict between the obligations of MSO as an agent of the broadcaster and his business as MSO, which is to provide signals to as many cable operators as possible. The broadcasters are appointing MSOs as exclusive agents at ground level on Minimum Guarantee basis, which is creating lot of distortions and disturbances in the market. Accordingly various cable operators are not able to get the signals of the broadcasters, as in order to perpetuate their monopoly these MSO agents are refusing the signals to rival cable operators on one pretext or the other. The appointment of MSO as an agent is totally prejudicial to the competition and is creating monopoly at ground. Matter may be put beyond doubt by adding one more proviso to Regulation 3.3 which should read as "Provided that a multi system operator cannot directly or indirectly be the designated agent of broadcaster or his/her authorized distribution agency." (Siti Cable)
8. As this matter is sub judice in the Supreme Court in the Sea TV Civil Appeal in which IMCL are interveners, IMCL do not wish to make any direct comment except to state that the Interconnect Regulations need to be interpreted along with the explanatory memorandum and replies to stake holder queries issued by TRAI. (IMCL)
9. MSOs have even otherwise been reduced to act as a collection arm of the broadcasters. Since the matter is sub judice before the Hon'ble Supreme Court in Sea Network matter, Hathway are of the view that outcome of the judgment be awaited and they would abide by the same. (Hathway)
10. The Interconnect Regulations need to be interpreted along with the explanatory memorandum and replies to stake holder queries issued by TRAI. The agent should not be a service provider if a genuine competitive market has to be developed. (COFI)

Issue for Consultation

Payment defaulters

- Whether the Regulations should make it obligatory that the applicant-distributors shall produce along with their request for services, a "No Pending Dues" certificate from the presently-affiliated MSO in respect of LCOs intending to get signal feed through such distributor or directly from broadcasters?

Comments Received

1. Yes. [Col V C Khare (Retd) - Cable TV Industry Observer]

2. The provision of excluding payment defaulters from the "Must Provide" obligation should be expanded to include the cases such as where an MSO seeks to expand its area of operations to provide signals to an LCO who has defaulted in payment to his currently affiliated MSO, or to the Broadcaster; where an LCO or group of LCOs any of whom have defaulted in payment seek to establish their own head-end and obtain signals directly from broadcasters; and where any of the promoters of a distributor of TV channels are promoters of any other distributor of TV channels which has defaulted in payment. Further, it is operationally impossible for broadcasters to verify whether an applicant-distributor is a payment defaulter prior to provision of service in accordance with the Regulations. Therefore, Star India recommend that the Regulations should include an obligation that the applicant-distributors include, along with their request for services, a "No Pending Dues" certificate from the presently-affiliated MSO in respect of LCOs intending to get signal feed through such distributor or directly from broadcasters. The Regulations should also provide that if any MSO provides signals to a new LCO, who was previously affiliated to a Broadcaster, without obtaining a copy of the "No Pending Dues" certificate from such Broadcaster, the Broadcaster shall have the right to disconnect such MSO. (Star)

3. This regulation makes sense. It is a relatively simple way to ensure that chronically defaulting operators will not be tolerated. (USIBC)

4. All the payment defaulters are required to be dealt with strictly, in furtherance of which, the Regulations should make it mandatory for all the applicant-distributors to produce, along with their request for services, a "No Pending Dues" certificate from the presently-affiliated MSO in respect of LCOs intending to get signal feed through such distributor or directly from broadcasters. (ESPN)

5. Yes it should be made obligatory that the applicant distributors produce No Pending Dues certificate from the presently affiliated MSO in respect of LCOs intending to get signal feed through such distributor or directly from Broadcasters. (B.N.B. Cables)

6. The issuance of the NOC is not a practical solution, it will bring in more litigations as the outgoing Service provider will delay NOC on various pretexts which can be litigated and thus may deprive the end consumer the service completely or partially. In case the input cost of the MSO are equal then the ultimate price to the LCO also will be the same and it will be the service which will be the determining factor and let the field decide for it. (ASC)

7. The provision for applicant – distributors to produce "No Pending Dues" from the presently affiliated MSO, is not a practical suggestion and would lead to all kinds of complications and litigations because the existing MSO would not want to lose any affiliated LCO and therefore is likely to put up false & frivolous demands of outstanding to prevent the LCO from shifting. In such a scenario in the absence of "No pending dues" certificate from the LCO, the other MSOs will not be able to provide feed to the LCO, thus forcing the LCO to stay with the existing MSO. Such a regulation would be detrimental to the progress of the industry and would amount to promoting de-facto monopolies. (Siti Cable)

8. The requirement of No Pending Dues certificate may create a problem because there may be a genuine dispute between the parties and the shifting applicant may not be able to procure and produce the certificate thus affecting his right to do business with others. (IMCL)

9. It is welcome step on the part of the Authority for the proposed amendment in the Interconnect Regulation. This dynamic and pragmatic view will resolve the evil in the system. (Hathway)

10. The requirement of No Pending Dues certificate may create a problem because there may be a genuine dispute between the parties and the shifting applicant may not be able to procure and produce the certificate thus affecting his right to do business with others. (COFI)

Issue for Consultation

Expansion of Existing Regulations

Subscriber Base

- Whether the subscriber base should remain fixed during the term of validity of subscription agreement?
- If not, what should be the methodology for periodic revision of subscriber base?
- Whether it should be made mandatory to provide a list of the LCOs (with Subscriber base/ lump sum payments)/households to the broadcasters/MSOs at the time of signing of the agreement?
- How should the subscriber base be determined for new entrants?

Comments Received

1. The subscriber base should remain fixed during the term of validity of subscription agreement unless provision exists in the agreement to revise the same along with reasons and justification. The methodology for periodic revision of subscriber base should be by physical door count verification in LCOs area by Broadcaster's agents along with the LCO. Ideally it should be made mandatory to provide a list of the LCOs (with subscriber base/lump sum payments)/households to broadcasters/MSOs at the time of signing of the agreement. The subscriber base for the new entrants be determined by encouraging CAS implementation, providing for acquisition of STB on softer terms, as a technological compulsion, like TV over IP and DTH, and assigning zero value to FTA content in the SMS (Subscriber Management System). [Col V C Khare (Retd) - Cable TV Industry Observer]

2. The subscriber base may typically change during the course of a subsisting contract and the subscription fee should be modified accordingly. Any increase or decrease in paid subscriber base on account of LCO churn can be given effect to only when all MSOs are required to give a break-up of their paid subscriber numbers by affiliate LCO as part of the subscription agreement. As MSOs do not provide a list of their affiliated LCOs and their paid subscriber base, broadcasters take the more conservative view of opposing any reduction in the paid subscriber base. The Regulations should mandate that the LCOs provide to the MSOs details of their declared subscribers (along with names and addresses) and the MSOs to provide such list to the broadcasters. This would facilitate the broadcasters to increase/decrease the subscription fee of the MSOs on account of LCOs churn. Given that there are instances of disputes on subscriber numbers between the Broadcaster and the MSO/cable operators, the TRAI may come up,

on an immediate basis, with a mechanism to deal with this issue. Star India suggest that the TRAI appoint an independent reputable third party agency (such as AC Nielsen) to deal with subscriber related disputes (by conducting surveys in the event of dispute). In the event of any dispute, the MSO/cable operator would be required to provide to the third party agency a true and accurate list of its affiliated cable operators, and their respective connected subscribers (along with their complete contact details). The independent reputable third party agency could then conduct a survey in the specified area within a specified time. The reports of the survey should be final and binding on both the parties. The costs for the survey should be paid by the losing party. In the case of new entrants, the area of operation may be defined in terms of demarcated geographical territory or in terms of the list of LCOs which the MSO proposes to connect over the term of the agreement. Accordingly, the broadcaster may make a non-discriminatory offer based on the area demarcation or based on current subscription revenue of the affiliated LCOs within the area of operation. Star India feel that since the number of new entrants is not as much, no regulation is required specifically for new entrants. (Star)

3. Subscriber base should not remain fixed. India's cable television subscriber base is growing at a fast rate, and there are still entire regions that are not currently serviced by cable television. To freeze the subscriber base during the course of an existing subscription agreement is neither necessary nor fair. The Ministry of Information and Broadcasting or TRAI must be empowered to press service providers to provide their subscriber base. The Ministry or TRAI should be urged to set up a special cell to begin "snap audits" of a few dozen service providers every year to review conformity of reporting rules, and to get a clearer picture on the amount of under-reporting existent in the market. Underreporting of subscriber number is a violation of copyright laws and distorts the value of the market. The regulation to provide a list of the LCOs (with Subscriber base/ lump sum payments)/households to the broadcasters/MSOs at the time of signing of the agreement makes sense. It is a relatively simple way to add an important layer of regulation in an industry, cable distribution, which is lightly regulated. Furthermore, both the distributors and the MSOs should be obligated to provide an accurate count as to the number of subscribers they are serving. It would seem to make sense to base it on estimates drawn from the population in the operator's operation of area, with provision of a complete list of the operator's cable affiliates and subscribers. There should be a survey of cable penetration of the area, with due allowance for the offering and appeal of the new entrant's product. (USIBC)

4. MSO/LCOs should be able to prospect new consumers on an ongoing basis and likewise consumers should be able to choose from an array of MSOs/LCOs. MSOs should provide broadcasters a list of their subscribers on a quarterly basis. This list should be geographically sorted with household addresses, names of subscribers and contact details. This will allow broadcasters – if they so desire – to spot check service quality. Also, this level of data mining will allow all the parties – Broadcasters, MSOs and LCOs to design special promotional offers. On a quarterly basis, new additions to the lists and deletions from the list may be flagged. It should be made mandatory to provide a list of the LCOs with their Subscriber base to the broadcasters/MSOs on a monthly basis and at the time of signing of the agreement. Approximately 50-60% of this should constitute the minimum guarantee in terms of payment obligation. For new entrants, the subscriber base may be determined based on the existing level of penetration of cable services in the area. (MPA)

5. The subscriber base should be specified in the agreement. Any increase/ decrease in the same should be dealt with in the manner such as; (a) it should be made mandatory for all MSOs/ Cable Operators to file with the broadcaster, a list of their subscriber base, on a monthly basis.; (b) a similar list for LCOs should also be filed; (c) this data should also be made available on TRAI's website so as to encourage transparency. In case of new channels / entrants, the subscriber base should be subject to negotiation between the two parties to the agreement. (ESPN)

6. The subscriber base should remain fixed during the term of validity of subscription agreement as the broadcasters specially event driven ones resort to strong arms tactics before important events and try and increase the subscriber base. The obligation for provision of list of subscribers should not be made mandatory at the time of signing of agreement. A minimum amount of subscriber base should be fixed in a way so that it does not hurt any of the parties involved. (B.N.B. Cables)

7. The subscriber base during the tenure of the agreement in case of non addressable environment should remain fixed, in case of the addressable environment it should be based on the actual no of subs. It is important that during the tenure of the price freeze the total outgo from a network is also kept fixed. The periodic revision in case of the non addressable environment can be done on the basis of any new constructions coming in which may increase the number of households in the area. At the time of signing of the agreement the LCO list with sub base is difficult, however, it can be mandated that within three months of signing the agreement the list can be provided containing the names of the LCO connected to the system. The subscriber base of the new entrant can be fixed as a minimum entry level by the service provider. (ASC)

8. It is duly recognized by TRAI in earlier Consultation Note and papers that in non-CAS areas the Interconnect agreements are on the basis of 'negotiated subscriber base'. Since the negotiated subscriber number is supposed to take care of distribution margin and also the inbuilt subsidy to the subscribers, it should remain fixed through out the term of validity of the subscription agreement. Since the settlement between the broadcaster and distributor of TV channels has been arrived at on the basis of negotiated subscriber base, there is no relevance and need to provide the list of LCOs etc as the broadcasters tend to misuse the said list to harass the distributor of TV channels by alleging that the LCOs figuring in the said list have much higher subscriber base than what is declared in the list at the time of signing the agreement and thus demand more subscription. In the alternative, when Interconnect agreement is entered into with the broadcasters for non-CAS areas, a particular declaration of the number of subscriber by the distributor of channels (LCO to MSO) should form a basis for the finally negotiated number. Therefore, if there is any increase in declared subscriber base on account of new LCOs joining the MSOs either in the same area or in new area when the MSO expands his operation, the same should be added to the subscriber base. Similarly when an LCO leaves the MSOs, the declared subscriber base should accordingly be reduced. Thus a proper reconciliation should be carried out whenever migration takes place both on account of increase in the declared subscriber base as also in respect of decrease in the declared subscriber base and the declared subscriber base should be revised both upwards & downwards as the case may be through a reconciliation exercise at periodic intervals and adjustments be carried out accordingly. For a new entrant the only methodology is negotiated settlement with the pay broadcasters for a particular period of time, which can be reviewed after the expiry of said period based on actual performance of the distributor of channels at the ground level. (Siti Cable)

9. There is no need to provide the lists of LCOs together with their list of declarations to broadcasters. The real reason why MSOs like IMCL cannot provide details of LCOs actual subscriber base is because LCOs also negotiate with MSOs on their notional subscriber base and pay a pre determined sum of monthly subscription fee. In fact no MSO is aware of the true and genuine subscriber base of a LCO. Alternatively if such a subscriber base was considered vital and necessary to provide in the Regulation then in absence of addressability the only viable method is to use Service Tax/ Entertainment Tax declaration or self declaration by LCO (as relied upon by IMCL unless proved contrary otherwise on a case to case basis). The subscriber base for new entrants should be a minimum of 300 connections for MSO and a minimum of 50 connections for LCO. (IMCL)

10. Dynamics of any business never remain static. However, in order to maintain stability and reasonability during the terms of the agreement, it is the agreed and negotiated subscriber base that should be allowed to remain static and fixed. If it is allowed to remain fluctuating on monthly basis or in short span of time / tenure, this would lead to more conflicts and disputes. Further, the negotiated subscriber base is a function of demand of a particular channel or bouquet of channels or a channel within the bouquet / non-moving channels with one or two channels in demand. CAS is the only solution. If the Authority in any case takes any view based on the present consultation paper under consideration then the *a-la-carte* as well as issues arising out of the Distribution Margin to the Dealers like the MSOs / LCOs needs to be addressed simultaneously without any further delay. The objective of the Authority to minimize the disputes through the present consultation paper would get vitiated if there are periodic revisions. If there is a negotiated subscriber base (as recognized in the 01st October 2004 Recommendation of TRAI) then there is no sanctity left in providing with the list of subscribers of LCOs and households. Further, MSOs receive only the lump-sum negotiated fees from its value chain, like the pay broadcasters receive from the MSOs. Further the situation has reached to such an extent that MSOs are paying more subscription fees for the negotiated subscribers to popular pay broadcasters, than the amount they are collecting from the paying subscribers / LCOs declaration. The subscriber base for new entrants be determined on the basis of negotiated and / or agreed subscribers. (Hathway)

11. Subscriber base should remain fixed during the term of validity of subscription agreement limited to one year. Subscriber base should be revised every year at the time of renewal of agreement or after completion of one year of the agreement. There is no need to provide the lists of LCOs together with their list of declarations to broadcasters. The real reason why MSOs cannot provide details of LCOs actual subscriber base is because LCOs also negotiate with MSOs on their notional subscriber base and pay a pre determined sum of monthly subscription fee. In fact no MSO is aware of the true and genuine subscriber base of an LCO. Alternatively if such a subscriber base was considered vital and necessary to provide in the Regulation then in absence of addressability the only viable method is to use a self declaration by LCO. The subscriber base for new entrants be determined on the basis of a minimum of 300 connections for MSO's business and a minimum of 50 connections for LCO. It has been a practice of broadcaster to give boxes under rural scheme for minimum number of subscriber on 300 and in urban markets on 500, the same can be allowed. (COFI)

Issue for Consultation

Multi System Operator

- Whether any minimum threshold of the number of subscribers and other parameters should be specified for a Cable Operator to be defined as a "Multi System Operator" and for being entitled to receive signals directly from broadcasters?

Comments Received

1. No. [Col V C Khare (Retd) - Cable TV Industry Observer]
2. The number of subscribers under an MSO varies depending on various factors (including size, geographical location, etc.). Therefore, it is very difficult to define a MSO based on number of subscribers. Therefore, the broadcasters should continue to define MSOs on a non-discriminatory basis. (Star)
3. There should be a uniform licensing procedure for all distributors and MSOs (subscriber thresholds, technical standards, financial requirements), but beyond that it should be a purely commercial decision as to whether to provide their signals directly. (USIBC)
4. The definition of "MSO" as contained in the Act should define a minimum threshold of the number of subscribers and other parameters for a Cable operator to be defined as a "Multi System operator" and for being entitled to receive signals directly from broadcasters. (ESPN)
5. No minimum number of subscribers should be fixed as this will block the advent of new entrants in this sector and also restrict the aspirations of existing cable operators from becoming a MSO thus directly making the existing even more powerful and assertive thus creating a monopolistic market environment which can hurt the consumers. (B.N.B. Cables)
6. Due to the diverse demographics of India it is difficult to specify the threshold number for the cable operator to be defined as MSO, the need of this definition is purely theoretical as MSO in present day also do the agreements to a great extent based on the head ends reach and then consolidate the same in one agreement. This may be left to the Broadcaster.(ASC)

The correct technical definition of an MSO is any company /entity which operates multiple headends in different areas or across state or country. In addition there are large independent cable operators also who operate single headend (Control room), provide direct services to the subscribers as well as give their feeds to other LCOs who in turn provide signals to the consumers. In order to be eligible or entitled to receive signals

directly from the broadcasters the MSO /independent LCO should have at least 25 cable operators connected to its network with a minimum aggregate subscriber base of 3000 connections. (Siti Cable)

8. Broadcasters have been charging a minimum of 500 connections in urban areas and 300 for rural areas for MSOs; since they have adopted this business model the same be allowed to continue. (IMCL)

9. It is welcome step on the part of the Authority for the proposed amendment in the Interconnect Regulation as even one person / LCO claims to be the MSO and attempts to destabilize the existing system. The role of the MSO is critical and serious business as it otherwise affect to the quality of service. It is therefore proposed that there should be a minimum 50 LCOs and at least 5,000 subscribers base as a threshold limit to be qualified as MSO. (Hathway)

10. Broadcasters have been charging a minimum of 500 connections in urban areas and 300 for rural area for MSOs, since they have adopted this business model the same be allowed to continue. (COFI)

Issue for Consultation

Renewal of Agreements

- Whether any time limit should be laid down for renewal of agreements prior to expiry of existing contract, so that in case the agreement can not be renewed, the subscribers get sufficient advance notice regarding discontinuation of those channels after expiry of existing contract?
- What arrangements should be made for extension of the contract during negotiations after the validity of a contract has expired?

Comments Received

1. Yes. This should be approximately four weeks more than the period of notice for discontinuation. The situation, of extending the contract during negotiations after the validity of a contract has expired, can arise only when the service has not been interrupted even after expiry of the validity period of the agreement. A logical approach should be to continue the service and levy new negotiated rates retrospectively from date of expiry of previous agreement. Wherever the service has been interrupted, new rates should take effect from the date of restoration of a service. [Col V C Khare (Retd) - Cable TV Industry Observer]

2. The MSOs/cable operators who intend to renew their agreement should send a written request at least two months prior to the expiry of their existing agreement. Along with the written request the MSOs/cable operators must, inter alia, send the various information/documents, including (i) post office license, (ii) photograph of authorized signatory, (iii) address proof, (iv) photo identity, (v) charter documents, (vi) letter of

authority, (vii) no-dues certificate, and (viii) such other documents as may be desired by the broadcasters. The regulation should mandate these requirements, failing which the broadcaster must have the right to disconnect the MSO/Cable operators after the expiry of the agreement. Extension of contract without execution of a separate agreement should be strictly discouraged. If such extensions are permitted, that would in effect validate provision of signals by the broadcasters to unauthorized MSOs/cable operators. (Star)

3. No, TRAI should not set a time frame for renewing existing agreements. This is a business-to-business process that need not be regulated. In addition, setting a time frame for renewing agreements would necessarily entail introducing enforcement measures; such measures could be abused by one party or the other through stalling the renewal process. An arrangement for extension of contract during negotiations after contract expires can be determined either in the original contract or on an ad-hoc basis when a contract expires. A regulation, forcing particular conditions, would not be useful as such a regulation would have to be written in such a manner as to make provisions for a mandatory extension of the terms. Such a regulation would inevitably favor one side or the other after the expiration of a contract. (USIBC)

4. The Act / Rules should lay down a time limit for renewal of agreements prior to expiry of existing contract(s), so that in case the agreement cannot be renewed, the subscribers should get sufficient advance notice regarding discontinuation of those channels after expiry of the existing contract. After the expiry of the contract three months time for negotiations should be given and in this time the operator (MSO / LCO) should be made to pay on the then prevailing rate of the channel for the period during which they receive the services from the broadcaster at the last agreed subscriber base, until the contract is either renewed or services discontinued. (ESPN)

5. Yes a time frame for renewal of agreements prior to expiry of old contract should be laid down so that the subscribers do not suffer and get enough advance intimation in case of continuation of any channels. (B.N.B. Cables)

6. The renewal of the agreement should be done at least a month prior to the expiry of the previous agreement. In case the agreement is not closed within the validity of the previous agreement and there has been no new habitation of the household in the area defined then the previous agreement should be kept valid and in the next thirty days if the same can not be concluded then the regulator should pass the order based on the facts presented within the next thirty days, in this interim period the broadcaster or its distributor should not take any step to discontinue the services. (ASC)

7. Ideally, the agreement should be for a period of 3 years and the commercial terms can be renegotiated after expiry of 12 months period. The negotiations for settlement of commercial terms should start at least 30 days before the expiry of the 12 months period and an attempt should be made to settle the same before the expiry of said 12 months. If the broadcasters stipulate certain unreasonable terms, the distributor of channels can approach TDSAT immediately after the expiry of 12 months period and seek redressal. If TRAI prescribes a standard agreement then most of such disputes can be eliminated

and renewals can take place in a speedier manner. If the negotiations in a good faith continue even after the expiry of 12 months period / agreement as mentioned above, the same can be continued till the fresh commercial terms are settled for the new period and no disconnection be resorted to. Once the new commercial terms are settled they would automatically apply with effect from the date of start of new period. (Siti Cable)

8. Time limit of an agreement and their renewals should not be less than 1 year and extendable mutually thereafter. There is no legal provision that agreements end after one year and cannot even be renewed as this is a violation of must provide interconnect regulation. Ideally once the licensee has signed an interconnect agreement it should be for the period of license and any disconnection should be exception and not the rule and be allowed only if all other methods to resolve the dispute fail. If these contracts are not long term contracts then this business will be uncertain and investment in this business will never be safe and not only service providers but the consumers will have to suffer if they have to change their service provider every year. It is evident from many Court cases that whenever there is a renewal of an agreement, broadcasters send notices for enhancing the revenue on the threat of denial of services or deny to renew the contract. It is also a restrictive trade practice on account of broadcasters since they insist on signing of agreement on a fixed number of subscriber base for a year and for any change in the number of subscribers. They insist on signing new agreements. If there is an agreement then it should be for licensing or authorized distribution and the payment should be on the basis of declared subscriber base from time to time and not on annual contracts. For extension of contract, ideally, negotiations should start before 60 days so that 30 days are given for negotiations and 30 days to approach TDSAT if the parties fail to reach the agreement. (IMCL)

9. Till the time old agreement or oral arrangements are in place the continuity should be maintained. If there is a complete break down of negotiation then and in that case alone a notice of one month needs to be given by the broadcasters / MSOs to the MSOs / LCOs as the case may be and if the affected party rights are prejudiced then the affected party may approach the appropriate forum for adjudication. Till such time the parties to the Interconnect regime should be encouraged to enter into an agreement through dialogue. The Authority should give a clarification that the Oral arrangement / Oral Agreement should form part of the understanding in determining the inter-se relationship between the value chains in the system. The Agreement shall have a continuity at least for a period of 3 years and it is only the commercials like the function of the rate and number of subscribers or the negotiated lump-sum periodical subscription fees or number of channels as the case may be needs to be reworked at suitable interval of say 12 / 18 months. (Hathway)

10. Time limit of an agreement and their renewals should not be less than 1 year extendable mutually thereafter. There is no legal provision that agreements end after one year and cannot even be renewed as this is a violation of must provide interconnect regulation. Ideally once the licensee has signed an inter connect agreement it should be for the period of license and any disconnection should be exception and not rule and be allowed only if all other methods to resolve the dispute fail. If these contracts are not long

term contracts then this business will be uncertain and investment in this business will never be safe and not only service providers but the consumers will have to suffer if they have to change their service provider every year. It is evident from many Court cases that whenever there is a renewal of an agreement, broadcasters send notices for enhancing the revenue on the threat of denial of services or deny to renew the contract. It is also a restrictive trade practice on account of broadcasters since they insist on signing of agreement on a fixed number of subscriber base for a year and for any change in numbers of subscribers. They insist on signing new agreements. It is felt that if there is an agreement then it should be for licensing or authorized distribution and the payment should be on the basis of declared subscriber base. For extension of contract, ideally negotiations should start before 60 days so that 30 days are given for negotiations and 30 days to approach TDSAT if the party's fail to reach the agreement. (COFI)

Issue for Consultation

Conversion of FTA channels into Pay channels

- Whether any advance notice should be stipulated for FTA channels turning into Pay channels, so that in case the service providers are unable to reach an agreement, the subscribers get sufficient advance notice regarding discontinuation of those channels from the date of their conversion into Pay channels?

Comments Received

1. Yes, at least 3 months. [Col V C Khare (Retd) - Cable TV Industry Observer]
2. The FTA channels are converted into Pay channel to enable the broadcasters to collect subscription revenue from the MSOs/Cable Operators. Therefore, it would become imperative for the broadcasters to enter into discussions with the MSOs/Cable Operators prior to such conversion. If the broadcasters and the MSOs/Cable Operators are unable to reach an agreement, it should give a one week's notice to the broadcaster and the consumers in terms of Clause 4.1A of the Regulations. (Star)
3. *It is safe to assume that the broadcasters and MSOs / cable operators will enter commercial negotiations well in advance of the conversion date from free to pay. However, should the parties be unable to reach agreement for the conversion, they should be left to negotiate the fate of the free channel at the expiration of their existing agreement. If TRAI is determined to set a notice period, then 7 days is reasonable. (MPA)*
4. The Act should stipulate a time period of 2 months for giving advance notice for FTA channels turning into Pay channels, so that in case the service providers are unable to reach an agreement, the subscribers get sufficient notice regarding discontinuation of those channels from the date of their conversion into pay channels. (ESPN)

5. The FTA channels getting converted to pay should be transmitted through CAS on STBs in order to avoid any increase in Tariff of the Basic Services. Since this cannot be done in retrospect, it should be done to avoid/stop the growing number of pay channels in the basic tier in the future especially due to the non availability of the pay tier. This will also reduce the growing burden on the lower income group customers who are at present subsidizing the upper income groups since the cost of every new pay channel is being distributed equally to all the subscribers including to the ones that do not even watch them. For this purpose and for ensuring uninterrupted services to the customers an advance notice of minimum six months should be fixed. The said period is the minimum one during which customers will be able to exercise their option and the service provider will be able to assess the no. of boxes/investment required to roll out the pay tier service to roll out the STBs. This will truly help TRAI to keep the existing so called (distorted) basic tier cost in control while the pay tier pricing will be determined by the market forces helping the operators to gradually enter the CAS regime without being rushed thus achieving the voluntary CAS objective. (Ortel)

6. Yes at least 2 months notice should be stipulated for FTA channels turning Pay channels so that sufficient time is there to get in an agreement and in case of failure to do so subscribers get sufficient notice regarding discontinuation of those channels. (B.N.B. Cables)

7. Normally channels going from FTA to pay mode do so well in advance however they should communicate to the public at large at least six months in advance at monthly intervals that they are going pay. This will help the consumer also to understand that if the service is to be availed then he may have to start paying more. Channels should file their rates with the regulators with the MRP and the distribution margins in the same. (ASC)

8. At least 3 months advance notice should be given by an existing FTA channel which wants to convert into a pay channel so that the distributors of channels can negotiate the agreement with such channel and the consumers also become aware that they need to pay for a particular channel resulting in monthly increase in their cable bills. Simultaneously a tariff declaration also needs to be filed with TRAI which should be displayed by TRAI on its web site. (Siti Cable)

9. Six months advance notice. (IMCL)

10. Yes once in every quarter only and i.e. 01st April, 01st July, 01st September and 01st January every year with an advance notice of three months in order for the system to know well in advance and the information should be passed on to the value chain in the system. (Hathway)

11. Six months advance notice.(COFI)

Issue for Consultation

Reference Interconnect Offer

- Whether an RIO should be issued by TRAI for approving the terms and conditions of model subscription agreements of dominant players and to regulate their activities in the broadcasting and cable TV services? If so, what should be the elements of such a model subscription agreement?

Comments Received

1. Yes. Some suggested elements could be such as detailed lists of channels/programs pertaining to agreement, subscriber base as on date of agreement, negotiated rates for each channel to mention MRP to the end viewer and wholesale rate to be charged from the distributor, narration of circumstances causing interruptions, if any, resolution of disputes and obligations in case of interruptions, safeguards against unauthorized distribution/piracy and actions to be taken on their detection, provision for arbitration and demise of agreement, accountability of Broadcaster, and Indemnity to Distributor, in any case of violation of content and advertising codes, refunds to subscribers in case of interruptions in service by the broadcasters, bank guarantees by Broadcasters to guard against unjustified interruptions and provisions for cancellation of down linking registration in case regulations are flouted by broadcasters. It is very difficult to visualize a scenario where broadcaster/distributor relations will be undisputed. Therefore, consideration is merited on 'Who should store these agreements'? Present staffing of TRAI does not meet the work load as such. Hence there may be a case for opening up a Cable TV Regulation wing with TRAI, or establishing CRAI (Cable TV Regulatory Authority of India) under the Ministry of I&B with adequate number of regional offices. [Col V C Khare (Retd) - Cable TV Industry Observer]
2. Broadcasters should be free to enter into commercial arrangement with MSO and cable operators which protect their interests. Such interests as the TRAI has already notified may be recorded orally, or reduced to writing in the form of subscription agreement. The RIO for telecom operators was issued by the TRAI given the incumbent monopoly of the state owned service provider. We would like to state that in the case of broadcasting this is not the case, and therefore, there is no need for an RIO to be issued. If however, the TRAI is of the view that it is imperative it could look at providing broad overview of what must be discussed between the parties before concluding a subscription agreement. (Star)
3. TRAI should not have an approval role for subscription agreements. This is tantamount to the government introducing a full regulatory regime for the sector, and would open the process to a level of regulatory involvement in the C&S sector seen in few if any countries. For the market to develop naturally, and for investors to understand the true value of any given market, there should not be any government intervention into commercial agreements. (USIBC)
4. The agreements are commercial agreements and the terms of the Agreement should be left to the freewill of the parties. No entity should have the right or power to approve agreements. (ESPN)
5. This is the most important aspect of this Act and onus to end monopoly should be put on the broadcasters and the MSOs to appoint more than one operator in an area so that the consumers are not at the mercy of a single operator. (B.N.B. Cables)
6. There should be a Reference Interconnect Agreement as applicable and made operative in the area of Telecom. The defined principles should be such as: Declaration of Interconnect rates by the Broadcasters / MSOs and their publication on the TRAI website; Timely and timely application of such rates; Principles for provision of content within one month beyond any recourse on signing of agreement; Making Anti piracy a part of fingerprinting mandatory in the decoders which are provided; Making forced

addressable Messaging mandatory to the particular operator and doing away with running of scrolls etc; Making web access for payments, accounting and authorizations mandatory for all the broadcasters and MSOs; Filing of monthly and yearly return by all Broadcasters and MSOs in the same pattern as prescribed by the FCC and Placement of all such data on the Web for access by all stake holders. (ASC)

6. The Hon'ble TDSAT in Petition No. 41C/2004 titled Star India Vs. IndusInd Media has mandated the execution of written agreements between the broadcasters and MSOs/cable operators as a mandatory requirement under the Interconnect Regulations. It is suggested that the TRAI should initiate a process for drafting and notifying the Standard Agreement for non-CAS areas which can be adopted by all the stakeholders as a model agreement and who can then either design/ align their agreements in accordance with the said model agreement stipulated by TRAI. The agreement should cover all the aspects of interconnection such as areas, subscriber base, mode of distribution, unauthorised distribution, content responsibility etc. Detailed inputs in this regard can be provided once TRAI initiates the process of formulating Standard Agreement. Siti Cable are of the view that Standard agreement should be formulated not only for Cable distribution but also for other distribution platforms. (Siti Cable)

7. RIO should be issued to regulate dominant players and the RIO should contain the elements such as the Authorization status/power; Area as asked for; Rate; Payment period; No of years; Transparency and Encourage competition and better services to the consumers. Till an RIO is finalized and also for the purpose of drafting an RIO, the issues need to be kept in mind are : MSO's cannot be made responsible for acts of cable operators / franchisee; there should not be a Minimum Guarantee provision; in case of negotiated subscriber base there should not be any need for provision of subscriber details / lists etc. and there should also not be any need for increase in subscriber base during the fixed term of the Agreement; in cases of Agreements on actual Subscriber base, a say 3 monthly revision (up or down) may be prescribed with a ceiling of say 5% both ways; industrial township should not be excluded from the Agreement; there should not be any restriction on expansion within the Service Area; Definition of Service Area should include both existing and new households within the demarcated service area; the Agreement should be technologically neutral; situations for disconnection may be prescribed; uniform 30 days Notice Period may be prescribed in all cases except in case of piracy where notice period should be of seven days; it should be clarified that expansion within Service Area is not piracy; there should not be any requirement of provision of Maps; broadcasters should not be allowed to see MSO's Account Books/ Records; MSO's contractual relationship with other parties should not be the concern of the Broadcaster; Licensing etc. for content should be Broadcasters responsibility; it should clearly be provided in the "Must Provide Clause" that the channels / connectivity will be provided to the seeker thereof within a period of 30 days which period should include the period for all negotiations, communications including with the agents of the broadcaster or the MSO as the case may be and A La carte bouquet should be made available in all categories. (IMCL)

8. Yes. Only cover with the basic principles of the Indian Contract Act with rights and obligations for entering into the agreement, keeping the utmost interest of the consumers / end subscribers in mind. (Hathway)

9. **RIO should be issued to regulate dominant players and the RIO should contain the elements such as the Authorization status/power; Area as asked for; Rate; Payment period; No of years; Transparency and Encourage competition and better services to the consumers. Till an RIO is finalized and also for the purpose of drafting an RIO, the issues need to be kept in mind are :** MSO's cannot be made responsible for acts of cable operators / franchisee; there should not be a Minimum Guarantee provision; in case of negotiated subscriber base there should not be any need for provision of subscriber details / lists etc. and there should also not be any need for increase in subscriber base during the fixed term of the Agreement; in cases of Agreements on actual Subscriber base, a say 3 monthly revision (up or down) may be prescribed with a ceiling of say 5% both ways; industrial township should not be excluded from the Agreement; there should not be any restriction on expansion within the Service Area; Definition of Service Area should include both existing and new households within the demarcated service area; the Agreement should be technologically neutral; situations for disconnection may be prescribed; uniform 30 days Notice Period may be prescribed in all cases except in case of piracy where notice period should be of seven days; it should be clarified that expansion within Service Area is not piracy; there should not be any requirement of provision of Maps; broadcasters should not be allowed to see MSO's Account Books / Records; MSO's contractual relationship with other parties should not be the concern of the Broadcaster; Licensing etc. for content should be Broadcasters responsibility; it should clearly be provided in the "Must Provide Clause" that the channels / connectivity will be provided to the seeker thereof within a period of 30 days which period should include the period for all negotiations, communications including with the agents of the broadcaster or the MSO as the case may be and A La carte bouquet should be made available in all categories. (COFI)

Issue for Consultation

Monopoly in the last mile

- What steps need to be taken to ensure that the monopoly at the last mile is removed so that consumers can get choice?
- Should a regulatory framework be laid down wherein the areas of operation and the number of operators are clearly defined?

Comments Received

1. It is incorrect to say that LCOs have monopoly. There is no prohibition against any one wanting to register for running a cable network. In near future, alternatives such as DTH and TV over IP will be available to viewers on Cable TV networks to choose between Cable TV, IP TV and DTH. Unless areas are auctioned like telecom circles, with investors also of that financial capability, the regulatory framework for laying down the areas of operation and the number of operators may not be feasible. In the system of registration with the post offices, area of operation of the applicant could be described with a representative sketch forming a part of the registration certificate. The registration authority could issue a consolidated map/sketch showing area of operation of each registrant and more than registrant in the same area, if any. [Col V C Khare (Retd) - Cable TV Industry Observer]

2. While this issue may be partially addressed with the advent of other distribution platforms, the monopoly in the last mile can only be addressed with the laying down of a clear cut licensing regime. The TRAI should immediately consider implementing a

regulatory framework which will involve licensing of cable operators in territories across India, in a manner similar to that of telecom. The TRAI can lay down the frame-work for appointing licensees for cable for either all of India, or for particular parts of India. These areas could be demarcated state-wise, city wise, etc. The TRAI could then, as is the case with Teleco, permit one or more cable operators for each area of operation. The license fees to be paid by the cable operators would ensure that only serious players willing to invest for the long term would operate in this market. (Star)

3. The "last mile" monopoly is already being removed through the growth of DTH satellite TV service. TRAI should quickly move to develop a licensing framework for cable operators in India, forcing operators to report their subscriber base and area of operation. The status quo, an absence of a licensing framework, is a root cause of many of the issues raised by TRAI in this consultation. In addition, much needed investment and consolidation in the last mile is slowed as investors shy away from the fragmented, opaque market. (USIBC)

4. DTH satellite television service is in fact already providing effective competition to "last mile" cable operators, serving as much as 15% of the overall pay TV subscribes in some areas and adding subscribers at impressive growth rates. TRAI should consider the level of competition more closely via a consultation on this specific issue. (MPA)

5. There should be a licensing regime for this purpose like in the telecom sector. It must be ensured that there are two to three licenses for each area. This is the best possible way to ensure competition at the LCO level. For the purpose of convenience, a regulatory framework may be laid down. (ESPN)

6. No regulation is recommended to regulate the carriage or its terms. (ASC)

7. With the launch of DTH, Broadband and HITS, the so-called existing de-facto monopoly of the last mile operator would no longer exist. In such a scenario any regulation in this regard is unnecessary. It is pertinent to mention that multiple operators in an area of operations encourage competition and ultimately consumers would be benefited. Limiting or restricting the number of operators in an area would be detrimental to such competition, would be counter productive and should not be resorted to at all. (Siti Cable)

8. It is too late for the regulator to define the area of operation and the number of operators since this would be very complicated on all India basis as there are no marked areas of operation or the number of operators. The situation is different from area to area and city to city. For instance in South Delhi there are 5-7 MSOs and independent operators, competing with each other with no monopoly in any area. There are also places like Faridabad where a vertical integrated company has a virtual monopoly in every area including the last mile and so far no MSO has been able to make an entry. Till the time the content is made available fairly and freely to new entrants last mile monopoly will remain. In fact it is IMCL's contention that there is no monopoly as such as there are thousands of operators. On the other hand there can be a potential monopoly of three to four DTH platform providers who would like to provide exclusive content to the detriment of thousands of cable operators if there was no Interconnect Regulation. (IMCL)

9. Choice comes only by way of the alternative platform like DTH, IPTV etc. and the so called monopoly in the last mile is a myth as there is enough competition in place. Defining areas of operation and the number of operators may be termed as anti competition and will lead to restrictive trade practice. Further it will be contrary to the Central legislation i.e. Cable TV Act, which provides license to operate in a particular Post Office jurisdiction / area. As long as he has the requisite Post Office license and Entertainment Tax Registration / Service Tax Registration and affiliation to any of the local MSOs is in place and he should give his true - full declaration and having valid Permanent Account Number under Income Tax Act (New Saral), the regulation can not have any conflicting view with the Central Government legislation and he should be entitled to provide signals to his total declared subscriber base.(Hathway)

10. There is no need for the regulator to define area of operation and number of operators since this should have been a part of licensing. In reality there is no monopoly in the last mile as any number of cable operators can register with post office to start a cable TV network. Monopoly is created only at the level of MSO/Broadcaster where there are compromises and alliances working. Till the time the content is made available fairly and freely to new entrants last mile monopoly will remain. (COFI)

Issue for Consultation

Carriage fee regulation

- Whether carriage fees on cable networks should be regulated? If so, on what basis should this be done and how should carriage charges be calculated?
- What should be the mechanism for ensuring that the ceiling for carriage charge is not exceeded?

Comments Received

1. Carriage fee on Cable Network should not be regulated. Carriage fee should be restricted to the maximum of revenue charged from the distributor for PAY TV. Perhaps carriage fee for FTA could be capped at 25% of the maximum chargeable for PAY TV. This should best be left to Network owners because this is also related to quality of headend equipment and, network hardware and degree of conformity to IS 13420. [Col V C Khare (Retd) - Cable TV Industry Observer]

2. The relationship between channel supplier and MSO should be left to market forces with no justification for price regulation of either channel supply or carriage. Star India's view, however, is that regulatory parity requires that while the price freeze on channel supply and subscription fees exists, a ceiling and freeze should be placed on carriage/placement fees. Such ceiling may be specified in terms of Rupees per subscriber reached, as declared by the MSOs. This is required to remove the incongruity that while revenues of broadcasters remain frozen, the broadcasters' costs (in terms of carriage fees) can increase in any proportion and at any frequency. The MSOs should be required to file copies of their carriage agreements with the TRAI so as to enable verification of payment within ceiling limits. The TRAI may consider withdrawal of such ceiling on carriage fees at the same time as withdrawal of price freeze over channel supply and subscription rates. The carriage fees may be paid by the broadcaster to the large MSOs on per declared subscriber basis. This mechanism would ensure that the ceiling for carriage charge is not exceeded. (Star)

3. The relationship between channel supplier and MSO should be left to market forces. Hence, there is no justification for price regulation on other side of the exchange i.e. both channel supply or carriage rates are best left to commercial negotiations between the parties. (USIBC)
4. The relationship between channel supplier and MSO/cable operator is safely left to market forces given the degree of competition in the supply of programming. There is, therefore, no rationale for TRAI to impose price regulation on either channel or carriage rates. (MPA)
5. Application of carriage fees on cable networks must be regulated in the manner such as: (a) the stipulation of the amount of carriage fee should be rationalized, so that new entrants may not be discouraged, (b) the amount of carriage fee must be fixed at a reasonable amount for the initial months of launch of a channel, preferably a maximum cap be stipulated and (c) the new entrants should not be charged after a period of 2-3 years subsequent to their launch. (ESPN)
6. Regulation of Carriage fees is an undesirable phenomenon which has come into existence by the cable operators owing to the limited capacity of the cable plant. This is expected to give way to addressable systems. At present ASC do not recommend any regulations to regulate the carriage or its terms. (ASC)
7. It would be totally unreasonable if an attempt is made to regulate the carriage /placement fee so as to ensure the advertisement revenue of the channel. There is no regulation / restriction on the advertisement appearing on a TV channel or the rates thereof. These are governed by the market forces of demand and supply and also on the popularity and reach of the channel. The popularity and reach on the other hand depend upon the visibility of the channel. In order to ensure the said visibility, the placement fee is being paid by the broadcasters to the cable networks. There cannot be any regulation on such carriage /placement fee and in fact creation of more capacity on the cable networks by encouraging digitalization is the most viable and practical way instead of any attempt to regulate the same through some Regulation. Thus the carriage fee should be left to the mutually negotiated settlement between broadcasters and distributors of channels and no interference is called for from the Authority. (Siti Cable)
8. Carriage fee on cable networks cannot be regulated since it is a historical fact that carriage has come into this business for TRPs. Content carriers / broadcasters have agreed to pay placement fee so that they get good TRPs which in turn will get them better advertisement pie. They are paying placement fee from their share of advertisement pie to the cable operators and if there is no curb on advertisements on channels the same should apply to the sharing of that. If there is a control on advertisements to be carried on pay channels or carrying an advertisement on free to air channels, they will not pay carriage to the MSOs or cable operators since they will have no reason to pay placement fees. If broadcasters get more advertisements on their networks by virtue of being available on good frequencies on the cable networks, cable operators have every right to seek a part from that revenue. In today's situation cable operators are allowing broadcasters to use their network without getting anything in return (i.e. the margin on MRP, MSO bill, collect and pay on MRP). (IMCL)

9. No. Any regulation on carriage fees would lead to the multiplicity of disputes. Carriage Fees would be subject matter of negotiation and the same should be left with the market forces otherwise it leads to the lack of transparency/ encouraging bad/ malpractices. (Hathway)

10. Carriage fee on cable networks cannot be regulated since it is a historical fact that carriage has come into this business for TRPs. Content carriers / broadcasters have agreed to pay placement fee so that they get good TRPs which in turn will get them better the advertisement pie. They are paying placement fee from their share of advertisement pie to cable operators and if there is no curb on advertisements on channels the same should apply to the sharing of that. If there is a control on advertisements to be carried on pay channels or carrying an advertisement on free to air channels, they will not pay carriage to the MSOs or cable operators since they will have no reason to pay placement fees. If broadcasters get more advertisements on their networks by virtue of being available on good frequencies on the cable networks, cable operators have every right to seek a part from that revenue. In today's situation cable operators are allowing broadcasters to use their network without getting anything in return (i.e. the margin on MRP, LCOs bill, collect and pay on MRP). (COFI)